

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

13 मार्च, 1991

खण्ड-1, अंक-9

अधिकृत विवरण

## विशय सूची

बुधवार, 13 मार्च, 1991

पृष्ठ संख्या

ताराकित प्रान एवम उत्तर	(9)1
नियम 45 के अधीन सदस्यों की मेज पर रखे गए ताराकित प्रानों के लिखित उत्तर विभिन्न विशयों का उठाया जाना	(9)29
विभिन्न विशयों का उठाया जाना	(9)46
वर्ष 1991-92 के बजट पर अनुदानों की मागों पर चर्चा तथा मतदान	(9)48

## हरियाणा विधान सभा

बुधवार , 13 मार्च, 1991

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्द सिंह चटठा) ने अध्यक्षता की।

ताराकित प्रान एवम उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

श्री सूरज भान: स्पीकर साहब, मुझे आपसे एक निवेदन करना है। पार्लियामेंट में तो यह रिवाज है कि सवालो के रिटन जवाब एक घंटा पहले सदन में सप्लाई कर दिये जाते हैं और यहा पर आधा घंटा पहले देने का रिवाज है। लेकिन आज यहा पर बडी मुक्ति कल से 5 मिनट पहले ही दिये गये हैं और वह भी मेरे कहने पर दिये गये हैं। कृपया इन्हे समय से दिलवा दिया करे।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। आप बैठिए।

### **Upgradation of School in the State**

**\*1227 Shri Hira Nand Arys:** Will the Minister of State for Education be pleased to State-

(a) the constituency wise number of schools upgraded from Primary to Middle to High Schools and: High Schools to 10+2 System during the year 1990:

(b) the criteria fixed by the Government for the upgradation of such schools as referred to in part (a) above;

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade such schools in Loharu constituency which have not been upgraded in accordance with the criteria fixed by the Government; and

(d) if so, the names of such Schools together with the time by which these Schools are likely to be upgraded?

**कृषि मंत्री (श्री कि न सिंह सांगवान):** स्पीकर सर, इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूँ मैं इसमें थोड़ी सी क्लैरिकल मिस्टेक्स हैं, वह आपके माध्यम से हाउस को बताना चाहता हूँ। इस सवाल के पार्ट "डी" का इंगलि 1 में तो जवाब ठीक है लेकिन हिन्दी वर्णन में कुछ कोरैक्शन की जरूरत है। हिन्दी में यह लिखा हुआ है "प्रश्न नहीं उठता।" इंगलि 1 में यह लिखा हुआ है "In view of the (c) above, no definite time schedule can be given." मेरे कहने का मतलब यह है कि इंगलि 1 वाला जवाब चूँकि ठीक है इस लिए हिन्दी वर्णन को भी इसी तरह से लिखा समझा जाए। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, जो लिस्ट हमने सबमिट ही है, उसमें थोड़ी सी टाईपिंग मिस्टेक्स हैं, उनके बारे में जब सदस्य सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दे दूँगा। अब मैं जवाब पढ़ देता हूँ।

**श्री अध्यक्ष:** ठीक है ।

**श्री कि न सिंह सांगवान:**

(क) विधान सभा क्षेत्रवार वर्ष 1990-91 में स्तरोन्नत किये गये स्कूलों की संख्या सूची विधान सभा पटल पर रखी जाती है।

(ख) विभिन्न वर्गों के स्कूलों के स्तरोन्नत करने के प्रस्ताव क्षेत्रीय कार्यालयों से मगवाये जाते हैं। ये प्रस्ताव राजस्व स्तरीय कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं जो कि बजट व्यवस्था अनुसार इन प्रस्तावों का निपटाना करती है। स्थानीय जनता द्वारा भूमि तथा कमरों की व्यवस्था, जनसंख्या, पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, फीडिंग स्कूल तथा क्षेत्र की आवश्यकता और पहलुओं को स्कूल स्तरोन्नत करते समय विचार में रखा जाता है।

(ग) नहीं, फिर भी वर्ष 1991-92 में क्षेत्रीय कार्यालयों से केसों की प्राप्ति पर इन स्कूलों पर विचार किया जाएगा।

(घ) उपरोक्त (ग) को मछेनजर रखते हुए कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी जा सकती।

### सूची

चुनाव क्षेत्र बार वर्ष 1990-91 के दौरान अपग्रेड किए गए स्कूलों का ब्यौरा:

क्रम संख्या	जिले का नाम / निर्वाचन	प्राथमिक से मिडल	मिडल से उच्च	उच्च विधालय से 10+2
-------------	------------------------	------------------	--------------	---------------------

	क्षेत्र	स्कूल	विधालय	पद्धति
1	2	3	4	5
1.	<b>जिला अम्बाला</b>			
	नग्गल	1	2	1
	कालका	1	—	1
	नारायणगढ	1	1	1
2.	<b>जिला यमुनानगर</b>			
	रादौर	1	—	—
	जगाधरी	—	—	—
3.	<b>जिला भिवानी</b>			
	तो ाम	2	—	—
	बवानीखेडा	1	1	1
	बाढडा	1	1	1
	दादरी	2	3	2

	मुण्ढाल खुर्द	—	—	1
4.	जिला हिसार			
	भट्टूकला	—	5	6
	बरवाला	1	1	1
	धिराय	1	1	2
	टोहाना	—	—	—
	फतेहबाद	1	—	—
	आदमपुर	1	—	—
	रतिया	2	1	—
5.	जिला गुडगाव			
	पटौदी	1	—	1
	तावडू	1	1	—
	मूह	1	—	—
	सोहना	1	—	—
6.	जिला फरीदाबाद			

	हमनपुर	1	1	1
	पलवल	2	1	2
<b>7.</b>	<b>जिला जीन्द</b>			
	जुलाना	—	—	1
	नरवाना	1	—	1
	उचाना	1	1	1
	सफीदो	—	1	1
<b>8.</b>	<b>जिला करनाल</b>			
	इन्द्री	—	—	1
	जुण्डला	2	2	1
	घरौडा	2	2	—
<b>9.</b>	<b>जिला पानीपत</b>			
	अंसध	—	—	1
	नौलथा	2	2	2
	समालखा	1	—	1

10.	जिला कुरुक्षेत्र			
	थानेसर	1	—	1
	पेहवा	1	—	1
	भाहबाद	—	—	1
11.	जिला कैथल			
	कैथल	—	—	1
	पुण्डरी	2	1	—
	पाई	1	2	1
	कलायत	1	—	1
12.	जिला महेन्द्रगढ			
	अटेली	—	1	1
	नारनौली	2	—	—
13.	जिला रिवाडी			
	रिवाडी	—	—	1

	बावल	1	—	—
	जाटूसान	—	1	1
<b>14.</b>	<b>जिला रोहतक</b>			
	बडौदा	2	1	2
	बादली	1	2	1
	झज्जर	—	1	1
	कलोई	2	—	1
	गोहाना	2	4	3
	कलानौर	1	1	1
	बहादुरगढ	—	—	1
	साहलावास	1	2	1
	मेहम	—	—	2
<b>15.</b>	<b>जिला सोनीपत</b>			
	कैलान	1	1	1
	राई	1	—	1

	रोहट	1	2	1
<b>16.</b>	<b>जिला सिरसा</b>			
	दडबाकंला	1	3	4
	ऐलनाबाद	1	1	1
	डबवाली	—	—	1
	सिरसा	1	2	1
		<b>55</b>	<b>51</b>	<b>60</b>

**श्री हीरा नन्द आर्य:** स्पीकर साहब, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए इलाकों की तरफ, चाहे वह सिरसा जिला हो, चाहे महेन्द्रगढ़ जिला हो, लोहारू का इलाका हो यहाँ मेवात का एरिया हो, क्या कोई विशेष ध्यान रखा गया है? अगर नहीं रखा गया है तो क्या मेरे इलाके में बहनी, भाखरा सिरसी और ओबरा में कोई 10 प्लस 2 के स्कूल अपग्रेड किये जायेंगे क्योंकि इनके आस पास कोई लड़कियों के स्कूल भी नहीं है और ये स्कूल सारी भातें पूरी करते हैं? मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही है कि इन स्कूलों की अपग्रेडेशन की प्रोजेक्ट भी इनके पास आयी थी और ये स्कूल सारी भातें पूरी करते थे लेकिन जो स्कूल अपग्रेड किये गये उनमें यह नहीं है? क्या मेरे हल्के के इन तीनों स्कूलों को अपग्रेड करने पर मंत्री जी विचार करेंगे?

**श्री किान सिंह सागवान:** स्पीकर साहब, जो नौमर्ज है वे मैने बताए है। जो भी स्कूल अपग्रेड किये गये है, वे नौमर्ज के मुताबिक ही और सब चीजो को ध्यान से रखकर किये गये है। उसमे मेवात का भी, बैकवर्ड इलाको का भी और दूसरी सारी बातो को ध्यान रखा गया है। मै यह भी बताना चाहता हू कि कुछ स्कूल पिछले साल यानी 1989-90 मे भी अपग्रेड हुए थे, जब बहिन सुशमा जी मंत्री थी। उस समय जंहा पर ज्यादा स्कूल अपग्रेड हो गये थे, वहा पर अब कम अपग्रेड किये गये है। जहा तक आर्य जी का ताल्लुक है इनके इलाके मे अपग्रेड करने के लिये तीन स्कूल कंसीडर किये जाते है।

**श्री सूरजभान:** अध्यक्ष महोदय, जो जवाब मंत्री महोदय ने दिया है उसमे अगर पहला जिला अम्बाला ही लिया जाये तो यह पता लगता है कि अम्बाला डिस्ट्रिक्ट मे छः कास्टीच्यूऐसीज होने के बावजूद केवल 3 स्कूल ही अपग्रेड किये जाते है यह खुु गी की बात है कि आपके हल्के मे भी स्कूल अपग्रेड हुए है। मै मंत्री जी से पूछना चाहता हू कि स्कूल अपग्रेडेान के लिए उन्होने क्या आइटेरिया रखा हुआ है क्योकि मेरे हल्के मे न तो कोई प्राइमरी स्कूल, न मिडल न ही कोई हाई स्कूल अपग्रेड किया गया है। इसका क्या का कारण है ?

**श्री किान सांगवान:** स्पीकर साहब, इसमे हल्के वाली कोई बात नही है। जो भी स्कूल नौमर्ज पूरा करते है, हमने वहां पर ही स्कूलो को अपग्रेड किया है स्पीकर साहब, हम सभी सदस्यो

का ध्यान रखते हैं जहाँ से भी डिमाण्ड आई है और नौम्बर्ज पूरे हुए हैं हम उनको अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं।

**श्री मुनी लाल:** स्पीकर साहब,

**Mr. Speaker:** Muni Lal Ji, please take your seat. I have not permitted you to speak. Dr. Maha Singh.

**श्री महा सिंह:** स्पीकर साहब, जो स्टेटमैट सदन के पटल पर रखी गई है उसके अनुसार कास्टिचूऐसी राइज में एक प्राइमरी से मिडिल स्कूल अपग्रेड किया है और एम 10+2 का अपग्रेड किया है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि 10+2 का जो स्कूल अपग्रेड किया है वह कौन सा है ?

**श्री किान सिंह सागवान:** स्पीकर साहब, स्कूलों के नाम की लिस्ट इस समय मेरे पास नहीं है।

**श्री योगेश चन्द भार्मा:** क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि फरीदाबाद की पलवल तथा हसनपुर कास्टिचूऐसीज को छोड़कर दूसरी कास्टिचूऐसीज का कोई भी स्कूल अपग्रेड न करने का क्या कारण है? पलवल में पांच स्कूल अपग्रेड किए हैं और हसनपुर में तीन स्कूल अपग्रेड किए हैं। क्या यह बात जाहिर नहीं करती कि विपक्ष के सदस्यों के साथ दुभांति बरती जाती है ?

**श्री किान सिंह सागवान:** स्पीकर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। सत्ता पक्ष के सदस्य जो कुछ ऐसे हैं जिनके यहाँ

कोई स्कूल अपग्रेड नहीं किया गया। हम सभी सदस्यों को एक जैसी ही मानते हैं।

**श्री राम बिलास भार्मा:** स्पीकर साहब, जो लिस्ट हमारे सामने है उससे पता लगता है कि गोहाना में 9 स्कूल, दडवा कला में 8, दादरी में 7 और भटटूकल में 6 स्कूल अपग्रेड किए हैं। बाकी जो चुनाव क्षेत्र है, जैसे महेन्द्रगढ में कोई स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ और लोहारू में कोई नहीं हुआ। स्पीकर साहब, तीस चुनाव क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ कोई भी स्कूल अपग्रेड नहीं किया गया। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि गोहाना दडवा कला, दादरी और भटटूकला ही ऐसे क्षेत्र हैं जो नौमर्ज को पूरा करते थे और कोई ऐसी जगह नहीं है जो नौमर्ज को पूरा करते हो ?

**श्री किान सिंह सागवाना:** स्पीकर साहब, ये सब जगह आईटेरिया पूरा करती थीं इसमें कास्टिचुऐसी या पक्षपात की कोई बात नहीं है। सत्ता पक्ष के सदस्यों की भी ऐसी जगह हैं जहाँ कोई स्कूल अपग्रेड नहीं किया गया लेकिन विपक्ष के सदस्यों की कास्टिचुऐसीज में स्कूल अपग्रेड किए गए हैं।

**डा० रघुबीर सिंह:** स्पीकर साहब, स्कूल अपग्रेडे की लिस्ट दी है, उसमें कहीं पर 9, कहीं पर 8 और कहीं पर 7 और कहीं पर 6 स्कूल अपग्रेड किए हैं। यह लिस्ट अपने आप में पक्षपात दर्शाती है और यह बात साबित होती है कि अंधा बाटे भीरनी अपने अपने को दे। स्पीकर साहब, इसमें क्लीयरकट

फेवरटिज्म और नैपोटिज्म जाहिर होता है कि ये स्कूल पक्षपात से अपग्रेड किए गए हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ये सब स्कूल नौमर्ज को पर करते थे और कितने ऐसे स्कूल रह गए जो नौमर्ज को पूरा करते हैं लेकिन अपग्रेड नहीं किए गए ?

**श्री किान सिंह सागवाना:** स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने जो यह ऐलगिान लगाया है कि पोलिटीकल कसीड्रेान से स्कूलों को अपग्रेड किया गया है यह बात ठीक नहीं है। जो कडीान फुलफिल करते थे वे स्कूल मिडल होने के लिये वे 149 थे उनमें से 55 अपग्रेड किए गए। मिडिल से हाई होने का जो आर्टेरिया पूरा करते थे वे 194 थे उनमें से 51 अपग्रेड किए गए। हाई स्कूल से सीनियर सैकण्डरी स्कूल होने का जो आर्टेरिया पूरा करते थे वे 217 थे लेकिन उनमें से साठ अपग्रेड किए गए।

**श्री वीरेन्द्र सिंह:** अध्यक्ष महोदय, जिला हिसार में विधान सभा के 10 हल्के हैं जिनमें से 7 हल्कों में स्कूल अपग्रेड किये गये हैं तीन हल्के छोड़ गये हैं। इनमें एक नारनौंद, जहा से मैं विधायक हूँ दूसरा हिसार जहा से हरिसिंह सैनी व तीसरा हल्का हांसी, जहा से श्री पी०के० चौधरी विधायक हैं। इन विपक्ष के हल्कों को जानबूझ कर छोड़ा गया है। दूसरी बात यह है कि मेरे हल्के में एक गांव जामनीखेडा है मैं और आज के मुख्यमंत्री एक बार वहा पर गये थे और वहा लोगों ने जब उनके सामने यह मांग की थी कि हमारे स्कूल को अपग्रेड किया गया तो उस वक्त मुख्य

मंत्री महोदय जी ने इस बारे में लोगों को विवास दिलाया था कि कुछ जोर मैं मारूंगा और कुछ जोर यदि चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी मारेगे जो यह काम हो जाएगा। मगर अभी तक वह स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को यह कहूंगा कि अब आप तो यह काम उन्हीं की कलम से हो सकता है। वे कब तक उस स्कूल को अपग्रेड कर देंगे ?

**श्री किान सिंह सागवाना:** अध्यक्ष महोदय, चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने जिस स्कूल का नाम बताया है उसको, जब अगले साल सम्बन्धित कमेटी बैठेगी, अब यही कसिडर किया जाएगा।

**श्री भगवान सहाय रावत:** अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि पिछड़े क्षेत्रों का शिक्षा के मामले में ध्यान रखा गया है। स्पीकर साहब, मेवात भी पिछड़े क्षेत्र में आता है और फरीदाबाद जिले में हथीन भी आता है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि बचारी व कौडल के लड़कियों के मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल, लोहैना के प्राईमरी स्कूल को मिडिल व अन्धोपा और गुराकसर के मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल करने का सरकार का कोई विचार है जबकि वे सभी फुलफिल करते हैं ?

**श्री किान सिंह सागवाना:** माननीय सदस्य महोदय ने जो स्पैसिफिक स्कूलों के बारे में पूछा है उस बारे में मैं आफ हैंड नहीं बात सकता। इसके लिये सैपरेट नोटिस दे तो हम बता देंगे।

**श्रीमती कमला वर्मा:** अध्यक्ष महोदय, सढौरा, छछरौली व यमुनानगर ये तीनो बडे क्षेत्र है और यहां तीनो सदस्य विपक्ष के है। इन इलाको मे किसी भी स्कूल को अपग्रेड नही किया गया है। क्या मंत्री महोदय बताने का कश्ट करेगे कि इन क्षेत्रो मे किसी भी स्कूल को अपग्रेड न करने के क्या कारण है ?

**श्री किान सिंह सागवाना:** अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नही है कि विपक्ष के सदस्यो के हल्को मे स्कूलो को अपग्रेड नही किया गया। लिस्ट पढे तो उनको पता चलेगा कि बहुत से ऐसे स्कूलो को अपग्रेड किया गया है जो कि विपक्ष के सदस्यो के हल्को से सम्बन्धित है। जो जो स्कूल सरकार के आईटेरिया को फुलफिल करते थे वहा स्कूलो को अपग्रेड किया गया है।

**श्री मुनी लाल:** मै मंत्री महोदय से जानना चाहता हू कि खोरी तथा सैरनवास के हाई स्कूलो को 10+2, और झाबवा के प्राईमरी स्कूल को मिडल स्कूल व प्रोथर के मिडल स्कूल को हाई स्कूल बनाने का सरकार कोई विचार रखती है। क्योकि ये सभी स्कूल अपग्रेडे इन के सभी नौर्मज को पूर करते है ?

**श्री किान सिंह सागवाना:** अध्यक्ष महोदय, अगले साल इनको कसिडर करने का प्रयत्न किया जाएगा।

**श्री महा सिंह:** अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के मे कोई स्कूल अपग्रेड नही किया गया है। मंत्री महोदय जो कर रहे है कि वहा पर स्कूल अपग्रेड किये गये है यह बिल्कुल गलत है। क्या मंत्री

महोदय मेरे हल्के मे स्कूलो की अप ग्रेडे ान का विचार रखते है ?

**श्री कि ान सिंह सागवान:** अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसी बात है तो हम इसके लिये सीरियसली नोटिस लेगे और बाकयदा इसकी जाच करवाएगे ।

**श्री ि ाव प्रसाद:** अध्यक्ष महोदय, सब से पहले हमारा जिला अम्बाला आता है जिसमे अम्बाला, अम्बाला छावनी और मुलाना का क्षेत्र आता है । इन जगहो मे क्या मंत्री महोदय की कृपा करेगे कि जो स्कूल सरकार के नौर्मज पूरा करते है उन स्कूलो के अप ग्रेडे ान मे जो कमी रह गयी है क्या एस पर सरकार विचार करेगी ?

**मुख्यमंत्री (श्री हुकम सिंह):** स्पीकर साहब, विधायको की रिकमैन्डे ान पर ही स्कूल अपग्रेड होते है और जिला से डी0ई0ओ0 की भी रिकमैन्डे ान होती है । इसके लिए एक कमेटी होती है जिस के अध्यक्ष ि ाक्षा मंत्री होते है । इस साल जो स्कूल अपग्रेड हुए है, वे सभी नौर्मज को पूरा करते हगे, तभी अपग्रेड किये गये हगे । पिछले साल किन्ही जिलो मे कम व किन्ही से ज्यादा स्कूल अपग्रेड किये गये हगे । पिछले साल किन्ही जिलो मे कम व किन्ही जिलो मे ज्यादा स्कूल अपग्रेड हो गये थे लेकिन मै हाउस को यकीन दिलाता हू कि जहां नौर्मज पूरे होते हगे और

जहा जहा पर आव यकता भी होगी, इन सभी बातो को ध्यान मे रखते हुए स्कूल अपग्रेड किये जाऐगा।

### **Breed of Cows and Buffaloes**

**\*1402 Shri Lachman Singh Kamboj:** Will the Minister of State for Animal Husbandry be pleased to state-

(a) the breed wise number of cows and buffaloes in Govt, Livestock Farm, Hissar, during the years 1985-86, 1986-87 1987-88,. 1988-89 and at present i.e up to 28-2-1991; and

(b) whether any stray cows have been caught during the period as referred to in part (a) abvoe; if so, the number thereof?

**Minister of State for Animal Husbandry (Shri Kulbir Singh Malik):**

(a) Breed wise number of cows and buffaloes at Govt. Livestock Farm, Hissar, during the years 1985-86, to 28-2-1991 is given in the table at Annexure - I

(b) Yes, the number is given in the table at Annexure H

### **ANNEXURE - 1**

**Breed wise number of cows and buffaloes at Govt Livestock Farm Hissar during 1985-86 to 28-2-1991**

Year	Haryana	Sahiwal	Tharparkar	Milich Buffaloes	Total

1985-86	248	159	96	-	503
1986-87	251	179	102	-	532
1987-88	256	164	90	-	510
1988-89	263	169	105	-	537
1989-90	276	167	111	-	554
1990-91	274	156	107	-	537
(upto 28-2- 1991)					

**ANNEXURE - 1**

**Number of stray cows caught during the period  
form 1985-86 to 28-2-1991**

Year	Number
1985-86	-
1986-87	-
1987-88	682
1988-89	906
1989-90	762
1990-91	710
(upto 28-2-1991)	

**श्री लक्षमन सिंह कम्बोज:** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूँ कि इनमें मेल कितने हैं और फीमेल कितनी है। इसके अलावा इनमें दूध देने वाली गाय कितनी है ?

**श्री कुलबीर सिंह मलिक:** स्पीकर साहब, मेरे लायक दोस्त पहले इस महकमे के खुद मंत्री रहे हैं। इन्होंने इस महकमे में अच्छा दूध पिया है। अध्यक्ष महोदय दुधारू गायों को वश 1985-86 से 1990-91 तक की सख्या अनैक्टार - 1 में दी हुई है मैम्बर साहब पढ़ने का कष्ट करें। इसी तरह से आवारों पर लूओ की सख्या अनैक्टार II में दी हुई है।

**श्री कैलाश चन्द भार्गव:** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि दुधारू गायों को दाना और चार किस नौर्म से दिया जाता है ?

**श्री कुलबीर सिंह मलिक:** स्पीकर साहब, बिल्कुल नौर्मज के मुताबिक ही दाना ओर चारा दिया जाता है। उसमें किसी किस्म की, कौताही नहीं रखी जाती है। फार्म में बड़े जिम्मेदार अफसर बैठे हैं। वहाँ पर हमारे चीफ सुप्रिन्टैन्डेंट है जो ज्वायंट डायरेक्टर के रैंक के हैं।

**श्री लक्षमन सिंह कम्बोज:** स्पीकर साहब, हमारे हिसार फार्म के चार सौ भेड़े चोरी हो गई थी, क्या वे बरामद हो गई हैं ?

**श्री अध्यक्ष:** कम्बोज साहब, क्या आपको भेडो और गायो मे फर्क का पता नही है ?

**श्री कुलबीर सिंह मलिक:** स्पीकर साहब, हमारी 13 भेडे चोरी हुई थी जो उधर बैठी है। (हंसी)।

**डा० रघुबीर सिंह:** स्पीकर साहब, हिसार लाइव स्टीक फार्म ब्रिटि 1 टाईम से ऐग्जिस्टैस मे है मै मंत्री महोद से जानना चाहता हू कि उस फार्म के औब्जैक्टस कौमि यिल है या साइटिफिक है और क्या सभी औब्जैक्टस अचीव हो रह है, अगर नही हो रहे तो उसको अचीव करने के लिए सरकार ने क्या स्टैप्स लिए है?

**श्री कुलबीर सिंह मलिक:** स्पीकर साहब, कादियान साहब इस मामले मे माहिर है क्योकि ये खुद प ुओ के डाक्टर भी रहे है। मै इनको बताना चाहूंगा कि हम उस फार्म मे चार पांच किस्म की गाय रखते है उनसे बहुत बढिया किस्म का ब्रीड तैयार करते है इसके अलावा वहा पर फोरमैन सीमैन भी रखते है। उसको हम कई दूसरी जगहो पर भेजते है। उस फार्म मे बढिया किस्म के साड भी तैयार किए जाते है। यदि किसी गांव की पंचायत को या किसी म्यूनिसिपल कमेटी को या किसी गऊ ाला को साडो की जरूरत हो तो हम उनको पाच हजार कीमत का साड रियासत वे कर एक हजार रूपए मे देते है।

**डा० रघुवीर सिंह:** स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

**श्री अध्यक्ष:** कादियान साहब, मंत्री जी ने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। आप बैठिए।

**श्री राम बिलास भार्मा:** अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने आवार गायों के बारे में बताया है कि क्योंकि यह सरकार आवार सास्कृति ने बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो आवारों गायें रखी हुई हैं उनको आपने दूध के लिए रखा हुआ है या आवार बनाने के लिए रखा हुआ है?

**श्री कु लबीर सिंह मल्लिम:** स्पीकर साहब, हम आवार पशुओं को डिस्पलिन में लाना चाहता हैं। चाहे किसी किस्म की आवारा गाय हो हम उनको गो सदन में रखते हैं जो कि 1987-88 में हिसार के अन्दर चालू किया गया है। राजस्थान में पिछले कुछ अर्से में बहुत भयंकर अकाल पड़ गया था जिसके कारण बहुत सी गायें वहाँ से आ गई थी, उनको हमने पहले तो फाटक में रिलौफ कैम्प के तौर पर रखा। फिर उसके बाद उन गायों को हमने हिसार गो सदन में रखा। हिसार गो सदन में कुछ गायें तो उसकसमय की हैं और कुछ गायें ऐसी भी रखी हुई हैं जिनके बारे में पचायतो ने दरखास्त दी है कि जो रानी गायें हैं वे हमारे खेतों में घूम रही हैं और फसलों का नुकसान करती हैं। उन गायों को

भी हमने उस गो सदन मे रखा हुआ है। कुछ गाय ऐसी है जो मरने की स्टेज पर है। कुछ गाये ऐसी है जो फार्म मे चरने के लिए चली जाती है तो उनको पकड कर फाटक मे दे देते है और उनका फाटक मे 7 दिन तक रखते है यदि 7 दिन के अन्दर अन्दर उनका कोई मालिक आ जाता है तो उससे चारे के पैसे ले करके उन्हे छोडा दिया जाता है। चारे के पैसे बहुत ही नौमिनल है। अगर कोई नहीं आता है उन गायो को भी गो सदन मे भेजे देते है। ऐसी गायो को हम उनकी रक्षा के लिए रखते है। गाय को हम माता की तरह रखते है, ऐसी गायो को हम दूध के लिए नहीं रखते।

**श्री अध्यक्ष:** यदि गाय को हम माता कहते है तो बैल को क्या पदवी देगे?

**श्री कुलबीर सिंह मलिक:** स्पीकर साहब, उसको हम बाप की पदवी देगे। (हंसी)

**श्री महा सिंह:** स्पीकर साहब, मै आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हू कि क्या हिसार लाइव स्टीक फार्म मे देहात के आम गरीब लोगो को सस्ते रेट पर गाय देने का प्रवाधान है, अगर नहीं तो क्या सरकार इस बारे मे विचार करेगी ?

**श्री कुलबीर सिंह मलिक:** स्पीकर साहब, लाइव स्टीक फार्म मे अच्छा ब्रीज तैयार करने के लिए गाये रखी जाती है। यदि किसी आदमी को बैहडी या बछडी की जरूरत है तो उसके लिए

वहा पर महीने के पहले मंगलवार को बोली होती है उस बोली में जो कोई आदमी बैहडी या बछडी लेना चाहे वह ले सकता है। वह बहडी या बछडी ऐसी होती है तो ब्रीड के लिए ठीक नहीं होती।

**श्री सीत राम सिंगला:** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि जो राशि पशुओं के चारे के लिए निर्धारित की जाती है क्या उस राशि को डेली बेजिज पर जो कर्मचारी रखे हुए है उन पर तो खर्च नहीं किया जा रहा है क्योंकि जो पशु वहा पर रखे हुए है उनको पूरा चारा न देकर के हरी घास जो ये वहा पर खुद पैदा करते हैं खिलाते हैं लेकिन जिस हिसार में चारा इन पशुओं को वहा पर मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता। मेरे कहने का मतलब यही है कि जो लोग पोलिटिकल प्रेसर आदि की वजह से लगाये जाते हैं उन्हीं पर ही पशुओं के चारे का पैसा खर्च कर दिया जाता है?

**श्री कुलबीर सिंह मलिक:** स्पीकर साहब, जितना सवला मैं इनका समझ पाया हूँ उस का जवाब मैं दे देता हूँ। वहा पर दो किस्म की गायें रखी जाती हैं। मैं इनको फिर कलियर कर देता हूँ कि वहा पर गऊ सदन में जो गायें रखी जाती हैं उनको केवल जिन्दा रखने के लिए ही पकडा जाता है और उनको चारा वही दिया जाता है जो हम वा पर घास गगैरहा पैदा करते हैं दूसरे दूधारू गाय और दूधारू बछडियो जो होती हैं उनके लिए जो चारा मौसम के हिसब से दिया जाना होता है, वह देते हैं।

**श्री सीता राम सिंगला:** स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने पूछा है कि जो पैसा पशुओं के चारे के लिए रखा जाता है क्या वह डेली बेजिज पर रखे गए कर्मचारियों की पे के लिए तो ट्रांसफर नहीं किया जाता?

**Mr. Speaker:** Your question is ambiguous. Please take your seat.

**श्री हीरा नन्द आर्य:** अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि जो गाय और बछड़ियाँ दूध देने में नाकार हो जाती हैं उनको किसानों को देते हैं स्पीकर साहब, जब सरकार उन्हें दूधारू नहीं बना सकती तो फिर ऐसी गायों को किसानों को देने का क्या फायदा क्योंकि जो ऐसी नाकार गाय वहाँ पर बेची जाती हैं उनमें बीमारियाँ भी बहुत अधिक होती हैं ?

**श्री कुलबीर सिंह मलिक:** स्पीकर साहब, जो जवाब मैंने पहले दिया है उसको भायद ये ठीक तरह से समझ नहीं पाये। मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि जो बछड़ियाँ या गाय बुल पैदा नहीं कर सकती और दूध में नाकार हो जाती हैं केवल उन्हीं की बोली हम हर मंगलवार को करते हैं।

**श्री सीत राम सिंगला:** स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि जो राशि के चारे के लिए निर्धारित की हुई है क्या उस राशि को डेली बेजिज पर लगे कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर तो नहीं किया जाता ?

**श्री कुलबीर सिंह मलिक:** अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि वहा 500-600 आदमी डेली वेजिज पर लगे हुए है। वहा पर जो हमारा खर्चा होता है वह तकरीबन एक करोड साठ लाख सालाना है। इसमे से एक करोड तो हम दूध या जो ऊन बेचते है उससे पूरा कर लेते है और 60 लाख रूपये का जो खर्चा बचता है उसको हम बीज व चारे आदि को बेच कर पूर कर लेते है क्याकि हम वहां पर अच्छे बीज व चारा भी पैदा करते है। यह मेरी समझ नही आया कि ये इस डेली वेजिज के मामले को कहा से ले आए?

**श्री सीता राम सिंगला:** स्पीकर साहब, तो उत्तर इन्होने दिया है यह सतोशजनक नही है।

**डा० हरनाम सिंह:** स्पीकर साहब, वहां पर 3 किस्म की 503 गाय 1985-86 मे थी। मै जानना चाहता हू कि जो हर साल गाय या बछडियो की पैदावार बढती है उनके जो बछडे होते है वे तो सीमैन के लिए सैन्टरो मे चले जाते है लेकिन जो बछडिया रहती है उनका क्या करते है? मेरे पूछने का मकसद सिर्फ इतना है कि 503 गायो से जो पैदावार बछडियो की हुई, वे कितने लोगो को किस रेट पर दी गई?

**10.00 बजे**

**श्री कुलबीर सिंह मलिक:** अध्यक्ष महोदय, मै माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि आये महीने गायो को डिस्पोज औफ किया जाता है। महीने के पहले मंगलवार को बोली होती है।

बोली के लिए एक कमेटी बनी हुई जिसे कलिंग कमेटी कहते हैं जिसमें चीफ सुपरिन्टैन्डेंट, फौर्ज, स्टेट कैटल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट का डायरेक्टर, यूनिवर्सिटी का एनिमल साईंस का एक एक्सपर्ट, डी०सी० का एक रि प्रैजैन्टेटिव तथा एक सैक्टर सुपरिन्टैन्डेंट होता है। ये पांचो मिल कर महीने के पहले मंगलवार को बछड़ियो की कीमत बुक वैल्यू पर निर्धारित करके उन्हें बेचते हैं।

### **Canal for Supplying of Drinking Water**

**\*1367 Shri Sita Ram Singla:** Will the Minister for irrigation and power be pleased to state-

(a) whether it is a fact that any scheme has been formulated by the Govt. for supplying of drinking water in Gurgaon through a Canal, digging of which was inaugurated by the Chief Minister, Haryana during last year;

(b) if so, the total amount, if any, received so far from HUDA and Municipal Committee Gurgaon by the Irrigation Department for the said purposes; and

(c) the extent to which the digging work of the said canal has been completed together with the time by which the construction work of the said canal is likely to be completed?

**गृह मंत्री प्रो० सम्पत सिंह:**

(क) हां जी।

(ख) 10 करोड रूपये हुडडा से।

(ग) 28.2.1991 तक प्रगति

मिट्टी का कार्य	113400 घनमीटर
लाईनिंग	675 वर्गमीटर

इस स्कीम के जून 1992 तक पूरा होने की सम्भावना है।

**श्री सीतराम सिंगला:** अध्यक्ष महादेय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हू कि इस काम पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च हुई है और अधिकारियों के दफतर फर्नीचर और अन्य कार्यों पर कितनी राशि खर्च हुई है ?

**प्रो० सम्पत सिंह:** स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हू कि 38932000 रूपये टोटल राशि खर्च हुई है। जिसमें से सबसे ज्यादा खर्च लैण्ड कम्पनसेशन पर हुआ है। लैण्ड कम्पनसेशन पर 28662000 रूपये खर्च हुए हैं और बाकी ऐस्टेब्लिशमेंट और अन्य कामों पर खर्च हुआ है। बाकायदा प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है जिसमें अर्थ वर्क और माईनर्ज आदि का खर्च होता है।

**श्री सीता राम सिंगला:** स्पीकर साहब, मेरा प्रश्न यह था कि कुल कितना खर्च हुआ है और उसमें से अधिकारियों के दफतर पर फर्नीचर आदि पर कितना खर्च हुआ है ?

**प्र० सम्पत सिंह:** स्पीकर सर, मैंने पहले ही बता दिया है कि जमीन की कम्पनसे 1 न पर 28662000 रूपये खर्च हुए हैं बाकी पैसा दूसरे कार्यों पर खर्च हुआ है।

**श्री अनिल कुमार विज:** अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में किसी अन्य जगह पर कौनाल बेस्ड ड्रिडिंग वाटर स्कीम विचारधीन है ?

**प्र० सम्पत सिंह:** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि भाहरो और गावों में जहाँ जहाँ पीने के पान की आवश्यकता होती है उसके मुताबिक ही स्कीम बनाई जाती है

**श्री भगवान सहाय रावत:** अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गुडगाव नहर की पेयजल की जो योजना है उसी सप्लाई कहा से होगी और यह नहर कहा कहा से आएगी और पीने के पानी के अतिरिक्त भी इसके पानी की कृषि के लिए उपयोग करने बारे भी क्या सरकार विचार करेगी ?

**प्र० सम्पत सिंह:** स्पीकर साहब, पानी यमुना से लिया जाएगा और टोटल 135 क्यूसिक पानी पीने के काम आएगा। अगर आवश्यकता से फालतू पानी होगा तो इसे कृषि के लिए इस्तेमाल करने बारे विचार किया जाएगा। अभी तो यह मामला काफी लम्बा है।

**श्री सीता राम बिलास:** अध्यक्ष महोदय, जिस गति से काम चल रहा है अगर इस गति से चलता रहा तो क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि यह काम 1922 तक पूरा हो जाएगा ?

**प्रो० सम्पत सिंह:** कार्य 1992 तक बाकायदा पूरा हो जाएगा ।

**श्री कैला । चन्द भार्मा:** अध्यक्ष महोदय, हमारे योग्य मंत्री महोदय बताएंगे कि क्या रिवाडी में भी पेयजल की सप्लाई की जाएगी ?

**प्रो० सम्पत सिंह:** स्पीकर साहब, यह स्कीम तो गुडगाव और बहादुरगढ के लिए है । रिवाडी के लिए इस स्कीम में से पानी देने की कोई योजना नहीं है ।

**श्री भगवान सहाय रावत:** अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि 135 क्यूसिक पानी तो पेयजल के लिए इस्तेमाल होगा और बाकी का पानी कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल होगा । क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि कृषि के लिए जो पानी इस्तेमाल होगा वा किस किस जगह कों दिया जाएगा ?

**प्रो० सम्पत सिंह:** स्पीकर सर, सबसे पहले तो गुडगाव और बहादुरगढ की पेयजल की आवकताओ पूरी की जाएगी । किस किस जगह को कृषि कार्य के लिए पानी दिया जाएगा वह तो बाद में देखा जाएगा ।

## **Allotment of plots of Economically Weaker Sections**

**\*1335. Shri Suraj Bhan:** Will the Minister of State for Tourism and Welfare of Scheduled Castes and Backward classess be pleases to State whether there is any scheme under consideration of the Government to allot residential plots to the Scheduled Castes, Backward Classes and Economically Weaker Sections of the Society in the State; if so, the details there of?

**पर्यटन राज्य मंत्री (श्री श्रीकृष्ण हुडडा):** नहीं।

**श्री सूरज भान:** अध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्री जी का जवाब पढकर बहुत अफसोस हुआ है। देहात मे और भाहरो मे भी इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। स्पीकर साहब, जिन परिवारो के सदस्यो की सख्या बढ गयी है, उनके मकान उतने ही छोटे पड गए है। इस चीज को ध्यान मे रखते हुए सरकार को हरियाणा के डिप्टी कमि। जर्न से इत्तलाह मागी थी और कहा था कि जितने भी नीजी परसन्ज, गरीब, पिछडे वर्ग के या इकोनोमिकल वीकर सैव। अन्श्रज के लोग है। उनको मकान बनाने के लिये जगह देनी है। उनकी लिस्ट दिसम्बर 1989 तक मांगी गयी थी और यह सूचना यह सोचकर मांगी गयी थी कि उनको प्लाट दिये जायेगे। यही नहीं इसके लिये सैट्रल गवर्नमेंट से फडज भी मिलते है। सैट्रल सहायता भी मिलती है। लेकिन मुझे अफसोस है कि इन्होने यह कह दिया है कि ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है मै यह जानना

चाहता हू कि उन लिस्टो का जो मागी गयी थी, क्या हुआ और उनके बारे में क्या फैसला किया है ?

**श्री श्री कृष्ण हुड्डा:** स्पीकर साहब, ये प्लॉट्स हमारा विभाग नहीं देता। दूसरे विभाग द्वारा ये प्लॉट्स दिये जाते हैं ये प्लॉट्स त्यागी साहब का विभाग देता है हमारी ऐसी कोई स्कीम नहीं है। पहला सर्वे 1974 में और दूसरा सर्वे 1978 में किया गया था। उसके मुताबिक 299082 परसंज को प्लॉट्स के लिए ऐलीजिबल पाया गया था उनमें से सरकार ने 298703 व्यक्तियों को प्लॉट्स अलाट किये हैं। भोश कठिन 379 मामलों में 184 व्यक्तियों के लिए भूमि अधिसूचना जारी की गयी है। इसके लिए 8.00 लाख रुपये का प्रोवीजन किया गया था। इसमें से उपायुक्तों को 7744665 रु0 97 पैसे दिये गये हैं।

**श्री सुरज भान:** स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है। चौधरी देवी लाल जी ने यह स्कीम मजूर की थी और यह कहा था कि लिस्टे मगवा लो। उसका जवाब नहीं आया।

**श्री श्रीकृष्ण हुड्डा:** स्पीकर साहब, तीसरा सर्वे अभी पूरा नहीं हुआ है उपायुक्त महोदय ऐलिजिबल केसिज की छानीबीन कर रहे हैं।

**श्री रतन लाल कटारिया:** स्पीकर साहब.....

**श्री अध्यक्ष:** आज आप की पगड़ी कहा है?..... (हंसी)

**श्री रतन लाल कटारिया:** स्पीकर साहब, पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि कल मेरी पगड़ी का आपने थोड़ा सा जिकर कर दिया था। इसलिये परवाना साहब ने अखबार में इसके बारे में लिख दिया। मेरी इस पगड़ी को देखने के लिये इतनी जनता उमड़ पड़ी कि मैंने उसको एग्जीबीटिव के लिये रख दिया ताकि लोगो उसको देख सकें। मैंने यह सोचा कि मैं जार हाउस अटैंड कर लेता हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी एक बात जानना चाहता हूँ मेरे एक सवाल के जवाब में मंत्री महोदय ने यह कहा था कि वे इस बारे में एक पौलिसी स्टेटमेंट देंगे। (व्यवधान एवम भोर) इनके यहाँ पर लोकल बौडी के मंत्री कांति प्रकाश भल्ला जी हैं जो पूरे पहलवान हैं। (व्यवधान एवम भोर)

#### **Appinment of Head Master**

**\*1345 Shri Muni Lal:** Will the Minister of State for Educaiton please to state-

(a) the district wise the number of Head Master appointed in primary and High Schools, speareately in the State During the period form 1998 to 1990; and

(b) the number of Head Masters out of those referred to in part (a) above belonging to Scheduled Castes and Backward Classes?

**Agriculture Minister (Shri Kishan Singh Sangwan):** (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

**Statement showing the No. of Headmaster/Head teachers in Government High/ Primary Schools promoted appointed form 1988-1990.**

No.of.promotions/appoi ntments of Headmasters of High School (information is for the entire states as ti is a State Cadre)	Those belonging to S.C / B.C	
	S.C	B.C
346	35	33

No.of.promotions of Headmasters of High School (information is for the entire states as ti is a State Cadre)	Gen	S.C	B.C	Total
1. Ambala/Yamunannagar	641	131	83	855
2. Bhiwani	400	64	64	528
3. Faridabad	400	39	28	467
4. Gurgaon	581	60	49	690
5. Hisar	575	65	48	688

6. Jind	352	58	48	458
7. Karnal/Panipal	257	37	31	325
8. Kurukshetra/Katihah	502	83	57	642
9. Mohinderghar/Rewari	563	65	39	667
10. Rohtak	374	60	33	467
11. Sonipat	265	46	22	335
12. Sirsa	302	54	31	407
Total	5212	762	553	6527

**श्री मुनी लाल:** स्पीकर साहब, इन्होंने जो जवाब दिया है उसके अनुसार 5212 मास्टर्ज तो जनरल कैटगरी से भर्ती किये हैं, 762 डिप्लोमा कास्टस के और 553 बैकवर्ड क्लासिज के भर्ती किये गये हैं। मेरे कहने का मतलब है कि यह कम भर्ती किये गये हैं। क्या आदमी नहीं मिले या और कोई कारण है ?

**श्री किान सिंह सागवान:** माननीय साथी ने जो यह फिगरज पढी है यह हैड टीचर्ज की फिगरज है जो हमने दी है। ये सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट काडर की पोस्टस है और ये सारी भर्ती प्रोमोशन से हुई है तभी हैड टीचर्ज लगाये गये हैं। प्रोमोशन करने के लिये कडीशन होती है जिसमें बाकायदा 6 साल का ऐक्सपीरियंस होना चाहिये। जो इनको पूरा करते हैं उन्हीं को हैड टीचर लगाते हैं। इसमें और कोई आइटेरिया नहीं है। यह ऐक्सपीरियंस की बिना पर बैकलोग है।

**श्री परमानन्द:** स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि हैड टीचर्ज की अप्वायटमेंट प्रोमोशन से होती है और उसके लिए छः साल का ऐस्कपीरियैस होना जरूरी है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस समय जे०बी०टी० टीचर्ज का छ साल का ऐक्सपीरियैस पूरा करने वाले कितने एस०सी० और बी०सी० टीचर्ज अवेलेबल हैं ?

**श्री किान सिंह सागवान:** स्पीकर साहब, कोई बकाया नहीं बचा है।

**श्री सीता राम सिंगला:** क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि 5212 टीचर्ज को प्रोमोट करने के बाद विभाग के पास इस बारे में कोई रिक्वायर्मेंट आई है या कोई कोर्ट में केस गया है? दूसरे सवाल यह है कि क्या प्रोमोशन होने के बाद कोई स्कूल बच गया है जहां अभी हैड टीचर्ज की डिमाण्ड है?

**श्री किान सिंह सागवान:** स्पीकर साहब, ऐसे स्कूल बचे हैं जहां हैड टीचर्ज प्रोमोट नहीं हुए लेकिन मैं नाम नहीं बता सकता। जहां तक कम्प्लेट की बात है इस वक्त हमारे पास कोई कम्प्लेट पैडिंग नहीं है।

**श्री सूरज भान:** स्पीकर साहब, तीन सालों का बैकलॉग है जिसमें 280 भाड्यूल्ड कास्टस को प्रोमोट नहीं किया जा सका और इससे पहले का भी बैकलॉग होगा। स्पीकर साहब, शिक्षा विभाग में बहुत ज्यादा बैकलॉग भाड्यूल्ड कास्टस और बैकवर्ड

क्लासिज का है। चाहिए तो यह था कि बैकलोग को पूरा करने की कोर्ि । । की जाती लेकिन बदकिस्मती यह है कि 18 तारीख को कैबिनेट की सब कमेटी की कोई मीटिंग होने जा रही है। जिसमें यह फैसला होने जा रहा है कि क्लास श्री मे प्रोमो इन मे रिजर्वे इन को खत्म किया जाए। ( गोर एवम व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** आप सप्लीमेंटरी कीजिए।

**श्री सूरज भान:** क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस बैकलोग को कब पूरा कर दिया जाएगा ?

**श्री कि इन सिंह सागवान:** स्पीकर साहब, बड़ा अच्छा सवाल लीडर आफ दि अपोजी इन ने किया है। मैं सदन को बताना चाहता हू कि 1988 में पहली जितनी भी अप्वायटमेंट्स होती थी चाहे वा डायरेक्ट हो य किसी ऐडवरटाइजमेंट या ऐम्पलाएमेंट ऐस्सचेंज के थ्रू हो, पोस्टस के लिए तीन बार ऐडवरटाइजमेंट होती थी और अगर तीन बार के ऐडवरटाइजमेंट के बाद भी कोई सूटबेल केन्डीडेट भाडयूल्ड कास्टस का या बैकवर्ड क्लास का नहीं मिलता था तो पोस्टस को जनरल कैटगरी के कन्वर्ट कर दिया जाता था लेकिन इस सरकार ने फैसला किया कि भाडयूल्ड कास्टस और बैकवर्ड क्लासिज के लोगों के राइटस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए और बैकलौग न बढ़े इस सम्बन्ध में 1988 में यह फैसला किया कि अगर तीन बार ऐडवरटाइजमेंट करने के

बाद श्री सिडयूल्ड कास्टस और बैकवर्ड क्लास के कैंडीडेटस न मिले तो भी उन पोस्टस को जनरल में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा।

**श्री हीरा नन्द आर्य:** स्पीकर साहब, मैं आपकी रूनिग चाहूंगा कि क्या कोई ऐसा मंत्री बनाया जा सकता है जो हाउस में जवाब ही न दे सके ? ( गोर एवम व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** यह कोई सप्लीमेंटरी नहीं है।

**श्री हीरा नन्द आर्य:** क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि हैड टीचर्ज की डायरेक्ट भर्ती में भी रिजर्वेशन है ?

**श्री किशन सिंह सागवान:** स्पीकर साहब, हैड टीचर्ज की प्रोमोशन होती है डायरेक्ट नहीं भरे जाते।

**श्री परमानन्द:** स्पीकर साहब, हैड मास्टर्ज की प्रोमोशन के बारे में कहा गया कि 364 पोस्टस भरी गईं। 346 में स्पीकर साहब, सिडयूल्ड कास्टस का कोटा 34 कम है और बैकवर्ड क्लासिज के कोटे में 2 पोस्ट कम है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि हैड मास्टर्ज की प्रोमोशन का आइटेरिया क्या है और क्या उस आइटेरिया को पूरा करने वाला कैंडीडेटस कोई रह तो नहीं गए हैं ?

**श्री किशन सिंह सागवान:** स्पीकर साहब, 346 हैड मास्टर्ज में से 147 डायरेक्ट भर्ती वाले हैं और 189 प्रोमोशन में भर्ती किये गये हैं स्पीकर साहब, इसके अलावा हैडमास्टर्ज की

प्रोमो इन के आईटेरिया के बारे मे इन्होने पूछा है इसके लिए तीन आईटेरिया है। एक तो बी०ए० या बी०एस०सी० क्वालीफिके इन होनी चाहिये। दूसरे बी०टी० या बी०एड० पास होना चाहिये और तीसरे 8 साल का उस टीचिंग ऐक्सपीरिऐन्स होना अनिवार्य है जो जो इन कडी इनज को फुलफिल करते थे उनको उसी के हिसाब से अप्वायट किया गया है। जहा तक एस०सी०बी०सी० का सवाल है कोई भी ऐसा नहीं बचा जो कि यह क्वालिफिके इन फुलफिल करता हो उसे प्रामोट न किया गया हो। यदि ऐसा कोई नाम इनके पास है तो हम दे दे, हम उसको एग्जामिन करवा लेगे।

**श्री भगवान सहाय रावत:** अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी बताएगे कि आज की तारीख मे जिला फरीदाबाद मे कितने हैडमास्टर्ज, हैड टीचर्ज के पद खाली पडे है और अगर कोई पद खाली है तो उनको कब तक भर दिया जाएगा ?

**श्री किान सिंह सागवान:** अध्यक्ष महोदय, यह सवाल इससे सम्बन्धित नहीं है।

### **Industrial Growth Centres**

**\*1320 Shri Anil Kumar Vij:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up Industrial Growth Centers in the State; and

(b) if so, the names of places where the aforesaid centres are likely to be set up?

**मुख्यमंत्री (श्री हुक्म सिंह):**

(क) जी हां।

(ख) (1) जूलाना जिला जीन्द, और

(2) बावल जिला रिवाडी मे।

**श्री अनिल कुमार विज:** अध्यक्ष महोदय, मै मुख्यमंत्री महोदय से यह जानना चाहता हू कि जुलान और बावल मे जो औधोगिक विकास केन्द्र की स्थापना सरकार की और से की जा रही है, उसकी स्थापना का आधार क्या है और किस लेवल पर यह फैसला लिया गया है।

**श्री हुक्म सिंह:** अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की एक सर्वे टीम ने राज्य का सर्वे करने के बाद जुलान और बावल दो जगहो को चुना है। इस सम्बन्ध अम्बाला, रोहतक, जीन्द और रिवाडी चार जिले चुने गये है।

**श्री राम बिलास भार्मा:** अध्यक्ष महोदय, जुलाना और बवाल इन दो स्थानो को औधोगिक दृष्टि से पिछडा हुआ मानकर केन्द्र सरकार ने यहा का चुनाव किया है। इसलिये मै सरकार से यह जानना चाहता हू कि इस केन्द्रो को आगे बढाने के लिये जो जो सुविधाए दी जानी है क्या वे सभी सरकार ने उपलब्ध करवा

दी है ताकि इन केन्द्रों का विस्तार किया जा सके। और लोग इस से लाभान्वित हो सके ?

**श्री हुक्म सिंह:** स्पीकर साहब, ये सैन्टर्ज तो अभी स्थापित किये जाने हैं।

**डा० हरनाम सिंह:** अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्यमंत्री महोदय ने यह बताया कि इन औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना के लिये चार जिले अम्बाला, रोहतक, जीन्द, व रिवाड़ी चुने गये थे और इन सभी का दौरा करने के बाद केन्द्र सरकार की सर्वे टीम ने जुलाना और बावल को औद्योगिक केन्द्र खोलने के लिए उपयुक्त समझा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में फाइनल फैसला केन्द्र सरकार का होता या किसी राज्य सरकार फैसला करती है ? अगर राज्य सरकार इन केन्द्रों को खोलने का फैसला करती है तो सरकार ने किस आधार पर इन चार जिलों का चयन कर के केन्द्र सरकार के पास भेजा था ?

**श्री हुक्म सिंह:** अध्यक्ष महोदय, फैसला भारत सरकार करती है। हरियाणा सरकार को भारत सरकार फी सैन्टर के हिसाब से 10 करोड़ देगी।

**श्री दुर्गा दत्त अत्री:** अध्यक्ष महोदय, अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया कि भारत सरकार फी सैन्टर के हिसाब से 10 करोड़ देगी। तो मैं उन से यह जानना चाहता हूँ कि सारे का

सारा पैसा केन्द्र सरकार ही लगायेगी या कि राज्य सरकार भी अपनी और से कुछ पैसा लगायेगी ?

**श्री हुक्म सिंह:** स्पीकर साहब, 10 करोड सैन्ट्रल सरकार व 5 करोड रूपया हरियाणा सरकार लगायेगी ।

**श्री अनिल कुमार विज:** अध्यक्ष महोदय, मै मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हू कि जो इन्होने चार जिलो के नाम केन्द्र को भेजे इनकी प्रायरिटी किस हिसाब से बनाई थी ?

**श्री हुक्म सिंह:** स्पीकर साहब, इडस्ट्रियल ग्रोथ सैन्टर बनाने के लिए किसी जगह पर रेलवे लाइन का होना जरूरी है ने इनल हाई वे या स्टेट हाई वे का होना जरूरी है। इसके अलावा बिजली हो और पानी हो। इस तरह की बहुत सी चीजे सैन्ट्रल टीम मे देखी थी। जहां उनको ये सुविधाए दिखए दी, उन जगहो को उसने एप्रूव कर दिया।

**श्री िव प्रसाद:** अध्यक्ष महोदय, ये सारी सुविधाए अम्बाला मे है लेकिन अम्बाला को सिलैक्ट क्या नही किया गया?

**श्री हुक्म सिंह:** स्पीकर साहब, हमने अम्बाला जिला का नाम भी भेजा था लेकिन उस टीम मे जुलाना और बावल को एप्रूव किया।

**श्री मुनी लाल:** स्पीकर साहब, इस सैटर पर बावल मे कब तक काम भुरू हो जाएगा और कब तक पूरा हो जाएगा ?

श्री हुक्म सिंह: स्पीकर साहब, इसकी प्रोजैक्ट रिपोर्ट तैयार होने लग रही है। उसके बाद भारत सरकार से पैसा मिल जाएगा और काम भुरू हो जाएगा।

**Grant given to the Muniapial Committees in the State**

**1336 Harnam Singh & Sh. Parma Nand:** Will the Minister of State for Locla Goverment be pleased to state the details of amount of grnat given to each Municipal committee in the State during the yera 1990-91 togetherwith the criteria adopted therefor?

**Minister of State for Local Government (Shri Kanti Parkash Bhalla):** Statement showing the details of grant given to each Municipal Committee in the State during the year 1990-91 is liad on the Table of the House. While sanctioining the grants, financila positon of the Municipality and the requirement of funds for words etc. is kept in view.

**Statement showing the grant in aid releases to Municipal Committees during the year 1990-91**

Sr. No.	Name of Municipal Committee	Amount releases in lacs
1.	Kalka	350000
2.	Jagadhri	100000
3.	Shahabad	100000

4.	Gohana	200000
5.	Palwal	100000
6.	Narwana	100000
7.	Fatehabad	100000
8.	Tohana	100000
9.	Mandi Dabwali	100000
10.	Charkhi Dadri	350000
11.	Bahadurgarh	100000
12.	Narnaul	100000
13.	Jhajjar	100000
14.	Buria	100000
15.	Chhachharauli	150000
16.	Naraningarh	150000
17.	Sadhaura	150000
18.	Radaur	100000
19.	Ladwa	100000
20.	Pehowa	250000
21.	Pundri	100000
22.	Kalayath	100000

23.	Check	200000
24.	Indri	100000
25.	Nilokheri	100000
26.	Gharaunda	100000
27.	Taraori	100000
28.	Samalkha	100000
29.	Assandh	100000
30.	Ganaur	100000
31.	Kharkhoda	100000
32.	Ferozepur Zhirka	100000
33.	Haily Manid	100000
34.	Pataudi	100000
35.	Farukh Nagar	100000
36.	Nuh	100000
37.	Sohna	100000
38.	Taoru	100000
39.	Punhana	100000
40.	Hassanpur	100000
41.	Hodel	100000

42.	Hathin	100000
43.	Julana	150000
44.	Uchana	100000
45.	Safidon	150000

स्थिति बहुत खराब है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सोनीपत नगरपालिका की वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसको ग्रांट नहीं दी गई ?

**श्री कान्ति प्रकाश भल्ला:** स्पीकर साहब, मैं अपने सीनियर साथी को कहना चाहूंगा कि वह नगरपालिका का ऐस्टिमेट बना कर हमारे पास भेज दें अगले साल जितनी ग्रांट वे चाहेगे, दे दी जाएगी।

**श्री सूरज भान:** अध्यक्ष महोदय, जिन म्यूनिसिपल कमिटीज पर विपक्ष का कब्जा है उनके साथी सौतेली मां जैसा व्यवहार किया गया है। सरकार की ओर से उन कमिटीज को ग्रांट का एक भी पैसा नहीं दिया गया। चाहे अम्बाला भाहर की म्यूनिसिपल कमिटी है, चाहे अम्बाला कौन्ट की म्यूनिसिपल कमिटी है, चाहे यमुना नगर की म्यूनिसिपल कमिटी है, चाहे सोनीपत म्यूनिसिपल कमिटी है और चाहे रोहतक म्यूनिसिपल कमिटी है इनमे से किसी भी कमिटी को ग्रांट नहीं दी गई। केवल रोहतक म्यूनिसिपल कमिटी को 50 हजार रूपये दिये गये हैं वह भी वहा डाक्टर अम्बेदकर साहब का स्टैच्यू इस्टाल करने के लिये दिए गए

है । मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिन म्यूनििसिपल कमेटीज को ग्रांट नहीं दी गई उसका क्या कारण है ?

**श्री कान्ति प्रकाश भल्ला:** स्पीकर साहब, अम्बाला छावनी की म्यूनििसिपल कमेटी, अम्बाला भाहर की म्यूनििसिपल कमेटी, और यमुना नगर की म्यूनििसिपल कमेटी, 'ए' क्लास म्यूनििसिपल कमेटीज है। खास करके जो अम्बाला छावनी की म्यूनििसिपल कमेटी, है उसको बड़ी भारी आमदनी है। अम्बाला छावनी म्यूनििसिपल कमेटी का जो मथुरा से पेट्रोल की पाई पाइप लाइन आती है उससे भी काफी आमदनी होती है स्पीकर साहब, जो ए क्लास म्यूनििसिपल कमेटीज है उनको ग्रांट देने की कोई आवयकता नहीं है क्योंकि उनकी आमदनी बहुत है उनके पास पैसा भी काफी है।

**सेठ लक्षमन दास:** स्पीकर साहब, करनाल म्यूनििसिपल कमेटी, ए क्लास म्यूनििसिपल कमेटी, जरूर है लेकिन उसके पास अपने कर्मचारियों को तन्खवाह देने के लिए भी पैसा नहीं है। इसके अलावा करनाल भाहर की सडको का बहुत बुरा हाल है वे सारे सडके टूटी पडी है। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूँ कि करनाल म्यूनििसिपल कमेटी की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसकी ग्रांट क्यों नहीं दी गई?

**श्री कान्ति प्रकाश भल्ला:** स्पीकर साहब, हरियाणा प्रदेश की सभी म्यूनििसिपल कमेटी, के प्रैजिडेंटस का एक सैमीना

हुआ था। उस सेमीनार में मुझे उस म्यूनिसिपल कमेटी, के प्रेजिडेंट ने इस बारे में बताया था। इसलिए हमने करनाल म्यूनिसिपल कमेटी को 10 लाख रुपए ए स्पे टाल ग्रांट के रूप में इम्प्रवमेंट ट्रस्ट से मुख्यमंत्री जी के आदेशों के अनुसार दिए हैं।

लाख पचास हजार और मेहम जो पहले मुख्यमंत्री जी को क्षेत्र उसको बीस हजार रुपये दिए गए हैं अध्यक्ष महोदय, चाहे स्कूल अपग्रेड का मामला हो या ग्रांट देने की बात हो जो विभाग जिस माननीय मंत्री के पास है क्या वे केवल अपने अपने चुनाव क्षेत्र को ही हरियाणा मानते हैं। कई नगरपालिकाओं की हालत इतनी बुरी है कि जिनको एक लाख रुपया भी नहीं दिया गया है। क्या इसके पीछे कोई राजनैतिक कारण है कि अपने अपने को ही रेवाडिया दे रहे हैं ?

**श्री कान्ति प्रकाश भल्ला:** स्पीकर साहब, ग्रांट्स म्यूनिसिपल कमेटियों की वित्तीय पोजीशन को देख कर दी जाती है। जैसे अम्बाला कौन्सिल के पास चूकि फंडज की कमी नहीं है इसलिए उसको नहीं दी गई। जो कमजोर कमेटियाँ हैं उनको ग्रांट दी जाती है।

**श्री परमानन्द:** स्पीकर साहब, मंत्री जी ने बताया कि यह ग्रांट कमेटीज की फाइनेंशियल को देख कर दी जाती है। जीन्द म्यूनिसिपल कमेटी की पोजीशन इतनी बुरी है कि उन्होंने सरकार से एक करोड़ रुपए का लोन भी मांगा था लेकिन उस कमेटी को

एक पैसा भी ग्राट का नहीं दिया गया। न तो उसको स्लम क्लीयरेंस के लिए और न ही सीवरेज के लिए कोई पैसा दिया गया है। क्या इसलिए नहीं दिया कि मैं इस समय अपोजी इन में है ?

**श्री कान्ति प्रकाश भल्ला:** अध्यक्ष महोदय, अभी हमने एक करोड़ तीन लाख की ग्राट बाटी है और एफ0डी0 की तरफ से एक करोड़ दस लाख की और ग्राट मजुद हो चुकी है। इसके अलावा 21 लाख 25 हजार की ग्राट अलग अलग कमेटियों की बाटी जा चुकी है। उसकी लिस्ट कल तक हमें नहीं मिली थी इसलिये वह पटल पर नहीं रख सके।

**डा० हरनाम सिंह:** स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हरियाणा में ऐसी कितनी म्यूनिसिपल कमेटीज हैं जो अपने मुलाजिमों को तनखाह नहीं दे सकती और जिस म्यूनिसिपल कमेटी की ऐसी हालत है उसको माली इमदाद क्यों नहीं दी गई?

**श्री कान्ति प्रकाश भल्ला:** स्पीकर साहब, हरियाणा प्रदेश के अन्दर टोटल 81 म्यूनिसिपल कमेटीज हैं। पेहवा म्यूनिसिपल कमेटी ने अपनी मुलाजिमों की तनखाह के 6 लाख रूपए देने थे। उस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म आया था कि मुलाजिमों को उनकी तनखाह दी जाए। उस बात को ध्यान में

रखते हुए हमने उस म्यूनिसिपल कमेटी को ग्राट दी है जिसका जिकर स्टेटमेंट में है।

**श्री देवी लाल:** स्पीकर साहब, कुल 68 नगरपालिकाओं को अनुदान दिया गया है इनमें सोनीपत नगरपालिका का नाम नहीं है। सोनीपत नगरपालिका की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सोनीपत नगरपालिका की वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसको ग्राट नहीं दी गई ?

**श्री कान्ति प्रकाश भल्ला:** स्पीकर साहब, मैं अपने सीनियर साथी को कहना चाहूंगा कि वह नगरपालिका का ऐस्टिमेंट बना कर हमारे पास भेज दें अगले साल जितनी ग्राट वे चाहेंगे, दे दी जाएगी।

**श्री सूरज भान:** अध्यक्ष महोदय, जिन म्यूनिसिपल कमेटीज पर विपक्ष का कब्जा है उनके साथी सौतेली मां जैसा व्यवहार किया गया है। सरकार की ओर से उन कमेटीज को ग्राट का एक भी पैसा नहीं दिया गया। चाहे अम्बाला भाहर की म्यूनिसिपल कमेटी है, चाहे अम्बाला कैंट की म्यूनिसिपल कमेटी है, चाहे यमुना नगर की म्यूनिसिपल कमेटी है, चाहे सोनीपत म्यूनिसिपल कमेटी है और चाहे रोहतक म्यूनिसिपल कमेटी है इनमें से किसी भी कमेटी को ग्राट नहीं दी गई। केवल रोहतक म्यूनिसिपल कमेटी को 50 हजार रुपये दिये गये हैं वह भी वहा डाक्टर अम्बेदकर साहब का स्टैच्यू इस्टाल करने के लिये दिए गए

है । मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिन म्यूनिसिपल कमिटीज को ग्रांट नहीं दी गई उसका क्या कारण है ?

**श्री कान्ति प्रकाश भल्ला:** स्पीकर साहब, अम्बाला छावनी की म्यूनिसिपल कमिटी, अम्बाला भाहर की म्यूनिसिपल कमिटी, और यमुना नगर की म्यूनिसिपल कमिटी, 'ए' क्लास म्यूनिसिपल कमिटीज है। खास करके जो अम्बाला छावनी की म्यूनिसिपल कमिटी, है उसको बड़ी भारी आमदनी है। अम्बाला छावनी म्यूनिसिपल कमिटी का जो मथुरा से पेट्रोल की पाई पाइप लाइन आती है उससे भी काफी आमदनी होती है स्पीकर साहब, जो ए क्लास म्यूनिसिपल कमिटीज है उनको ग्रांट देने की कोई आवयकता नहीं है क्योंकि उनकी आमदनी बहुत है उनके पास पैसा भी काफी है।

**सेठ लक्ष्मण दास:** स्पीकर साहब, करनाल म्यूनिसिपल कमिटी, ए क्लास म्यूनिसिपल कमिटी, जरूर है लेकिन उसके पास अपने कर्मचारियों को तन्खवाह देने के लिए भी पैसा नहीं है। इसके अलावा करनाल भाहर की सडको का बहुत बुरा हाल है वे सारे सडके टूटी पड़ी है। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूँ कि करनाल म्यूनिसिपल कमिटी की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसकी ग्रांट क्यों नहीं दी गई?

**श्री कान्ति प्रकाश भल्ला:** स्पीकर साहब, हरियाणा प्रदेश की सभी म्यूनिसिपल कमिटी, के प्रैजिडेंटस का एक सैमीना

हुआ था। उस सेमीनार में मुझे उस म्यूनिसिपल कमेटी, के प्रेजिडेंट ने इस बारे में बताया था। इसलिए हमने करनाल म्यूनिसिपल कमेटी को 10 लाख रुपए ए स्पे टाल ग्रांट के रूप में इम्प्रवमेंट ट्रस्ट से मुख्यमंत्री जी के आदेशों के अनुसार दिए हैं।

लाख पचास हजार और मेहम जो पहले मुख्यमंत्री जी को क्षेत्र उसको बीस हजार रुपये दिए गए हैं अध्यक्ष महोदय, चाहे स्कूल अपग्रेड का मामला हो या ग्रांट देने की बात हो जो विभाग जिस माननीय मंत्री के पास है क्या वे केवल अपने अपने चुनाव क्षेत्र को ही हरियाणा मानते हैं। कई नगरपालिकाओं की हालत इतनी बुरी है कि जिनको एक लाख रुपया भी नहीं दिया गया है। क्या इसके पीछे कोई राजनैतिक कारण है कि अपने अपने को ही रेवाडिया दे रहे हैं ?

**श्री कान्ति प्रकाश भल्ला:** स्पीकर साहब, ग्रांट्स म्यूनिसिपल कमेटियों की वित्तीय पोजीशन को देख कर दी जाती है। जैसे अम्बाला कौन्सिल के पास चूकि फंडज की कमी नहीं है इसलिए उसको नहीं दी गई। जो कमजोर कमेटियाँ हैं उनको ग्रांट दी जाती है।

**श्री परमानन्द:** स्पीकर साहब, मंत्री जी ने बताया कि यह ग्रांट कमेटीज की फाइनेंशियल को देख कर दी जाती है। जीन्द म्यूनिसिपल कमेटी की पोजीशन इतनी बुरी है कि उन्होंने सरकार से एक करोड़ रुपए का लोन भी मांगा था लेकिन उस कमेटी को

एक पैसा भी ग्राट का नहीं दिया गया। न तो उसको स्लम क्लीयरेंस के लिए और न ही सीवरेज के लिए कोई पैसा दिया गया है। क्या इसलिए नहीं दिया कि मैं इस समय अपोजी गन में है ?

**श्री कान्ति प्रकाश भल्ला:** अध्यक्ष महोदय, अभी हमने एक करोड़ तीन लाख की ग्राट बाटी है और एफ0डी0 की तरफ से एक करोड़ दस लाख की और ग्राट मजुद हो चुकी है। इसके अलावा 21 लाख 25 हजार की ग्राट अलग अलग कमेटियों की बाटी जा चुकी है। उसकी लिस्ट कल तक हमें नहीं मिली थी इसलिये वह पटल प नहीं रख सके।

**डा० हरनाम सिंह:** स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हरियाणा में ऐसी कितनी म्यूनिसिपल कमेटीज हैं जो अपने मुलाजिमों को तनख्वाह नहीं दे सकती और जिस म्यूनिसिपल कमेटी की ऐसी हालत है उसको माली इमदाद क्यों नहीं दी गई?

**श्री कान्ति प्रकाश भल्ला:** स्पीकर साहब, हरियाणा प्रदेश के अन्दर टोटल 81 म्यूनिसिपल कमेटीज हैं। पेहवा म्यूनिसिपल कमेटी ने अपनी मुलाजिमों की तनख्वाह के 6 लाख रूपए देने थे। उस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म आया था कि मुलाजिमों को उनकी तनख्वाह दी जाए। उस बात को ध्यान में

रखते हुए हमने उस म्यूनिसिपल कमेटी को ग्राट दी है जिसका जिकर स्टेटमेंट मे है।

**श्री देवी लाल:** स्पीकर साहब, कुल 68 नगरपालिकाओ को अनुदान दिया गया है इनमे सोनीपत नगरपालिका का नाम नहीं है। सोनीपत नगरपालिका की वित्तीय है।

### सूची

क्रम सख्या	जिले का नाम / निर्वाचन क्षेत्र	प्राथमिक से मिडल स्कूल	मिडल से उच्च विधालय	उच्च विधालय से 10+2 पद्धति
1	2	3	4	5
1.	<b>जिला अम्बाला</b>			
	नरगल	1	2	1
	कालका	1	—	1
	नारायणगढ	1	1	1
2.	<b>जिला यमुनानगर</b>			

	रादौर	1	—	—
	जगाधरी	—	—	—
<b>3.</b>	<b>जिला भिवानी</b>			
	तो गाम	2	—	—
	बवानीखेडा	1	1	1
	बाढडा	1	1	1
	दादरी	2	3	2
	मुण्ढाल खुर्द	—	—	1
<b>4.</b>	<b>जिला हिसार</b>			
	भट्टूकला	—	5	6
	बरवाला	1	1	1
	धिराय	1	1	2
	टोहाना	—	—	—
	फतेहबाद	1	—	—
	आदमपुर	1	—	—

	रतिया	2	1	—
<b>5.</b>	<b>जिला गुडगाव</b>			
	पटौदी	1	—	1
	तावडू	1	1	—
	मूह	1	—	—
	सोहना	1	—	—
<b>6.</b>	<b>जिला फरीदाबाद</b>			
	हमनपुर	1	1	1
	पलवल	2	1	2
<b>7.</b>	<b>जिला जीन्द</b>			
	जुलाना	—	—	1
	नरवाना	1	—	1
	उचाना	1	1	1
	सफीदो	—	1	1
<b>8.</b>	<b>जिला करनाल</b>			

	इन्द्री	—	—	1
	जुण्डला	2	2	1
	घरौडा	2	2	—
<b>9.</b>	<b>जिला पानीपत</b>			
	अंसध	—	—	1
	नौलथा	2	2	2
	समालखा	1	—	1
<b>10.</b>	<b>जिला कुरुक्षेत्र</b>			
	थानेसर	1	—	1
	पेहवा	1	—	1
	भाहबाद	—	—	1
<b>11.</b>	<b>जिला कैथल</b>			
	कैथल	—	—	1
	पुण्डरी	2	1	—
	पाई	1	2	1

	कलायत	1	—	1
<b>12.</b>	<b>जिला महेन्द्रगढ</b>			
	अटेली	—	1	1
	नारनौली	2	—	—
<b>13.</b>	<b>जिला रिवाडी</b>			
	रिवाडी	—	—	1
	बावल	1	—	—
	जाटूसान	—	1	1
<b>14.</b>	<b>जिला रोहतक</b>			
	बडौदा	2	1	2
	बादली	1	2	1
	झज्जर	—	1	1
	कलोई	2	—	1
	गोहाना	2	4	3
	कलानौर	1	1	1

	बहादुरगढ	—	—	1
	साहलावास	1	2	1
	मेहम	—	—	2
<b>15.</b>	<b>जिला सोनीपत</b>			
	कैलान	1	1	1
	राई	1	—	1
	रोहट	1	2	1
<b>16.</b>	<b>जिला सिरसा</b>			
	दडबाकंला	1	3	4
	ऐलनाबाद	1	1	1
	डबवाली	—	—	1
	सिरसा	1	2	1
		<b>55</b>	<b>51</b>	<b>60</b>

**Pay Scales to Govt. aided Privat School Teachers**

**\*1339 Shri Shiv Parshad:** Will the Minister of state for Education be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to give new pay scales and other facilities to the teachers of permanently recognised private schools in the State; and

(b) if so, the time by which the above said facilities are likely to be provided?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल):

(क) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में हरियाणा राज्य के सहायता प्राप्त अराजीकाय तथा स्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों में अध्यापकों कर्मचारियों को वेतनमानों और महगाई भत्ते में 1.4.1979 से राजकीय स्कूलों में उनकी भान्ति कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमानों में समानता दी जा चुकी है। जहां तक अन्य सुविधाओं का सम्बन्ध है यह मामला सरकार के सक्रिय विचारधीन है।

(ख) भीष्म ही निर्णय लिया जाना सम्भावित है।

### **Construction of Roads**

**\*1373 Shri Balbir Singh Chaudhary & Capt. Ajay Singh Yadav:** Will the Minister for P.W.D (B&R) be pleased to state-

(a) the districtwise & Constituency wise total number of roads sanctioned for construction during the years

1985-86, 1986-87,1987-88,1988-89,1989-90,1990-91 (to date); and

(b) the number of roads out of those referred to in part (a) above have been constructed?

**लोक निर्माण मंत्री (श्री जगननाथ):** एक सूची जिलावार तथा निर्वाचन क्षेत्रवार (अनैक्सचर ए तथा बी की क्रम 1) सदन के पटल पर रखी जाती है।

अनुबन्ध "ए"

वर्ष 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90, /अप टू जनवरी – 1991 तक मन्जूर भुदा सडके तथा निर्माण की गई सडको की जिलैवार ब्यौरा:-

क्रमांक न०	जिले का नाम			वर्ष अनुसार जो सडके स्पीकृत की गई			1990-91 अप टू जनवरी	जोड	पूर्ण हुई सडको की सख्या
		1985- 86	1986- 87	1987- 88	1988- 89	1989- 90			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अम्बाला	8	78	17	6	1	1	111	83

2.	यमुनानगर	5	3	6	2	7	—	23	15
3.	करनाल	2	3	2	—	4	—	19	6
4.	पानीपत	1	1	2	3	5	1	13	4
5.	कुरुक्षेत्र	9	6	—	1	19	3	38	15
6.	कैथल	21	6	1	2	4	—	34	11
7.	रौहतक	9	2	26	27	71	10	145	30
8.	सोनीपत	6	—	3	—	2	—	11	3
9.	जीन्द	1	1	2	3	6	3	16	5
10.	फरीदाबाद	1	1	3	5	15	—	25	10
11.	गुडगाव	18	4	2	4	9	1	38	19

12.	भिवानी	33	33	6	8	6	3	89	35
13.	हिसार	61	13	7	9	7	8	105	35
14.	सिरसा	2	3	9	5	13	25	57	11
15.	रिवाडी	7	1	—	1	7	—	16	6
16.	महेन्द्रगढ	6	1	—	2	4	—	13	6
	जोड	190	156	86	86	180	55	753	294

### अनुबन्ध "बी0"

वर्ष 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90, /अप टू जनवरी - 1991 तक मन्जूर भुदा सडके तथा निर्माण की गई सडको का जिलेवार/क्षेत्रियनुसार ब्यौरा:-

क्रमांक न०	जिले का नाम			वर्ष अनुसार जो सडके स्पीकृत की गई			1990-91 अप टू जनवरी	जोड	पूर्ण हुई सडको की सख्या
		1985- 86	1986- 87	1987- 88	1988- 89	1989- 90			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ए जिला अम्बाला									
1.	कालका-1	4	2	—	5	—	—	11	4
2.	नारयणगढ-2	4	—	—	1	—	1	6	4

3.	सढौर-3	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	मुलाना-7	-	52	4	-	1	-	57	55
5.	अम्बाला कैन्ट-8	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	अम्बाला-9	-	-	1	-	-	-	1	-
7.	नगल-10	-	24	12	-	-	-	36	20
	योग	8	78	17	6	1	1	111	83
	<b>बी- जिला यमुनानगर</b>								
1.	सढौरा-3	-	2	1	-	1	-	4	3
2.	छछरौली-4	1	-	-	2	-	-	3	1

3.	जगाधरी-5	1	—	5	—	2	—	9	5
4.	यमुनानगर-6	1	1	—	—	3	—	5	4
5.	रादौर-21	1	—	—	—	1	—	2	2
	जोड	5	3	6	2	7	—	23	15
	सी-जिला करनाल								
1.	इन्द्री-11	—	1	1	8	1	—	11	3
2.	नीलोखडी-12	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	करनाल-13	—	—	—	—	1	—	1	1
4.	जुडला-14	1	2	—	—	1	—	4	—

5.	घरौडा-15	1	-	1	-	1	-	3	2
6.	अंसध-16	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड	2	3	2	8	4	-	19	6
	<b>डी० जिला</b> <b>पानीपत</b>								
1.	असध-16	1	-	-	1	2	-	4	1
2.	पानीपत--17	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	समालखा-18	-	-	-	1	2	1	4	1
4.	नौलथा-19		1	2	1	1		5	2
5.	पाई-27	-	-	-	-	-	-	-	-

	जोड	1	1	2	3	5	1	13	4
	ई जिला कुरुक्षेत्र								
1.	नीलोखेडी	—	—	—	—	—	—	—	—
2..	भाहबाद-20	2	—	—	—	—	2	4	2
3.	रादौर-21	2	—	—	1	—	—	3	2
4.	पेहवा-23	3	2	—	—	3	1	9	4
5.	पुडरी-26	—	1	—	—	—	—	1	—
	जोड	9	6	—	1	19	3	38	15
	एक जिला कैथल								

1.	गुहला-24	—	2	—	1	1	—	4	2
2.	कैथल-25	1	1	—	—	1	—	3	1
3.	पुडरी-26	16	1	1	1	—	—	19	8
4.	पाई-27		2	—	—	1	—	3	—
5.	कलायत-44	4	—	—	—	1	—	5	—
6.	राजौद-22	—	—	—	—	—	—	—	—
	जोड	21	6	1	2	4	—	34	11
	जी जिला रोहतक								
1.	हसनगढ-28	2	—	10	14	3	—	29	12

2.	किलोई-29	—	—	—	1	5	—	6	—
3.	रोहतक-30	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	मेहम-31	—	1	10		44	—	55	5
5.	कलानौर-32	2	1		1	1		5	1
6.	बेरी-33	1	—	—	2	—	—	3	1
7.	सालावास-34	—	—	—	—	2	—	2	—
8.	झज्जर-35	—	—	—	—	4	1	5	1
9.	बादली-36	—	—	3	2	3	3	11	3
10.	बहादुरगढ-37	2	—	—	1	4	1	8	3
11.	गोहाना-39	1	—	—	3	—	3	7	1

	जोड	9	2	26	27	71	10	145	30
	एफ जिला सोनीपत								
1.	केलायाना-40	4	-	-	-	1	-	5	1
2.	सोनीतप-41	1	-	-	-	-	-	2	2
3	राई-42	-	-	2	-	1	-	3	-
4	रोहट-43	1	-	-	-	-	-	1	-
5	हंसनगढ-28	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड	6	-	3	-	2	-	11	3
	आई जिला जिन्द								

1.	असंध-16	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	कलायत-44	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	नरवान-45	-	-	-	-	2	1	3	1
4.	उचाना-46	-	-	-	-	-	1	1	1
5.	राजौद-47	-	-	-	1	1	-	2	-
6.	जीन्द-48	1	1	2	-	-	-	4	-
7.	जुलाना-49	-	-	-	-	3	-	3	-
8.	सफीदो-50	-	-	-	2	-	1	3	2
	जोड	1	1	2	3	6	3	16	4
	जे० जिला								



	जोड	1	1	3	5	15	—	25	10
	के जिला गुडगावं								
1.	फिरोजपुर झिरका-57	1	—	1	—	1	—	3	3
2.	नूंह- '58	1	—	—	2	—	—	4	4
3.	तावडू-59	2	2	—	1	2	—	7	4
4.	सोहना-60	1	1	1	—	4	1	8	1
5.	गुडगाव-61	2	—	—	—	1	—	3	1
6.	पटौदी-62	10	1	—	1	1	—	13	6
	जोड	18	4	2	4	9	1	30	19

	एल जिला भिवानी								
1.	बादरा-63	—	4	1	3	—	—	8	3
2.	दादरी-64	2	—	1	—	2	—	5	—
3.	मुडाल-65	—	3	1	4	1	—	9	4
4.	भिवानी-66	4	9	—	—	—	—	13	4
5.	तौ गाम-67	7	6	1	—	1	1	16	8
6.	लौहारू-68	—	4	2	1	1	1	9	3
7.	बवानी खेडा-69	20	7	—	—	1	1	29	13
	जोड	33	33	6	8	6	3	89	35

	एम जिला हिसार								
1.	बवानी खेडा-69	19	5	—	—	—	5	29	18
2.	बरवाला-70	—	—	—	1	1	—	2	1
3.	नारनौद-71	1	—	—	6	—	—	7	2
4.	हांसी-72	4	2	2	—	1	—	9	—
5.	भटटू कला-73	1	2	1	—	—	2	8	2
6.	हिसार-74	1	1	—	—	—	—	2	—
7.	धिराय-75	2	2	—	2	1	—	7	—

8.	टोंहाना-76	3	—	4	—	1	—	8	—
9.	रतीया-77	2	—	—	—	—	—	2	—
10.	फतेहबाद-78	2	—	—	—	—	—	2	—
11.	आदमपुर-79	26	1	—	—	—	—	27	12
12.	दडवा कला-80	—	—	—	—	1	1	2	—
	जोड	61	13	7	9	7	8	105	35
	एन जिला सिरसा								
1.	दडवा कला-80	—	—	1	—	3	23	27	1

2.	ऐलनाबाद-81	—	1	5	—	3	1	10	2
3.	सिरसा-82	1	1	—	—	1	—	3	—
4.	रोडी-83	1	1	1	2	5	—	10	2
5.	डबवाली-84	—	—	2	3	1	1	7	6
	जोड	2	3	9	5	13	25	57	11
	ओ० जिला रिवाडी								
1.	बावल-85	3	—	—	—	3	—	6	3
2.	रिवाडी-86	4	—	—	1	—	—	5	2
3.	जाटूसाना-87	—	—	—	—	2	—	2	—

4.	सालहावास-34	—	1	—	—	2	—	3	1
	जोड	7	1	—	1	7	—	16	6
	<b>पी जिला महेन्द्रगढ</b>								
1.	जाटूसाना-87	2	—	—	—	—	—	2	—
2.	महेन्द्रगढ-88	1	—	—	1	2	—	4	1
3.	अटेली-89	1	—	—	1	2	—	4	1
4.	नारनौल-90	2	1	—	1	2	—	6	5
	जोड	6	1	—	2	4	—	13	6
	<b>कुल जोड</b>	190	156	86	180	55	753	55	294

### **Election to Block Samitis**

**\*1349 Dr. Raghvir Singh:** Will the Minister for Development and Pachayat be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to hold election of Block Samitis of Pachayats: and

(b) if so, the time by which the election are likely to be held?

**विकास मंत्री (श्री सुभाश चन्द कटियान):**

(क) जी हां ।

(ख) मामला राज्य सरकार के विचारधीन है ।

### **Poly Clinic for Animals**

**\*1358 Shri Mani Ram:** Will the Minister for State for Animal Husbandry be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Poly-Clinic for animal in Village Chautala, Tehsil Dabwali District Sirsa; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized?

**पुपालन राज्य मंत्री (श्री कुलबीर सिंह मलिक):**

(क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित पोलीक्लिनिक् धनराशि की उपलब्धि की सार्त वर्ष 1991-92 के दौरान पूरा होने की सभावना है।

### विभिन्न विशयो का उठाया जाना

**श्री सूरज भान:** अध्यक्ष महोदय, आज अखबारो मे छपा है कि हरियाणा सरकार चन्द्रास्वामी को प्रोटैक्शन देने के लिए सिपाही देती है। मैं जानना चाहता हू कि सरकार किस कानून के तहत उनको यह प्रोटैक्शन दे रही है। (गोर एवम विघ्न) हरियाणा सरकार जब अपने लोगो को तो प्रोटैक्शन नहीं द पा रही तो फिर बाहर के लोगो को प्रोटैक्शन कैसे दिया जा रहा है? हमारे सीआईडी के दो सिपाही पहले ही पकडे गए है जिससे सरकार बदनाम हुई है। (गोर एवम व्यवधान) इस बारे मे सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

**श्री अध्यक्ष:** चौधरी साहब मि० रावत की इस बारे मे एक काल अटैन्शन मोशन आई है। That is under consideration.

**श्री राम बिलास भार्मा:** स्पीकर साहब, दिल्ली मे सीआईसी वाली जो घटना हुई यह बहुत ही अपनाम जनक थी। इसके बाद जो कहानी इन्होने जवबा के तौर पर घडी कि थे तो किसी भाादी के सिलसिले मे चौधरी सुलतान सिंह से मिलने गए थे। वह ठीक नहीं थी। (गोर एवम व्यवधान) उनके बारे मे अखबारो मे भी आया और उनकी परिवार वालो की तरफ से भी

आया है कि उनकी जान को खतरा है क्योंकि पुलिस ने उन दोनों को गायब कर दिया है। ( गोर)

**गृहमंत्री (प्रो० सम्पत सिंह):** स्पीकर साहब, हमने कोई कहानी नहीं घड़ी बल्कि जो सच्चाई थी वह बताई गई है। ( गोर एवम व्यवधान) हमने सौ फिसदी सही बात कही है।

**श्री अध्यक्ष:** भार्मा जी, यह कहानी कहने की बजाये अच्छा होता यदि आप यह पूछते कि मेरी काल अटैन् इन मो इन का क्या हुआ।

**श्री राम बिलास भार्मा:** अध्यक्ष महोदय, अब बता दीजिए कि मेरी उस काल अटैन् इन मो इन का क्या हुआ?

**Mr. Speaker:** Sharma Ji, I have received that today and the same is under consideration.

**श्री राम बिलास भार्मा:** स्पीकर साहब, उनको गायब कर दिया है। ( गोर एवम व्यवधान) उनकी जान को खतरा है।

**Mr. Speaker:** Sharma Ji, as I have said, I have received your calling attention motion and that is under consideration.

**श्री राम बिलास भार्मा:** स्पीकर साहब, मैंने कल भी आपसे प्रार्थना की थी और आज फिर प्रार्थना करता हू कि एच०सी०एम० के पेपर्स लेते समय जो धाधलिया हुई है। उस बारे में मैंने एक काल अटैन् इन मो इन दी थी उसका क्या हुआ ?

**Mr. Speaker:** I have sent it to the Government for comments.

**श्री हीरा नन्द आर्य:** अध्यक्ष महोदय, सारे दे 1 मे यह बहुत ही चर्चित विषय रहा है हरियाणा प्रदेश 1 की सी0आई0डी0 के दो आदमी दिल्ली मे पकडे गए है।( गोर एवम व्यवधान) उनकी पत्नी की तरफ से रिक्वायत आई है कि उनको गायब कर दिया है और अब उनकी जान को खतरा हो सकता है। मेरी इस काल अटैन्शन मोशन का क्या हुआ है ?

**Mr. Speaker:** Arya Ji, that is under consideration.

**श्री रतन लाल कटारिया:** स्पीकर साहब, यमुना नदी के तट से पुलिस की मिली भगत से हजारो गाय यू0पी0 मे भेजी जा रही है मैने इस बारे मे एक कालिग अटैन्शन मोशन दिया हुआ था उसका क्या बना?

**Mr. Speaker:** Kataria Ji, I have sent it to the Government for comments.

**कामरेड हरपाल सिंह:** स्पीकर साहब, मैने भी भटठो के मजदूरो के बारे मे एक काल अटैन्शन मोशन दी थी क्योकि उन मजदूरो के साथ बहुत अधिक ज्यादती हो रही है। मेरी उस काल अटैन्शन मोशन का क्या बना।

**Mr. Speaker:** Comrade Sahib, I have rejected it.

**श्री परमा नन्द:** अध्यक्ष महोदय, ट्रासपोर्ट डिपार्टमेंट में चौरी छिपे ऐडहाक बेसिज पर और 89 डेज पर जो एम्पलाईज रखे जा रहे हैं उनके बारे में मैंने एक काल अटै इन मो इन दी थी, उसका क्या बना?

**श्री अध्यक्ष:** मेरे रिकार्ड के मुताबिक आपकी तरफ से इस बारे में कोई कालिग अटै इन मो इन नहीं आई है।  
However, you please enquire form me about it afterwards.

**श्री उदय भान:** स्पीकर साहब, फरीदाबाद में तहसीलदार सेल ने रिहैबिलिटे इन के प्लान लोगो से झूठे एफिडेविट लेकिन अलाट किये हैं। इस बारे में मैंने एक काल अटै इन मो इन दी है उसका क्या बना?

**Mr. Speaker:** Chaudhry Sahib that is under consideration.

**श्री सूरज भान:** स्पीकर साहब, मैंने बहन कमला वर्मा की इल लीगल डिटे इन के बारे में एक प्रिविलेज मो इन दी थी उसका क्या बना?

**Mr. Speaker:** Chaudhry Sahib, I have called the comment of the Government on it within 24 hours.

**वर्ष 1991-92 के बजट पर अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान**

**श्री अध्यक्ष:** आनरेबल मैम्बर्ज, अब वर्ष 1991-92 के बजट की डिमांडज फार ग्रान्टस पर डिस्कान होगी।

पहली प्रैक्टिस के मुताबिक और हाउस का टाईम सेव करने के लिए आर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमांडज (स0 1 से 25) एक साथी पढी गई तथा मूव की गई समझी जाएगी। आनरेबल मैम्बर्ज किसी भी डिमांड पर डिस्कान कर सकते हैं लेकिन बोलने से पहले वे डिमांड का नम्बर बता दे जिस पर बोलना चाहते हो। डिस्कान के बाद डिमांडज हाउस की वोट के लिए पुट की जाएगी। साथ ही मैं रिक्वैस्ट करूंगा कि हर मैम्बर 10 मिनट से ज्यादा टाईम न ले ताकि ज्यादा से ज्यादा मैम्बर साहेबान को बोलने का मौका मिल सके।

That a sum not exceeding Rs. 17447000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of chargs under Demand No. I Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 460008000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of chargs under Demand No. 2 General Administration.

That a sum not exceeding Rs. 124707000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of chargs under Demand No. 3 Home.

That a sum not exceeding Rs. 282180000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 4 Revenue.

That a sum not exceeding Rs. 108467000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 5 Excise & Taxation.

That a sum not exceeding Rs. 792625000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 6 Finance.

That a sum not exceeding Rs. 11991694000 for revenue expenditure and Rs. 3665000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 7 other Administrative Services.

That a sum not exceeding Rs. 570531000 for revenue expenditure and Rs. 534367000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 8 Buildings and Roads.

That a sum not exceeding Rs. 3557614000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 9 Education.

That a sum not exceeding Rs. 1654161000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 10 Medical and Public Health.

That a sum not exceeding Rs. 80697000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 11 Urban Development.

That a sum not exceeding Rs. 212064000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 12 Laboru and Employment.

That a sum not exceeding Rs. 1800102000 for revenue expenditure and Rs. 18264000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 13 Social Welfare and Rahabiliation.

That a sum not exceeding Rs. 48254000 for revenue expenditure and Rs. 1970080000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 14 Focd and Supplies.

That a sum not exceeding Rs. 2313501000 for revenue expenditure and Rs. 848394000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that

will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 15 Irrigation.

That a sum not exceeding Rs. 229535000 for revenue expenditure and Rs. 64216000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 16 Industries.

That a sum not exceeding Rs. 849720000 for revenue expenditure and Rs. 6300000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 17 Agriculture.

That a sum not exceeding Rs. 300599000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 18 Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs. 31766000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 19 Fisheries.

That a sum not exceeding Rs. 452406000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 20 Forest.

That a sum not exceeding Rs. 737814000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in

respect of chargs under Demand No. 21 Community Development.

That a sum not exeeding Rs. 352767000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of chargs under Demand No. 22 Cooperation.

That a sum not exeeding Rs. 184892000 for revenue expenditure and Rs. 255400000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of chargs under Demand No. 23 Trasport.

**वर्ष 1991 के बजट पर अनुदानो की मागो पर चर्चा  
तथ मतदान**

That a sum not exeeding Rs. 18252000 for revenue expenditure and Rs. 20500000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of chargs under Demand No. 24 Tourism.

That a sum not exeeding Rs. 2476256000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of chargs under Demand No. 25 Loans and Advances by State Government.

**श्री जय नारायण खुण्डिया (कलानौर अनुसूचित जाति):**  
स्पीकर साहब, मै डिमाड नम्बर 8,3,20,23 तथा 9 पर अपने विचार

व्यक्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं कृषि की डिमांड पर बोलना चाहूँगा। ( गौर एवम विघ्न)

**श्री वीरेन्द्र सिंह:** स्पीकर साहब, वैसे तो मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ क्योंकि टाईम समाप्त हो गया है और मुझे इन्ट्रूट से मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि श्री दुर्गा दत्त अत्री जी ने जो प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया है उसका क्या बना?

**Mr. Speaker:** That matter and S.P's conduct has already been discussed and raised here for a number of times.

**Shri Verender Singh:** Sir, It is fresh privilege motion.

**Mr. Speaker:** I will discuss it with you.

**श्री जय नारायण खुण्डिया:** स्पीकर साहब, कृषि के लिए 84 करोड़ 97 लाख 20 हजार रुपये की राशि रखी गई है। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि वैसे तो सरकार ने कृषि के बारे में बहुत ही बढ़ा-चढ़ाकर बातें कही हैं। यह कहा गया है कि हमने गन्ने का रेट बहुत ज्यादा दिया है। यह बात ठीक है कि गन्ने का रेट बहुत ज्यादा दिया है। यह बात ठीक है कि गन्ने का रेट हरियाणा प्रदेश में बढ़ा है लेकिन फिर भी हरियाणा के किसानों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया गया है। लोहे और सीमेंट के रेट कितने बढ़े हैं और गेहूँ का रेट कितना बढ़ा है इससे ही किसान के साथ हुए भेदभाव का पता चल जाएगा। गेहूँ का भाव किसान को 215 रुपये क्विंटल दिया गया लेकिन वह 450

या 500 रूपये प्रति क्विंटल पर बिक रहा है। यह रेट पिछले दिनों ही बढ़े हैं। जब किसान के खेत में फसल होती है तो रेट बहुत ही कम तय किया जाता है। लेकिन जब फसल किसान के घर में चली जाती है तो उसका रेट बढ़ता ही चल जाता है। स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह सरकार किसानों की हमदर्द सरकार नहीं है। बल्कि किसानों के हित की बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है और किसान के साथ भेदभाव किया जा रहा है। आज सीमेंट और लोहे के रेट कहीं से कहीं पहुँच गए हैं। (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष:** आप कौन सी डिमाण्ड पर बोल रहे हैं ?

**श्री जय नारायण खुण्डिया:** स्पीकर साहब, मैं कृषि की डिमाण्ड पर बोल रहा हूँ। एस0वाई0एल0 का मामला भी वही का वही अटका हुआ है। इसी मामले पर चौधरी देवी लाल और स्वर्गीय डा0 मंगल सेन ने मिलकर युद्ध भुरू किया था। एस0वाई0एल0 के पानी का मामला हरियाण प्रदे 1 के लिए जीवन मरण का प्र 1ान है। इस मामले का हल करने के लिए अभी तक सरकार ने कोई गम्भीर प्रयत्न नहीं किए हैं। चौधरी देवी लाल जी ने इलैक् 1ान के वक्त बार बार कहा था कि अगर चुनाव में हमारी सरकार बनी तो एस0वाई0एल का पानी प्रदे 1 में लाया जाएगा। नहर का काम आज चल नहीं रहा। मैं सरकार से यह पूछना चाहूँगा कि क्या सरकार यह पानी हवाई जहाज से प्रदे 1 में लाएगी? जमीन ऐक्वायर कर रखी है लेकिन काम ठप्प पड़ा है। इस प्रकार से किसानों के साथ बड़ा भद्दा मजाक किया जा रहा

है। स्पीकर साहब, किसानों के साथ हरिजनों और पिछड़े वर्गों के साथ भी भेदभाव किया जा रहा है। भीम राव अम्बेदकर जी ने भारतीय संविधान में 20 प्रतिशत नौकरियाँ एस0सीज0 के लिए रिजर्व करने का प्रावधान किया था। यह 20 प्रतिशत आरक्षण हरिजनों की हालत को सुधारने और समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए किया था। कांग्रेस की सरकार ने 40 वर्षों तक इस देश पर शासन किया लेकिन आज भी आरक्षण के मामले पर हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। एक तरह से यह उनके साथ भेदभाव मजाक है। इसी तरह से तीन साढ़े तीन साल से यह सरकार भी उनके साथ भेदभाव कर रही है। मैंने असेम्बली में इस बारे में क्वेश्चन भी किया था कि पुलिस की भर्तियों के अन्दर कितने एस0पी0, डी0एस0पी0, इन्सपैक्टर, सब-इन्सपैक्टर, हवलदार, हेड कान्स्टेबल और कान्स्टेबल भर्तियाँ किए गए हैं और उनमें कितने हरिजन और पिछड़े वर्ग के हैं? जवाब में बताया गया कि टोटल जो भर्तियाँ हुई हैं, उसके अन्दर पुलिस में डी0एस0 पीज में 12 की कमी है निरीक्षकों में 221 की कमी है, उप निरीक्षक में 62 की कमी है, और सिपाहियों में 421 की कमी है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि बार बार हाउस के अन्दर आवाहन दिया जाता है कि जो बैकलॉग रिजर्वेशन के अन्दर है, उसको पूरा करेंगे लेकिन यह सरकार इस बारे में कुछ भी नहीं कर रही है। यह बैकलॉग हर साल बढ़ता जा रहा है। इसको कम नहीं किया जा रहा है। मेरी अपनी सरकार से यह निवेदन है कि आपको इसके लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट करनी चाहिये। पुलिस के

अन्दर या दूसरे जिन भी महकमो के अन्दर इस तरह की हालत है, वहा पर इस कमी को पूरा किया जाये। मै ि 1 डयूल्ड कास्टस एड ि 1 डयूल्ड ट्राइब्ज कमेटी का मम्बर हू। इस नाते मुझे पूरा पता है कि आज भी डिपार्टमेंटस के अन्दर क्लास 1 के अन्दर एक डेढ परसैट, क्लास 2 के अन्दर 2 परसैट और क्लास 3 के अन्दर केवल 10 या 11 परसैट से ज्यादा इनकी भर्ती नहीं है। यह बात ठीक है कि क्लास फोर में रिजर्वे िन पूरी है और वह भी इसलिये क्याकि बाल्मीकि इन पोस्टस पर आ जाते है। सफाई वगैरहा करने के लिये वे आ जाते है। इसके बगैर काम नहीं चल सकता इसलिए क्लास फौर में 20 से 25 परसैट तक है। क्लास फोर में इनकी रिजर्वे िन पूरी है। मै यह कहना चाहता हू कि हमारे महकमो के अन्दर जो बैकलौग है, उस के बारे में बार सैट्रल गवर्नमेंट से चिटठी आयी हुई है कि इस बैकलौग को पूरा किया जाये। पता नहीं किस तरह से यह सरकार काम करती है। यह बैकलौग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। मै सरकार से पुरजोर अपील करता हू कि इस बैकलौग को स्पै िल रिकूटमेंट करके पूरा किया जाये। इसके साथ साथ इन डिमांडज में होम डिपार्टमेंट के लिये भी पैसा मांगा गया है। मै यह कहना चाहता हू कि पिछले दो साल के अन्दर हरियाणा प्रदेश के अन्दर जो घटनाएँ घटी है, उससे हरियाणा प्रदेश का नाम सारे हिन्दुस्तान के अन्दर उजागर हुआ है। जिस तरह से कोसलीह के अन्दर बहुत बडा कांड हुआ। गोहाना के अन्दर कांड हुआ। मेहम के अन्दर भैसी का कांड हुआ। इतना ही नहीं, जैसे सूरज भान जी की जीप जलायी गयी, उनके

मकान को नष्ट किया गया, बनारसी दास गुप्ता पर हमला हुआ, दुर्गा दत्त अत्री अब भी बार बार यह कह रहे हैं कि जींद का एस0पी0 हजारी लाल उनको आज भी चुनौती दे रहा है। (व्यवधान एवम भाोर) उन्होंने यह कहा है कि पडित जी, अब विपक्ष के अन्दर जितने भी आप पडित बैठे हुए हैं, आप सावधान रहना। पजाब से उग्रवादी आये हैं और आपकी जान खतरे में है। हमारे लायक दोस्त श्री सम्पत सिंह जी मेरी इस बात पर हंस रहे हैं। हमने इस हाउस में बार बार उस की धमी का जिकर किया है। मेरा कहना यह है कि जब बार बार हाउस के अन्दर उस एस0पी0 का नाम आ रहा है तब आप उसके खिलाफ एकान क्यो नहीं लेते।

**एक आवाज:** यह किस मांग पर बोल रहे हैं।

**श्री जय नारायण खुण्डिया:** मैं होम डिपार्टमेंट की मांग सख्या 3 पर बोल रहा हूँ। इसमें वह मांग शामिल है। यह मांग सख्या 3 की बात है। इसके साथ ही मैं परिवहन के मुताल्लिक यह कहना चाहता हूँ कि उसकी इतनी बुरी हालत है कि अगर आप चडीगढ से रोहतक या नारनौल को जायेगा तो रास्ते में कम से कम 10 बसे खराब मिलेगी क्योकि उनके स्पेयर पार्ट्स ठीक ढग से लगाते नहीं हैं। यह नहीं बसो के भी 10 तक नहीं होते और उनकी सफाई तक नहीं होती। इतना ही नहीं परिवहन के अन्दर फर्जी टिकटें भी चलती हैं यहा पर फर्जी टिकटें भी छापी जाती हैं और इनके अपने चहेते ही उन फर्जी टिकटों को बेचते हैं। स्पीकर साहब, मण्डल कमिशन की रिपोर्ट के सम्बन्ध में जो झगडे हुए

उनमे कम से कम 150 बसिज राजनीतिक्षज्ञो के इ तारे पर फूकी गई और बहुत अधिक नुकसान किया गया। एस0पी0 और डी0एस0पी0 पर हमले हुए। इन झगडो के दौरान जितने भी एस0पी0 और बी0सी0 के आई ए0एस0 और एच0सी0एस0 औफिसर्ज थे उनके साथ बुरा व्यवहान किया गया। मि0 बिडसाल हांसी के एस0डी0एम0 थे उन पर हमला किया गया। औ0पी0 इन्दौरा एस0डी0एम0 फतेहबाद थे उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया और आर0सी0 चौधरी डी0सी0 सोनीपत के साथ भी इसी तरह का दुर्व्यवाह किया गया। (इस समय श्री उपाध्यक्ष महोदय, पदासीन हुए।) उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह का वातावरण इस प्रदे ा के अन्दर फैला हुआ था। डिप्टी स्पीकर महोदय, भिवानी के अन्दर जो घटनाए हुई उनके बारे मे आप अच्छी तरह से जानते है क्याकि आप वहा के रहने वाले है। इस साढे तीन साल के माहौल मे लोग अपने आपको सुरक्षित नही समझते। आज हर जगह प्लाटो पर नायायज कब्जा किया जा रहा है। आम आदमी अपने आपको सुरक्षित महसूस नही कर रहा है। बहन बेटियो की इज्जत पर हमला हो रहा है। डिप्टी स्पीकर साहब, तीन साल के दौरान इतनी चौरिया हुई है जिसका कोई हिसाब नही है। मैने असैम्बली के अन्दर इस बारे मे क्वै चन भी किया था और वे आकडे मेरे पास है। 1987 मे कम से कम दो सौ, 1988 मे तीन सौ, 1989 मे 400 और 1990 मे 500 इस तरह से चोरिया बढती गई है। इस तरह से स्कूटर्ज, कारो, ट्रक्स की चोरियां हुई है। डिप्टी स्पीकर साहब, ये लोग हमसे पैसा मन्जूर कराना चाहते है लेकिन मै इनसे पूछना

चाहता हू कि इन्होंने क्या काम किया? क्या यह सरकार इन फौजों के लिए पैसा मंजूर कराना चाहती है जिनसे लोग परे तान है और लोगों को तंग करते हैं। आज हर थाने में लोगों से जबरदस्ती पैसा लिया जा रहा है। अगर एस.एच.ओ. से पूछते हैं कि तुम पैसा क्यों लेते हो तो वे कहते हैं कि ऊपर भेजने के लिए पैसा चाहिए। ( गोर एवम व्यवधान)

**श्री मनी राम:** डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इनसे पूछना चाहता हू कि जब ये ज्योति लेकर गए थे तो इन्होंने जो अरबों रूपया इकट्ठा किया था वह कहा से आया था ?( गोर एवम व्यवधान)

**श्री जय नारायण खुण्डिया:** डिप्टी स्पीकर साहब, मनी राम को बड़ी तकलीफ हो रही है आने वाले समय में सारे हिन्दुस्तान के अन्दर ज्योति जागेगी और भारत वर्ष के अन्दर भारतीय जनता पार्टी का राज होगा। ( गोर एवम व्यवधान)

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हू। ( गोर एवम व्यवधान) पचास हजार रूपया लेकर एकसीयन तरे पास आया था। ( गोर एवम व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, शिक्षा के बारे में मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हू। शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है जिसकी कोई हद नहीं है। आज किसी भी स्कूल के अन्दर जाकर देख लीजिए न तो वहाँ बैठने के लिए स्थान है और बिल्डिंग की हालत इतनी खराब है कि

वह सारी टपकती है। बच्चों के बैठने के लिए कोई टाट भी नहीं है और अध्यापकों की इतनी कमी है कि आप उसका अन्दाजा नहीं लगा सकते। डिप्टी स्पीकर साहब, शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिये बार बार इस हाउस में कहा गया। शिक्षा का स्तर तो तभी ऊंचा हो सकता है जब राज्य के अन्दर हर एक स्कूल में पूरे अध्यापक हों। मैंने अपने हल्के के बारे में भी कहा कि वहाँ पर कई स्कूलों के अन्दर टीचर्स का अभाव है। सो गल साइंस के टीचर्स नहीं हैं, मैथ के टीचर्स नहीं हैं। आप ही बताइये डिप्टी स्पीकर साहब, जिन स्कूलों में टीचर्स का अभाव होगा वहाँ कैसे बच्चे सुचारू रूप से अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे? कैसे उनका शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सकेगा? यहाँ पर यू ही हवाई मुल बताये जा रहे हैं कि हरियाण प्रदेश में शिक्षा का स्तर बडर ही ऊंचा जा रहा है। मैं आपको स्कूलों की हालत का क्या बताऊँ? कहीं टाट नहीं है, कहीं बिल्डिंग नहीं है तो कहीं पर टीचर्स नहीं हैं। कई जगहों पर स्कूलों की बिल्डिंगों की ऐसी दुर्दशा है कि उनको अनसेफ डिक्लेयर किया जा चुका है लेकिन सरकार को उस और कोई ध्यान नहीं है।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसी तरह से हस्पतालों की भी बडी ही दुर्दशा है। पब्लिक हेल्थ के लिए सरकार ने 1 करोड 65 लाख 41 हजार रुपये मागे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बार बार कहने के बावजूद भी सरकार इस और कोई ध्यान नहीं दे रही है। मेरी मांग भी थी कि मेरे इलाके में एक हस्पताल बनाया जाए लेकिन

सरकार ने अनसुनी कर दी। जो हस्पताल सरकार के चल रहे है उनकी हालत ऐसी है कि कही दवाई नाम की कोई चीज नहीं है मै आपका रोहतक की बात बताना हू कि वहा पिछले चार साल से सिविल हस्पताल रोहतक के अन्दर एक रेडियो ग्राफर काम कर रहा है। इस बारे मे मै कई बार हाउस मे भी कह चुका हू कि जहा भी वह आदमी आता है, वहा की म मीने जानबुझ कर खराब कर देता है। पहले उसको बहादुरगढ बदला गया, वहा की म मीने खराब की और उसके बाद उसे जीन्द ट्रासफर कर दिया गया तो वहा की म मीनो का भी उस आदमी ने भट्ठा बिठा दिया। वह आदमी पोलिटिकल आदमियो के इ तारे पर चल रहा है और पिछले चार सालो से वह आदमी रोहतक सिविल के अन्दर ही बिराजमान है। उनको वहा से हिलाने की किसी की हिम्मत नहीं पडती। वह हर जगह की म मीने इस लिये खराब कर देता है ताकि लोग बाहर प्राईवेट तौर पर जाकर अपने ऐक्सरे करवाए। उस आदमी ने प्राईवेट दुकान वालो से अपनी साठ गाठ कर रखी है। पिछले दिनो हम रोहतक हस्पताल के अन्दर गये तो पता चला कि वहा की ऐक्सरे म मीन उस आदमी ने 15 दिनो के अन्दर खराब कर दी है जिससे लोगो को बडी भारी परे तानी हो रही है। रोहतक हस्पताल की म मीन खराब होने के कारण लोगो को झञ्जर वगैरहा जाना पडता है या फिर प्राईवेट दुकानो से अपने इलाज के लिये ऐक्सरे करवाने पडते है जो कि उनको बहुत ही महगा पडता है। यह सब कुछ उसी एक आदमी की वजह से हो रहा है जो कि रोहतक मे ही बैठा है। प्राईवेट दुकानो के साथ

उस आदमी ने अपना पचास प्रतिशत भोयर रखा हुआ है और वह सरकार के साथ साथ लोगों को भी लुट रहा है। इस सारे मामले की जांच होनी चाहिये और उस तुरन्त ही वहा से बदला जाना चाहिये।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं नगरपालिकाओं की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिनके लिये इस सरकार ने 8 करोड़ 6 लाख 97 हजार रुपये की राशि की मांग की है। नगरपालिकाओं की इतनी बुरी हालत है कि क्या कहूँ। खासतौर पर रोहतक भाहर की बहुत बुरी हालत है। आपने आते जाते देखा भी होगा कि सड़कों की हालत खस्ता है और बड़े बड़े खड्डे हैं जिससे लोगों को आगे जाने में बड़ी दिक्कत होती है लेकिन इस सरकार का उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि वहाँ विपक्ष में प्रधान सुन्दर लाल सेठी हैं इसलिए वहाँ ग्रांट भी एक नये पैसे की नहीं दी गई। उपाध्यक्ष महोदय, रोहतक के साथ इतना भारी भेद भाव किया जा रहा है। जब सम्पत सिंह जैसे राजनीतिक लोग और बड़े बड़े नेता चुनाव के दौरे के समय रोहतक में आते हैं तो रोहतक भाहर की मिट्टी को उठा कर तिलक लगाते हैं लेकिन अब इन्होंने वहाँ पर खून बहाना शुरू कर दिया है। डिप्टी स्पीकर साहब, चुनाव के दिनों में तो रोहतक भाहर इनकी भारीफ नजर आता है लेकिन जब वहाँ से जीत जाते हैं तो उसके बाद उस तरफ इनका ध्यान ही नहीं जाता। (विधन) इम्प्रवैमेंट ट्रस्ट भी अभी बहाल किए गए हैं। उस ट्रस्ट के 5-6

मैबर है। उस ट्रस्ट ने 17 दुकानों बनाई जिनमें से दो दो दुकानों तो मैम्बरों ने बाट ली और बाकी की चेयरमैन ने रख ली। इन दुकानों को 60-60 हजार रूपए में उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम अलौट करवा दिया लेकिन ठीक नहीं की। वह एक दुकान आज चार लाख रूपए की है। जिन लोगों को ये दुकानें दी गई थी उन्होंने उनको चार चार लाख रूपए में डिस्पोज आफ कर दिया। रोहतक की गलियों और सड़कों की भी बहुत बुरी हालत है। अब की बार हमारे लायक दोस्त सम्पत सिंह जी रोहतक में आएंगे तो इनको मजा चखाएंगे।

**गृहमंत्री (प्रो० सम्पत सिंह):** डिप्टी स्पीकर साहब, रोहतक तो मैं जाता रहता हूँ। वहाँ पर बाकायदा काम हो रहे हैं लेकिन ये भ्राम के टाइम रोहतक में निकलते हैं उस वक्त इनको...  
.....नहीं होंता। इसलिए इनको सब जगह खड्डे ही खड्डे नजर आते हैं।

**श्री जय नारायण खुण्डिया:** डिप्टी स्पीकर साहब, ये दिन में वहाँ मेरे साथ चले इनकी धरणा न गिर जाए तो मुझे बता दे।

**प्रो० सम्पत सिंह:** .....

**श्री उपाध्यक्ष:** हो । और भाराब वाली बात रिकार्ड न की जाए।

**कामरेड हरपाल सिंह:** डिप्टी स्पीकर साहब, दूसरे लोगो को भी टाइम मिलना चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष:** अभी आप बैठे। खुण्डिया जी, अब आप वाईड अप करे क्योकि आपने काफी टाइम ले लिया है। इसीलिए पहले की कहा गया था कि कृपया दस दस मिनट के लिए ही बोले।

**श्री जय नारायण खुण्डिया:** डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी देवी लाल जी क सरकार ने जो बुढापा पैन्शन की स्कीम चलाई थी यह बहुत ही सराहनीय काम है जिन लोगो को पहले 60-60 रूपए मिलते थे, जिस दिन से यह सरकार आई है उनको उस दिन से वह 60 रूपए भी मिलने बन्द हो गए है। तीन चार केस तो मेरी नालेज मे है, मेरे पास उनकी चिट्ठियां है। उनको पिछले चार साल से एक पैसा नही मिला है। वे 85-85 साल के बूढे है, मेरे पास उनका पीछे का रिकार्ड है पीछे वे मानी आर्डर लेते रहे थे। लेकिन जब से यह सरकार आई है।

**11.00 बजे।**

उनकी पैन्शन बंद हो गई है मेरे खुद के गांव गरनावठी मे भी ऐसे 5-6 केस है जिनको पहले पैन्शन मिलती थी लेकिन अब बंद हो गई है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस तरह की अनियमितताओ का सरकार सुधार करें। डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात मै फूड एंड सप्लायज विभाग के बारे मे कहना

चाहूंगा कि इस विभाग के डी०एफ०सी० के कारण रोहतक भाहर मे भोर मचा हुआ है। पिछले दिनो रोहतक भाहर मे गरीब लोगो को 4-5 रूपए किलो के हिसाब से भी आटा नही मिला इसमे कोई भाक नही कि वह उस डी०सी० और एस०पी० साहब से मिला। वहा के डी०सी० और एस०पी० साहब बडे सज्जन आदमी है। उन्होने उस समय हमे कहा था कि जो अच्छी बाते होगी वह हम जरूर करेगे। डिप्टी स्पीकर साहब, उन्होने कई जगहो पर हमारे कहने मे छापा मारा। वहा पर जितने भी डिपो होल्डर्ज है उनके साथ भी हमने बात की। डिपो होल्डर्ज कहते है कि हम क्या करे? हमसे 15-15 रूपए बोरी के हिसाब से फूड एंड सप्लाइज विभाग के आफिसर्ज लेते है। हम उन बोरियो को आगे बेच देते है। इसी तरह से चीनी का हाल है। सरकार ने जितनी भी गेहू गावो के गरीब लोगो के लिए भेजी थी वह गावो मे न जा कर भाहरो मे जा करके मिलीभगत से बेची गई। मैने इस बारे मे फूड एंड सप्लाइज विभाग के मंत्री श्री नर सिंह दाडा से बात भी कि थी जब हम कैटीन मे चाय पी रहे थे। मैने इनसे कहा था कि इसका कोई न कोई समाधान जरूर किया जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, भारद्वाज साहब सदन से उठ कर बाहर जा रहे है मैने उनसे भी रेडियो ग्राफर्ज के बारे मे बात की थी। अब मै हल्के की कुछ बातो की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। मेरे हल्के कलानौर का बहुत बुरा हाल है। ज्यादातर मंत्री रोहतक जिले के होते हुए रोहतक जिले के बारे मे नही बोल सकते। क्यो नही बोल सकते क्योकि उनको कुंसी मिली हुई है। रोहतक जिले मे सडको और

स्कूलो का इतना बुरा हाल है जिसका कोई हिसाब नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे हल्के कलानौर में मडौदी जाटाना और मडौदी रागडान दो गाव है। उन गावो में मुख्यमंत्री जी भी कई बार गए हैं उनके साथ मैं भी था। वहा पर जो रोड बननी है उसकी सैव तन हो चुकी है लेकिन अभी तक उसका काम भुरु नहीं किया गया है। वहा पर डेढ डेढ फुट पानी खडा रहता है। दोनो साईड में गांव है और उसके बीच से रोड जाती है। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि उस रोड का काम जल्दी से जल्दी भुरु करवाया जाए ताकि लोगो को कोई दिक्कत न हो। इसी तरह से मेरे हल्के में एक सडक कलानौर से सैम्पल होती हुई कलगा तक बननी है। वह सडक मार्किट कमेटी से बनानी है। लेकिन उस सडक का काम भी खटाई में पडा हुआ है। उसको बनाने के बारे कोई जिकर नहीं है। मैं सरकार से प्रार्थना करुगा कि सरकार उस और ध्यान दे कर उस सडके को बनाने का काम भुरु कराए। इसी तरह से मेरे हल्के में स्कूलो की बिल्डिंगो की हालत खराब है। उन बिल्डिंगो के बारे में मैं सरकार से रिक्वैस्ट करुगा कि उनकी रिपेयर का काम जल्दी से जल्दी भुरु कराया जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं ज्यादा समय न लेते हुए और आपका धन्यवाद करते हुए सरकार से यह अनुरोध करुगा कि जो भी मेरी मांग है उनकी तरफ ध्यान दे करके खास तौर से रोहतक जिले के कामो की तरफ ध्यान दे।

(धन्यवाद)

श्री योगे । चन्द भार्मा (बल्लबगढ): डिप्टी स्पीकर साहब, समय अभाव के कारण मुझे बजट पर बोलने के लिए समय नहीं दिया गया। आपने इन डिमांडज पर बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं डिमांड नम्बर 2,3,4,6,9,10,11,12,14 और 23 पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। इन डिमांडज पर बोलने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि जैसे तुलसी दास जी ने रामायण की रचना करते समय राक्षसों और देवताओं का आह्वान किया था कि वे उनको प्रणाम करते हैं उनको प्रमाण करते हैं उसी तरह से मैं भी अपने स्पीच स्टार्ट करने से पहले सत्ता पक्ष के भाईयों का प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम करने का मकसद है कि जब मैं बोलूँ तो सत्ता पक्ष के भाई कोई विघ्न न डालें। मैं आपको वि वास दिलाता हूँ कि मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा जो आपको अच्छी नहीं लगेगी। उपाध्यक्ष महोदय, अग मैं सबसे पहले ऐग्रीकल्चर की डिमांड पर बोलना चाहूँगा। औला दृष्टि से हुए नुकसान का जो 400 करोड़ रुपये पर एकड़ के हिसाब से पैसा किसानों को सरकार द्वारा दिया जा रहा है यह आज की महगाई के समय में बहुत कम है इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस राशि को बढ़ाया जाये क्योंकि जो खर्चा उनका एक एकड़ पर आता है वह 400 रुपये से ज्यादा आता है। पीछे मेरे हल्के के एक गाँव बहबुलपुर में काफी तूफान आया जिससे वहाँ पर सारे पेड़ उखड़ गए थे और लोगों का बड़ा भारी नुकसान हुआ था। वहाँ पर लोगों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई। बिजली के जो खम्भे थे वे भी सारे उखड़ गए थे उनको तो

एच0एस0ई0बी0 ने लगा दिया है। कुछ थोड़ी बहुत सुविधा जो डी0सी0 की तरफ से दी जानी थी वह दी गई है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लैवल जो सुविधाए दी जानी चाहिए थी वे आज तक नहीं दी गई है। वे लोग आज काफी परे गान है। जब लोगो को किसी प्रकार की कोई सुविधा न दी जाये और फिर इतनी भारी डिमांड सरकार की और से मन्जूरी के लिए आये तो वह ठीक नहीं लगता क्योकि जब सरकार किसी साइक्लोन और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की तरफ ध्यान नहीं दे सकती और उनका कोई सुविधा नहीं दी जा सकती तो फिर इस पैसे लेने का क्या फायदा है?

उपाध्यक्ष महोदय अब मैं शिक्षा की जो मांग है उस पर बोलना चाहूंगा। हाउस मे एक सवाल के जवाब मे मंत्री महोदय ने जवाब देते हुए बताया कि सभी हल्को मे बराबर अनुपात मे स्कूल और कालेज अपग्रेड किए गए है मेरे हल्के मे कालेज तो कोई अपग्रेड नहीं किया गया। इसका मुझे कोई दुख नहीं है। जहां पर ज्यादा अनपढ लोग है वहा पर कालेज पहले अपग्रेड किए जाए अच्छी बात है। लेकिन जहा मासूम बच्चो के साथ अन्याय हो यह ठीक बात नहीं है। सरकार ने फरीदाबाद जिले मे पलवल क्षेत्र मे 5 और हसनपुर क्षेत्र मे 3 स्कूल अपग्रेड किए है। वहा पर चार हल्के और बकाया रहते है जहा पर कोई स्कूल अपग्रेड नहीं किया गया। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहा पर भी स्कूल अपग्रेड किये जाये। मैं सरकार के नोटिस मे यह लाना चाहता हू कि

फरीदाबाद जिले में और फरीदाबाद के अन्दर जो लोग रह रहे हैं वह पावर्टी लाईन से भी नीचे की लाईन के रह रहे हैं। यदि उन बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी तो स्टेट के अन्दर अनसुलझे ऐलिमेंटस पैदा होंगे तो जो बाद में झगड़े करेंगे और सरकार के लिए मुसीबत बन सकते हैं। मेरी सरकार से पुरजोर प्रार्थना है कि बच्चों को शिक्षा देने के लिए विशेष प्रबन्ध करना चाहिए क्योंकि अमीर लोग तो अपने बच्चों को 200-250 रुपये देकर पब्लिक स्कूलों में पढ़ा सकते हैं लेकिन बेचारे गरीब आदमी कहा जाये। इसलिए मेरी सरकार से पुरजोर प्रार्थना है कि गरीब बच्चों की तरफ से सरकार विशेष ध्यान दे ताकि वे पढ़ लिख सकें। उपाध्यक्ष महोदय, देवली में एक सैन्ट्रल स्कूल मंजूर हुआ था। वह सैन्ट्रल स्कूल वहाँ पर इस भारत के साथ मंजूर हुआ था कि गाँव की पंचायत स्कूल के लिए जमीन ट्रांसफर करेगी। यह स्कूल खुला भी है लेकिन इस समय वह देवली में न चल कर पलवल में एक बहुत बड़े आदमी के घर में चल रहा है। इसको उसको किराया भी बहुत अधिक आ रहा है। गाँव की पंचायत की तरफ से स्कूल के नाम जमीन ट्रांसफर करने की फाईल करीब डेढ़ साल से डिवायलपमेंट मिनिस्टर के पास पड़ी है लेकिन उस फाईल को कलियर नहीं किया जा रहा है। वह इसलिए नहीं कलियर किया जा रहा क्योंकि उससे उस बड़े आदमी को काफी किराया आ रहा है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि इस फाईल को जल्दी से जल्दी कलियर किया जाये ताकि यह स्कूल देवली में चालू हो सके। वहाँ पर यह स्कूल इसलिए खोला गया था कि उससे 4-5 गाँवों जैसे

मान्दकौल, देवली, जटोला व असावटी आदि के बच्चो को फायदा हो। भाहरो मे तो वैसे ही बहुत से स्कूल खुले हुए है। इसलिए भाहर के बच्चे आई०ए०एस और एच०सी०एस० बनते है। गाव का तो कोई बच्चा नही निकलता, अगर एकाध निकलता भी है तो वह मुक्ति कल से क्लर्क से ऊपर नही निकल पाता।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने एरिये के एक गाव सागरपुर की चर्चा करना चाहता हू। भामान और दूसरी सुविधाओ के लिए गाव की जो नजूल जमीन थी उसे पिछले 2-3 महीने पहले तहसीलदार सेल्ज ने मौके पर जा कर 19 लाख रुपये मे नीलाम कर दिया। उसका बाजारी भाव 38.40 लाख से कम नही होगा। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक और डी०सी० के रेट के मुताबिक वहा पर 50 हजार रुपये एकड का रेट है। तहसील मे जा कर जब इसकी रजिस्ट्री करवाई गई तो यह 2 लाख 35 हजार की हुई। यानि कबीब साढे सोलह लाख रुपये बीच के अफसर और पोलिटिगियन्ज या ब्यूरोकेटस खा गए। इसी प्रकार दहारा ग्राउड की जो जमीन बेची गई थी सरकार ने मेहरबानी करके उस रजिस्ट्री को कैसल कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने मेरी यह प्रार्थना है कि सागरपुर गांव की जमीन की जो रजिस्ट्री है उसे भी फौरन कैसिल किया जाए और उस पर ये नायायज कब्जे को हटाया जाए। (विधन)

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नम्बर 14 जो कि खाध एवम आपूर्ति से सम्बन्धित है पर बोलना चाहता हू। खाध एवम

आपूर्ति महकमा जब बना था तो यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग था। लोगो की जरूरतो की जो चीजे है उनका वितरण लोगो सही हो इस महकमे का यही मतलब था। लेकिन आज इस महकमे मे इतना भ्रष्टाचार बढ गया है कि यदि पानी और हवा पर भी इस महकमे का अधिकार होता तो यह महकमा इन्हे भी ब्लैक मे बेच डालता। भगवान का भुक्र है कि हवा और पानी पर इस महकमे का कन्ट्रोल नही है वरना लोगो को जीने के लिए इन्हे भी ब्लैक मे खरीदना पडता और पूरा महकमा उसको खा जाता। हमारा डी0एफ0एस0ओ0 बराबर दो साल मे वहा बैठा हुआ है जब कि उसकी प्रोमो न होनी है लेकिन उसे प्रोमोट नही किया जा रहा है। उस प्रोमोट कर के चण्डीगढ लगाया जाए और हमारी जान उससे बचाई जाए। सरकार ने कज्यूमर्ज प्रोटैव न ऐक्ट, 1988 बनाया था। इससे लिए यह सरकार बधाई की पात्र है। इस ऐक्ट के तहत सरकार ने डिस्ट्रिक्ट फौर्म पूरे हरियाणा मे दो जगह रखे है। यह 3 टायर सिस्टम है। डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कौंसिल और ने नल कौंसिल इस प्रकार इसकी क्लासिफिके न की गई है। डिस्ट्रिक्ट फोरन के लिए इस ऐक्ट मे खासतौर मे लिखा गया है—

“There shall a be a District Forum is every District”

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी से मेरी यह प्रार्थनाप है कि कज्यूमर्ज को लुटाई से बचाने के लिए, सभी कज्यूमर्ज की रक्षा करने के लिए इसको सभी जिलो मे स्थापित किया जाए। आज

अगर एक कज्यूमर से 15-20 रूपये लूट लिये जाते है तो वह परे ानी से बचने के लिए फोरम के पास नही जाता। अगर सभी जिलो मे कन्ज्यूमर्ज फोरम होगे तो जिसकी लुटाई हुई है वह इनमे जा कर ि ाकायत करेगा। इस प्रकार बाकी के लोग इस लूट से बचेगे। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी स्टेट एक वैल्फेयर स्टेट है। वैल्फेयर स्टेट मे जो भी कार्य किये जाते है वे लोगो की भलाई के लिए ही किए जाते है उससे सरकार को कुछ नही मिलता। इस प्रकार कार्य लोगो की भलाई के लिए होते है इसलिए सरकार को कन्ज्यूमर्ज प्रोटैक् ान ऐक्ट के तहत जल्दी से जल्दी डिस्ट्रिक्ट फोरम बनाने चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इस मे कोई भाक नही कि इस कुछ खर्च तो जरूर होगा लेकिन इससे लोगो को बहुत ही फायदा होगा। जब हम करोडो रूपये दूसरे जनहित कार्यों पर खर्च कर रहे है तो इस कार्य पर यदि कुछ पैसा खर्च किया जाए तो यह बहुत ही अच्छी बात होगी। आन्ध्र प्रदे ा की सरकार ने अपने सारे जिलो मे डिस्ट्रिक्ट फोरम बनाए है। सबसे जो इफैक्टिव डिस्ट्रिक्ट कज्यूमर्ज फोरम है, वे महाराष्ट्र सरकार के है। इसलियस मेरा कहना यह है कि अगर सरकार को इस बात की नौलेज न हो तो मै सरकार को यह बताना चाहता हू कि वह अपने लोगो को महाराष्ट्र मे यहा आन्ध्रप्रदे ा मे भेजकर इसकी नौलेज गेन कर सकती है। (व्यवधान एवम भाोर) डिप्टी स्पीकर साहब, मै आपका इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हुंए आगे कुछ ओर कहना चाहता हू अब मै जनरल ऐडमिननिस्ट्रे ान के ऊपर थोडा सा बॉलना चाहूंगा। बल्लभगढ तहसील के अन्दर तकरीबन 25 गांव

ऐसे है जो अब पलवल तहसील मे पडते है उन गावो की बहुत बुरी द ाा हैं। वहां का एम0एल0ए0 जो उनको रिप्रेजेंट करता है, वह कटियाल साहब है। मै इनके बारे मे कुछ नही कह सकता हू लेकिन आज तक भी उन गावो का कोई बाली वारिस नही है। मार्किट कमेटी की सडक बनेगी तो उन गावो मे नही बनेगी, पी0डब्ल्यू0डी0 कोई सडक बनायेगा तो उन गावो मे नही बनायेगा, कहने का मतलब है कि उन गावो मे कोई काम नही होगा। पचायतो के अन्दर ग्राट देनी हो या किसी और तरह का काम डिवैल्पमैट का हो, तो वह वहा पर नही होगा। डिप्टी स्पीकर साहब, ये गाव बल्लभगढ सब डिवीजन मे पहले लगते थे। मेरा कहना यह है कि इन गावो को पलवल सब डिवीजन से तोड कर फिर से बल्लभगढ सब डिविजन मे मिलार दिया जाये। इसमे सरकार का कोई खर्चा भी नही आयेगा। मुख्यमंत्री जी यहा पर बैठे हुए है वह कृपया इस बात को नोट कर ले। हम जैसे विरोधी दल के विधायक भी इनकी बडाई करते है। यकीनन इनमे कोई बात होगी, आखिर यह दुनिया पागल तो नही है। आज जो हम लोग इनकी बडाई करते है इसके पीछे कोई न कोई बात है।(व्यवधान एवम भाोर) मै डिमाड पर ही आ रहा हू। आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुन तो ले।

**श्री उपाध्यक्ष:** भार्मा जी, आपको बोलते हुए 15 मिनट हो गये है।

**श्री योगे 1 चन्द भार्मा:** डिप्टी स्पीकर साहब, मै जल्दी ही खत्म कर रहा हू। डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा सरकार ने काम किये है। बहुत से इलाको मे सडके बनायी है। सब तरह की योजनाए बनायी है लेकिन कुछ विरोधी पक्ष के विधायको से कुछ नाराजगी थी इसलिए उनके इलाको मे सडके रह गयी है। थोडा सा हुयूमैन बिहेबीयर भी ऐसा है कि जब भी कोई बाटता है तो वह अपनो अपनो को ही देता है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय इतने अच्छे है कि मै उनसे एक रिक्वैस्ट करना चाहता हू यह पी0डब्ल्यू0डी0 का महकमा श्री भारतद्वज जी के पास है। (व्यवधान एवम भाोर) ठीक है, यह महकमा जगन नाथ जी के पास होगा। मे यह बताना चाहता हू कि हमारे यहा पर भी सडको की बहुत आव यकता है। मेरे यहा खादर का इलाका है। चौधरी देवी लाल जी न्याय युद्ध के दौरान वहा पर गये थे। वहा के लोगो ने बडी ही दरिया दिली के साथ उनका स्वागत किया था। उस समय उनको पगडी भी दी थी और उस रूपया भी साथ दिया था। उसके नतीजे के तौर पर यह हुआ कि बल्लभगढ से हमे जीत मिली।

**श्री उपाध्यक्ष:** आप अब समाप्त करे।

**श्री योगे 1 चन्द भार्मा:** केवल 5 मिनट और लूगा। मुख्यमंत्री जी यहा पर बैठे हुए है। वहा की 20000 की आबादी है। उन लोगो को जीवन की कोई सुख सुविधा मुहैया नही है बस की भाक्ल तक वहा के लोगो ने नही देखी है। लेडीज को डिलीवरी

आदि के लिये भी कोई मैडीकल सहायता की सुविधा नहीं है। रास्ते में ही वे दम तोड़ देती हैं। ला एंड आर्डर नाम की वहा पर कोई चीज नहीं है थानेदार अगर वहा पर कोई चला जाये तो वह पेट पर हाथ रखकर कहता है कि इस पेट के लिये क्या लाये हो। मैं यहा चाहूंगा कि वहा पर पुल जल्दी से जल्दी बनाया जाये ताकि वहा के लोगो को समुचित विकास हो सके। पुल के निर्माण के बनाये जाये ताकि वहा के लोगो का समुचित विकास हो सके। पुल के निर्माण के बिना वहा पर कुछ भी नहीं हो सकता। मैं विधान सभा के अन्दर उन लोगो की तरफ से यह माग रख रहा हूँ। मेरा विचार यह है कि सरकार इस बारे में विचार करेगी। उस समय चौधरी देवी लाल ने बड़ी मेहरबानी की थी। उन्होंने वायदा किया था कि सत्ता में आने के बाद छ महीने में यह पुल बनवा दूंगा। उन्होंने इवैस्टीगो इन रिपोर्ट और फिजिबिलिटी रिपोर्ट मगवाई थी और बाबु मूल चन्द ने एक पत्र लिखा था कि इस पुल के निर्माण की तुरन्त आवश्यकता है लेकिन धनाभाव के कारण उसका निर्माण भुर्रु नहीं हो सकता। डिप्टी स्पीकर साहब, यह काम सात करोड़ रूपए का है लेकिन जन जीवन को सुविधा देने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि वहा पर जल्दी से जल्दी पुल की सुविधा दी जानी चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, फरीदाबाद में जुडिियल कौम्पलैक्स को डिप्टी कमिश्नर के बैठने के लिए दे दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद एक बहुत ही इम्पौरमेंट डिस्ट्रिक्ट है और वहा मुख्यमंत्री जी और गृहमंत्री जी जाते रहते हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी

और गृह मंत्री जी से प्रार्थना है कि वहा पर जुडिाियल कौम्पलैक्स के साथ साथ वकीलो को बैठने के लिए कोई स्थान दिया जाए। इस समय वहा वकीलो के बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है। वैसे तो मैं समझता हू कि हरियाणा मे कही पर भी वकीलो के बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन कई जगह मारी सरकार ने वकीलो के लिए चैम्बर प्रोवाइड किए है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि मेहरबानी करके मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करे कि वहा पर वकीलो के बैठने के लिए जुडिाियल कौम्पलैक्स के साथ साथ चैम्बर की सुविधा भी प्रदान की जाए। कौम्पलैक्स होने से वहा सारे के सारे दफतर इक्टठे हो जाएगे और लोगो को इधर उधर भागना नहीं पडेगा। इससे लोगो की तकलीफो कम हो जाएगी। डिप्टी स्पीकर साहब, इन भाब्दो के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हू क्योकि आपने मुझे समय दिया।

**श्री मोहम्मद असलम खा (छछरोली):** उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमाण्ड नम्बर 2,3 और 4 पर अपने ख्यालत रखना चाहता हू। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सब से पहले डिमाण्ड नम्बर 2 के बारे मे यह कहना चाहता हू कि हमारे यहा खिजराबाद मे एक्साइज एंड टैक्से ान का एक बैरियर लगा हुआ है। वह बोर्डर से पच्चीस किलो मीटर पर है लेकिन इस बैरियर के कारण लोगो को बहुत भारी परे ानी हो रही है। लोगो को बहुत तकलीफ है। कोई भी अपने घर के लिए सामान लाता है उसको परे ान किया जाता है कोई कार वाला हो, कोई ट्रक वाला या कोई स्कूटर वाला हो

मतलब यह है कि कोई आदमी थोडा सा भी सामान लेकर आता है उसको बहुत अधिक परे ानी किया जाता है। कोई कार वाला, कोई ट्रक वाला या कोई स्कूटर वाला हो मतलब यह है कि कोई आदमी थोडा सा सामान लेकर आता है उसको बहुत अधिक परे ानी का सामना करना पडता है। पहले यह बैरियर क्लेसर मे या उसके बाद ताजेवाला मे लगाया और उसके बात खिजरबाद मे लगा दिया। मै सरकार से प्रार्थना करता हू कि लोगो को इससे बडी तकलीफ है इसलिए इस बैरियर को वहा से हटा दिया जाए। दूसरी बात मै यह कहना चाहूंगा कि आर्म लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए लोगो को बडी भारी एक्सरसाइज करनी पडती है। एस0डी0एम0 के दफतर से पांच छ रूपया फीस जो प्रैसकाइब्ड है जमार कराने के बाद लोगो का पांच सौ छ रूपया और खर्च हो जाता है। कभी उसको थाने मे जाना पडता हैं कभी उसको एस0पी0 के दफतर मे जाना पडता है। तब जाकर एस0डी0एम0 के दफतर मे जाना पडता है और कभी उनको डिप्टी कमी ानर के दफतर जाना पडता है। इस तरह से उनको पूरी एक्सरसाइज करनी पडती है। तब जाकर लाइसेंस रिन्यू होता है। मै यह कहना चाहता हू कि जो भी आदमी आर्म लेता है यह कोई गरीब आदमी नही होता वह अमीर आदमी होता है। आज एक अच्छे आर्म की कीमक बीस हजार से कम नही है। और वह अमीर आदमी ही खरीद सकता है। अगर इस फीज को पाच छ सौ रूपए से बढकर सौ रूपए कर दिया जाए और इस दौड धूप से आदमी को बचाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे सरकार को रैवेन्यू मे भी

फायदा होगा और लोगो की दिक्कत भी कम हो जाएगी। तीन साल के बाद लाइसेंस रिन्यू होता है लेकिन जिसके पास आर्म होता है उसको दुबारा से पूरे प्रोसीजर से गुजरना पडता है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर किसी आदमी का करैक्टर खराब है तो पुलिस सीधे एस0डी0एम0 को लिख दे कि फलां आदमी का लाइसेंस रिन्यू न किया जाए। इससे लोगो की भागदौड कम हो जाएगी। मैं और कही की बात तो नही जानता लेकिन मुझे पता है कि यमुना नगर मे तीन हजार या अढाई हजार ऐप्लीके 1न पिछले डेढ साल से पैडिंग पडी है। लोगो को पता ही नही लगता कि उनकी फाइल कहा पर है। वे बेंचारे फाइल ढूडते रहते है लेकिन पता नही लगता कि उनकी फाइल कहा पर है।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं डिमांड न0 8 पर कुछ कहना चाहूंगा जोकि बिल्डिंग एण्ड रोडज से ताल्लुक रखती है। मेरे इलाके मे काफी देर पहले दो पुलो की मन्जूरी हुई थीर लेकिन उन पर अभी तक काम भ चालू नही हुआ है। एक पुल पर थोडा बहुत काम ऐसे चल रहा है जैसे कि कीडी रेंग रही हो। कभी एक साल मे उसका एक पाया, अगले साल दूसरा पाया बना देते है और अब तक तीसरे पाया का कुछ पता नही है कि वह कब बनता है? एक उसके ऊपर लैटर जरूर डाल दिया है। सात पाये बनने है और आप इस से अन्दाजा लगा लीजियेगा कि जिन रफतार से वहा पर काम हो रहे है। उसके हिसाब से कम से कम 10 साल का वकफा लगेगा। इसलिये मेरी सरकार से रिक्वैस्ट है

कि इन दो पुलो कोटुपर व फतेहगढ जो कि सोमनदी पर बनने है का काम जल्दी ही किया जाना चाहिये, क्योकि इन पुलो के न बनने के कारण लोगो को 25 किलोमीटर का फासला तय करके चक्कट काट कर आना पडता है मेरे विचार मे भाायद इनका किसी ठेकेदार के साथ झगडा चल रहा है। मेरी प्रार्थना है कि उस को निपटा कर इन पुलो के निर्माण का काम जल्दी ही भुरु करवाया जाना चाहिये।

डिप्टी स्पीकर साहब, मै आगे यह कहना चाहता हू कि इस सरकार ने लोगो से वायदा किया था कि छोटे छोटे गावो को सडको से जोड दिया जाएगा। मेरे हल्के मे कुछेक सडके है जिनका हदबस्त नम्बर अलग अलग है। एक रोड है द्वारपुर से खानपुर तक और दूसरे भीलपुरे से कन्यावाला तक। इन सडको का निर्माण जल्द से जल्द किया जाना चाहिये ताकि लोगो को आने जाने मे दिक्कत न हो। हमारा खादर का इलाका है। अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है तो उसको ट्रैक्टर या चारपाई पर लिटा कर हस्पताल ले जाना पडता है लेकिन रोडज वहा को इतनी खराब है कि अगर बरसात पढ जाए तो रास्ता बिल्कुल ठप्प पड जाता है जिससे लोगो को काफी परे गानी होती है।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मै ऐजूके गन के मुताबिक कुछ बाते रखना चाहता हू। यहा हाउस मे सरकार की तरफ से कई बार कहा गया कि जिन स्कूलो मे टीचर्ज नही है हम वहा पर टीचर्ज अप्वायट कर रहे है लेकिन मै आपका बताना चाहता हू कि

इस कमी को अभी तक सरकार ने पूरा नहीं किया है जिस कारण से बच्चों की पढाई का नुकसान हो रहा है। हिन्दी का टीचर तो साईस पढा नहीं सकता और न ही मैथ का टीचर इंगलि । ही पढा सकता है। इसलिये हरियाणा के अन्दर जहा स्कूलों के अन्दर अलग अलग सब्जैक्टस के टीचर्ज की कमी है, वहा पर टीचर्ज लगाए जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, आज से चार महीने पहले डी0ई0ओज0 को यह पावर्ज दी गई थी कि वे अपने लैबल पर इस तरह की अप्वायटमैन्टस कर ले। कुछ देर के बाद वह फाइल चण्डीगढ मे मंगवा ली गई और अब फाईल पता नहीं कहा पर है। यह मसला अब बिल्कुल ही ठप्प हो गया है जिस कारण से बच्चों की पढाई का नुकसान हो रहा है। कितने ही ऐसे बच्चे है जो स्कूलों मे पूरे सब्जैक्टस के टीचर्ज न होने के कारण नुकसान उठा रहे है और फेल हो रहे है। इसलिये मेरी रिक्वैस्ट है कि इन स्कूलों मे टीचर्ज की कमी को दूर किया जाए। यह सिलसिला पूरे हरियाणा के अन्दर की है। सरकारइस और ध्यान दे।

अब मै डिमाड नम्बर 15 जो कि इरीगे ान से ताल्लुक रखती है पर अपने विचार रखूंगा। सन् 1870 मे ताजेवाला हैडवर्कस बना था और आज उस हैड वर्कस की हालत इतनी खस्ता है कि वह किसी वक्त भी टूट सकता है। सरकार उसकी मुरम्मत तो समय समय पर करती ही रहती है लेकिन उसका यह पता नहीं कि वह कौन सी बरसात निकालेगा और कौन सी बरसात मे वह हैड टूट जाएगा। उसकी हालत इतनी खस्ता है कि वह

कभी व किसी वक्त भी टूट सकता है। अगर वह टूट गया तो उसके कारण से ईस्टर्न व बैस्टर्न यमुना कैनाल्स दोनों ही बन्द हो जाएगी। ईस्टर्न यमुना कैनल का तो ऐडमिनिस्ट्रटिव कन्ट्रोल यू०पी० सरकार का है। इस बारे में तो उसने देखना है लेकिन बैस्टर्न यमुना कैनल जो है उससे सारे हरियाणा को पानी दिया जा रहा है। अगर यह नहर बन्द हो गई तो आप सोचिये कि हरियाणा के किसानों की क्या हातल होगी? लोगों का भारी नुकसान होगा। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इसी तरह से डिप्टी स्पीकर साहब, हथनी कुण्ड का मामला है। एक बार चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी, जो कि बिजली एवम सिंचाई मंत्री थे, मेरे साथ वहा पर गये थे और अखबारों नुमाइन्दे भी वहा पर मौजूद थे। हथनी कुण्ड बैराज के बारे में, मैंने उन से बातचीत की थी। उन्होंने मुझे कहा कि इस स्कीम की कांग्रेस के वक्त से वे लोग लटकाते रहे हैं और आज सरकार हमारी है हमारी सरकार जल्द ही इस पर काम शुरू करवाएगी। अगर सरकार ने यह काम भीघ्न न करवाया तो इससे भी बैस्टर्न यमुनास कैनल के ऊपर असर पड़ेगा और वह बन्द हो जाएगी जिसका पानी आज सारे हरियाणा के अन्दर मुहैया किया जाता है आज भी इस काम को लटकाया जा रहा है। हमने सरकार को यह कहा था कि अभी इस काम को करवा दीजियेगा क्योंकि सारी मीनिरी बाढ़ में लेनी पड़ेगी। सारा स्टाफ भी यहा से चला जाएगा। मैंने जाती तौर पर यह रिक्वेस्ट की थी कि सरकार को इस बारे में कुछ न कुछ

करना ही चाहिये। कही यह हो कि खुदा न खास्ता हथनी कुण्ड बैराज भी बना और दूसरा ताजेवाला हैड टूट गया तो दोनो नहरे बन्द हो जाएगी और लोगो को पानी नहीं मिल पाएगा और हमारा हरियाणा का किसान रोता रहेगा।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मै डिमांड न0 20 पर बोलना चाहता हूँ। मेरी कास्टीच्यूएन्सी मे जगलात पडता है और जो लोगो की दिक्कते है वह भी जगलात से ही संबधती है चाहे कोई उस जंगल मे अपने पशु चराता है या कोई चोरी से लडगी काटता है वहा पर फौरेस्ट गार्ड को बडी जबरदस्त पावर दी गई है वह एक आदमी पर दस और बीस हजार रूपए तक जुर्माना कर सकता है उसके पास किसी भी मैजिस्ट्रेट से ज्यादा पावर है। होता क्या है कि किसी आदमी ने चोरी से लकडी काट ली। जंगलात के ऊपर ही हम लोगो का गुजारा है और उसके बगैर जिन्दा नहीं रह सकते। वहा पर किसी के पास अपना पक्का मकान नहीं है और लोग झोपडियो मे रहते है। वे झोपडियो लकडी से ही बनती है। उसके लिए कोई कायदा बनना चाहिए, या तो उनको झोपडी के लिए 3-4 साल के बाद लकडी दी जाए। अगर उसको लकडी नहीं दी जाएगी तो वह लकडी की चोरी करेगा। अगर उसको लकडी दी भी जाती है तो उस वक्त दी जाती है जब जंगल मे आग लग जाती है। अगर उनको रूटीन मे तीन चार साल के बाद लकडी दे दी जाए तो वे चोरीनही करेगे। एक आदमी अगर लकडी काट लेता है और उसकी कीमत पांच सौ रूपए है तो

पांच सौ रूपए तो उससे फ़ारैस्ट गार्ड मांगता है और पांच सौ रूपए पुलिस वाले मांगते हैं इस हिसाब से उसको एक हजार रूपए देने पडते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने असल में चोरी से लकड़ी काटी है और पुलिस समझती है कि वाकया ही उसने चोरी की है तो उससे पैस वसूल किया जाए। अगर पुलिस समझती है कि उसने चोरी नहीं है तो उससे पैसा वसूल किया जाए। अगर पुलिस समझती है कि उसने चोरी नहीं की है तो उसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए एक पावर होना चाहिए। अब पुलिस को भी पावर है और फ़ारैस्ट गार्ड को भी पावर है। इस तरह से लोगों को लूटा जाता है मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि महकमा जंगलात से वहा पर पिलर्ज लगाए हुए हैं ताकि जानवर जंगल के अन्दर न जा सके। वहा पर बड़े छोटे छोटे पिलर्ज बनाए गए हैं। एक पिलर में मुँ कल से किलो डेढ किलो सरिया डाला होगा और सीमेंट के बारे में तो सभी को मालूम है कि कितना डाला जाता है। वे पिलर्ज रेत से बनाए गए थे इसलिए वे टूट गए और उनमें जो सरिया लगाया हुआ था उसको बच्चे उठा कर ले गए होंगे। लेकिन वहा पर लोगों को पकड़ कर उन पर पांच पांच हजार रूपए जुर्माना किया गया। पांच हजार रूपए के तो वे सारे पिलर नहीं होंगे। चार पांच पिलर गिरने से पांच हजार रूपया जुर्माना कर दिया। वहा का आदमी पांच हजार रूपया तो दो तीन साल में भी नहीं कमाता। इसलिए इस बारे में सरकार तवज्जह दे।

डिमांड न0 23 पर भी मैं बोलना चाहता हू। अभी दो साल पहले कलेसर में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक टूरिस्ट कौम्प्लैक्स बनाने की ऐप्रूवल आई। उसको मौके पर देखने के लिए डा0 महा सिंह जी गए थे। मगर आज तक उस सिलसिले में कुछ नहीं किया गया। मैं जानना चाहता हू कि वह स्कीम कहा गई। क्या उस सैंटर की सरकार ने वापिस ले लिया या उसके कागज की रूले पड़े हैं। इसके बारे में सरकार गौर के ताकि उस इलाके की भी डिवैल्पमेंट हो सके। वह जगह बहुत खूबसूरत है और उसे और भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। धन्यवाद।

**श्री आत्मा राम गोदार (धिराय):** उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हू। वर्ष 1991-92 में जो पैसा खर्च होगा वह बजट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हिसाब से रखा गया है। मैं सब से पहले मांग न0 3 पर बोलना चाहता हू जो गृह विभाग से संबंधित है। उपाध्यक्ष महोदय, जब से विधान सभा का सैशन चल रहा है तब से मेरे विपक्ष के साथियों ने गृह विभाग पर बहुत बड़े हमले किए हैं। जो जनरल मुश्किलें हैं उनका जिक्र करना, लोगों के सामने लाना और उनको हाउस में डिस्कस करना जरूरी है और उस पर जरूर हैल्दी डिस्कशन होनी चाहिए लेकिन किसी पोलिटिकल मकसद को पूरा करने के लिए किसी बात को उछाला जाए तो वह कोई हैल्दी डिस्कशन नहीं होती। मेरे विपक्ष के साथी पब्लिक में जा कर आग लगाने की बात कहे और यहाँ आ

कर सरकार को यह कहे कि सरकार आग नहीं बुझाती। इस रूप में जो डिस्कान हुई वह कोई हैल्दी डिस्कान नहीं है उसके पीछे कोई मकसद होता है और वह मकसद राजनीतिक है और उसको ले कर मेरे विपक्ष के साथियों में तानाजनी करनी है। उसके आधार पर जो मर्जी आए कह दिया जाए और यहाँ तक कह दिया जाए कि फला मंत्री 420 है या और कुछ कह करके मेरे विपक्ष के साथी हसते हैं और खुश होते हैं। यह उसको भावना नहीं देता। ऐसी बातें करना कोई हैल्दी डिस्कान नहीं है। यदि आपके पास इस विभाग के बारे में कोई ऐसी बात हो तो उसकी ठीक ढंग से डिस्कस करे ताकि जो असलियत है वह सामने आए, हाउस को भी उस बात का इल्म हो और लोगों को भी उस बात का पता लगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि हिन्दुस्तान के सभी लोग जानते हैं कि 1990-91 में दो बहुत बड़ी घटनाएँ हुईं उनको घटनाएँ नहीं बल्कि दुर्घटनाएँ कहा जाए तो अच्छा है। उन दुर्घटनाओं को लोग मण्डल कमण्डल कहते हैं। अगर देखा जाए तो वास्तविक रूप में मण्डल आयोग की रिपोर्ट लागू की गई थी। बहुत अच्छी बात हुई उस रिपोर्ट का कोई विरोध नहीं हुआ। यह बहुत अच्छी बात थी क्योंकि कमजोर वर्ग के लोगों को और पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय देने की बात थी। लोगों ने उस रिपोर्ट को सराहा भी लेकिन जिस रूप में और जिस सोच को आगे रख करके मण्डल आयोग की रिपोर्ट को एकदम पब्लिक के अन्दर फैंक दिया गया, उसका उल्टा असर हुआ। बजाये उस रिपोर्ट को एप्रिप्रिएट करते उसका रीएक्टान हो गया। ये जो बातें हुईं

उनसे सारे हिन्दुस्तान के अन्दर जान और माल का बहुत नुकसान हुआ। सारे हिन्दुस्तान में करोड़ों रूपए का नुकसान हुआ उसमें हमारा हरियाणा प्रदेश भी लपेट में आ गया लेकिन मैं अपने गृह विभाग की इस के लिए सराहना करूंगा कि उसने हरियाणा के अन्दर किसी जान का नुकसान नहीं होने दिया। उस समय हरियाणा प्रदेश के लिए सैटर की तरफ से फोर्स उपलब्ध नहीं हुई। ऐसे वक्त से ज्यादा से ज्यादा फोर्स होनी चाहिए लेकिन उस समय जो हमारी हरियाणा पुलिस थी वह उस ऐजेंटे को के लिए नाकافی थी पूरी फोर्स न होने के कारण हरियाणा माल नुकसान होने से तो नहीं बच पाया लेकिन जान का नुकसान नहीं होने दिया गया। हमारी हरियाणा पुलिस ने उस ऐजेंटे को में हरियाणा के अन्दर एक भी जान का नुकसान नहीं होने दिया लेकिन माली नुकसान को होने से नहीं बचा पाई। मैं समझता हूँ कि हमारी हरियाणा पुलिस ने उस समय जानी नुकसान नहीं होने दिया उसके लिए उसने सारे हिन्दुस्तान में सराहनीय काम किया है। सारे हिन्दुस्तान के अन्दर जहाँ सैकड़ों और हजारों जाने गई हैं वहाँ हरियाणा प्रदेश के अन्दर एक भी जान का नुकसान हमारी पुलिस ने नहीं होने दिया। यह हमारी पुलिस का एक सराहनीय काम था। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसकी 300-400 किलोमीटर लम्बी सीमा पंजाब बॉर्डर के साथ लगती है। हम पिछली 8-9 साल से देख रहे हैं कि पंजाब में किस तरह से घटनाएँ हो रही हैं। यदि हमारे साथ लगते हुए पंजाब राज्य में ऐसी घटनाएँ हो तो स्वाभाविक है कि उसका असर हरियाणा

प्रदे 1 पर भी पडेगा। लेनिक मै अपने गृह विभाग की सराहना करता हू कि हमारे पडोसी राज्य पजाब मे इतनी उग्रवादी घटनाए होती है और हो रही है लेकिन हरियाणा मे ऐसी उग्रवादी घटनाए उसने नही होने दी। अगर कोई घटना किसी प्वायट पर हो जाए तो उस समय पुलिस का यही रोल होता है कि वह दोशिया को पकड ले। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा ही एक अकेला ऐसा राज्य है जहा पर आज तक जो भी उग्रवादियो द्वारा घटना हुई उनमे सभी को या तो पकडा लिया गया या उनको मार दिया गया या फिर उन्हे जेलो की सलाखो मे डाल दिया गया है। पुलिस का यही काम है कि जहां पर कोई घटना हो जाये तो उस केस की छानबीन की जाये और दोशियो को पकड कर उन्हे सजा दिलाई जाये। हमारे गृह विभाग का काम बहुत ही प्र ासनीय रहा है। आजकल पजाब मे उग्रवादियो के पास मार्डन वैपन्ज है इसलिए उनका मुकाबला करने के लिए हमारी पुलिस के पास भी मार्डन वैपन्ज होने चाहिए ताकि उनका मुकाबला आसानी से हमारी पुलिस कर सके। मेरे हिसाब से तो इस मांग के तहत जो पैसा मांग गया है वह बहुत कम सके। मेरे हिसाब से तो इस इस मांग के तहत जो पैसा मांगा गया है वह बहुत कम है क्योकि हमारी पुलिस ने अब तक बहुत ही अच्छा काम किया है। यह बात भी मै इनके नोटिस मे लाना चाहता हू कि हरियाणा दिल्ली के तीन तरफ लगता है और दिल्ली हरियाणा से घिरी हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज तक दिल्ली में जितनी भी घटनाएँ हुई हैं उनको वहाँ की पुलिस पकड़ नहीं पाई लेकिन हमारी पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा है जिन्होंने यहाँ पर आ कर कोई घटना की है। उपाध्यक्ष महोदय, यहाँ पर मण्डल रिपोर्ट की बात आई। 1990 में एक लहर मण्डल और कमण्डल की भी चलो। हमारे साथी बैठे हैं। यहाँ कममण्डल की लहर चलो उसके पीछे भी कुछ राजनीतिक चाल थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मण्डल रिपोर्ट का जिक्र कर रहा था। सबसे पहले मैं यह उन्होंने बताना चाहता हूँ कि जिस समय चौधरी देवी लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए जिनको सारे हिन्दुस्तान में सराह गया और सारे हिन्दुस्तान की नजरे हरियाणा की तरफ लगी कि जो हरियाणा में काम हो रहे हैं यानि जो कल्याणकारी काम यहाँ पर किए जा रहे हैं वे काम उनके प्रदेश में भी हों। मेरे कहने का मतलब यह है कि चौधरी देवीलाल की स्कीमों ने सारे हिन्दुस्तान के लोगों को प्रभावित किया चाहे मजूर था या चाहे कोई किसान था। इन दो वर्गों के लोग तो विशेषकर प्रभावित हुए क्योंकि हरियाणा में इनके हक के लिए काम किया जा रहा था। इसका नतीजा यह हुआ कि चौधरी देवी लाल जी हिन्दुस्तान में बहुत लोकप्रिय हो गए और उस लोकप्रियता को तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री वी०पी० सिंह मीट आउट नहीं कर सके और उन्होंने जल्दबाजी में यह मण्डल रिपोर्ट लागू कर दी ताकि उनकी लोकप्रियता को घटाया जा सके। इस रिपोर्ट को वी०पी० सिंह ने लागू करते समय न तो अपनी पार्टी के सदस्यों से पूछा और न ही

सहयोगी पार्टियों से। बल्कि अपने नम्बर बनाने के चक्कर से खुद हो फैसला करके यह रिपोर्ट जल्दबाजी में लागू कर दी और उसका जो नतीजा हुआ वह सभी को पता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं कमण्डल का जिक्र करना चाहता हूँ। इस बात को संविधान इजाजत नहीं देता कि कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी धार्मिक मामले में शामिल हो। ( गोर एवम व्यवधान) इन्होंने राम मन्दिर बनाने के बहाने से एक आन्दोलन चलाया। ( गोर एवम व्यवधान)

**श्री राम बिलास भार्मा:** आन ए प्वायट आफ आर्डर सर। उपाध्यक्ष महोदय, ये कौन सी डिमांड पर बोल रहे हैं जरा नाम तो बताए। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये किस डिमांड पर बोल रहे हैं या इनका जवाब दे रहे हैं। ( गोर एवम व्यवधान) कौन सी डिमांड में बी०जे०पी० का जिक्र आया है क्या इनको दिन रात सिर्फ बी०जे०पी० ही दिखाई है। उपाध्यक्ष महोदय, इनको इररैलेवेंट नहीं बोलना चाहिए।( गोर एवम व्यवधान)

**श्री आत्मा राम गोदार:** उपाध्यक्ष महोदय, इनके उस आन्दोलन में जगह जगह जाने गई है लेकिन हरियाणा में हमारे गृह विभाग ने बड़ी मुस्तेदी के साथ काम करते हुए इनके ऐजिटे इन की बढ़ने नहीं दिया। (विघ्न)

**श्री सीता राम सिंगला:** आन ए प्वायट आफ आर्डर सर। उपाध्यक्ष महोदय, ये डिमांड पर ही बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। (विघ्न)

**श्री आत्मा राम गोदारा:** उस समय बी०जे०पी० के लोगो ने एक आन्दोलन चलाया था। (विघ्न)

**श्री राम बिलास भार्मा:** उपाध्यक्ष महोदय, बी०जे०पी० वालो ने कोई आन्दोलन नहीं चलाया था। मै इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि वह आन्दोलन वि व हिन्दू परिशद वालो ने चलाया था। (विघ्न)

**श्री आत्मा राम गोदारा:** आदरीणय श्री अडवानी जी ने कमल का फूल लगा कर रथ यात्रा भुरू की थी। (विघ्न)

**श्री उपाध्यक्ष:** आप कौन सी डिमाण्ड पर बोल रहे है ?

**श्री आत्मा राम गोदारा:** मै गृह विभाग की मांग पर बोल रहा हू। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, रथ यात्रा जहा से भी गुजारी वही पर तनाव फैला। आप तो जानते है कि रोहतक से जब रथ यात्रा गुजरी तो स्टूडेंटस पर लाठी चार्ज हुआ था। रथा यात्रा के कारण ही वहा पर तनाव फैला था।

**श्री राम बिलास भार्मा:** आपको सरकार ने रथा यात्रा मे अडचन डालने की कोि । । की लेकिन आपकी यह कोि । । सफल नहीं हुई।

**प्रो० सम्पत सिंह:** उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने रथ यात्रा में अडचन डालने की कोशिश नहीं की। तनाव की आशंका को देखते हुए सरकार ने पूरे प्रबन्ध किये थे। रथ यात्रा के कारण सारे देश के अन्दर एक तनाव फैला हुआ था और जयपुर में सकड़ो लोग मारे गए थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के प्रबन्ध में सकड़ो लोग मारे गए थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के प्रबन्ध किए गए थे। हमें हरियाणा की जनता और हरियाणा की पुलिस पर नाज है कि उन्होंने साम्प्रदायिकता की आग को भड़काने नहीं दिया। हमें इस बात पर गर्व है।

**श्री राम बिलास भार्मा:** आपने तो हरियाणा पुलिस और सी०आई०डी० की ड्यूटी लगाई थी कि रथ यात्रा में अडचन डाली जाए। रथ यात्रा के कारण रोहतक में कोई तनाव नहीं फैला बल्कि लाखों लोगों ने रथ यात्रा का स्वागत किया था।

**प्रो० सम्पत सिंह:** उपाध्यक्ष महोदय, सारे देश में साम्प्रदायिक तनाव फैला हुआ था। हरियाणा में भी भाई चारे और साम्प्रदायिक सदभावना को खत्म करने की साजिश की गई थी लेकिन इसके बावजूद भी हमने भाई चारा और साम्प्रदायिक सदभाव को बनाए रखने की पूरी कोशिश की। (विघ्न)

(इस समय कई सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गये)

**श्री उपाध्यक्ष:** आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठिए।

**श्री कैला । चन्द भार्मा:** कही पर भी साम्प्रदायिक तनाव नहीं था। (विघ्न)

**श्री उपाध्यक्ष:** आप प्लीज बैठे ।

**श्री सीता राम सिंगला:** माननीय गृह मंत्री जी बहुत ही योग्य हैं और बड़ी योग्यता से उन्होंने रथ यात्रा के समय साम्प्रदायिक माहौल को कंट्रोल किया। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि मण्डल कमी ।न आन्दोलन के समय इनकी योग्यता कहा चली गई थी। (विघ्न)

**प्रो० सम्पत सिंह:** मण्डल कमी ।न आन्दोलन के समय भी कुल मिला कर स्थिति नियन्त्रण में रह थी और मिलिट्री की सहायता से स्थिति को काबू में रखा गया था। (विघ्न)

**श्री उपाध्यक्ष:** आप कृपया बैठिए ।

**श्री आत्मा राम गोदारा:** इस आन्दोलन का नतीजा यह हुआ कि गृह विभाग पर भारी अतिरिक्त खर्च का बोझ पड़ा। इस बात की जिम्मेदारी उस हालात पर है जो उस वक्त पैदा हो गए थे। पुलिस ने स्थिति से निपटने में बहुत ही सराहनीय काम किया। उपाध्यक्ष महोदय, गृह विभाग पर यह अनवसैस्री खर्च पड़ा जिस कारण गृह विभाग के खर्च में बढ़ौतरी हुई।

**श्री उपाध्यक्ष:** अब आप अगली डिमाण्ड पर बोले ।

**श्री आत्मा राम गोदारा:** अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग को जो अतिरिक्त खर्च करना पडा है मै उसके कारणो को कह रहा हू। यह ऐसी डिमाण्ड है जो सब लोगो से कन्सर्ड है। मेरे साथी आवाज उठाते है कि हम असुरक्षित है हमारी रक्षा की जाए यह डिमाड उनसे सबधित है।(विघ्न)

**श्री उपाध्यक्ष:** आप बैठे और श्री गोदार को बोलने दीजिए।

**श्री आत्मा राम गोदारा:** उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पुलिस ने बडे बडे ऐजिटे 1न्ज मे हमारे लोगो को बचाया, सम्पति को बचाया। मेरी बी0जे0पी0 के साथी फिर उठ कर खडे हो जाएगे। रथ यात्रा के अलावा उन्होने एक ज्योति भी जलाई थी। जो ज्योति जली थी उसके कारण भी पुलिस पर अतिरिक्त कार्य का बोझ पडा। (विघ्न)

**एक आवाज:** वह ज्योति प्रकाश के लिए थी। (विघ्न)

**श्री आत्मा राम गोदार:** उपाध्यक्ष जी, इस अतिरिक्त बोझ के बावजूद भी पुलिस ने बडी सतकर्ता से काम करके हरियाणा को बचाने मे बहुत बडा योगदान कियां। (विघ्न)

**श्री राम बिलास भार्मा:** डिप्टी स्पीकर साहब, क्या यह बजट की डिमाडज पर बोल रहे है या बहस का जवाब दे रहे है? (व्यवधान एवम भाोर) डिप्टी स्पीकर साहब, आप देखिये कि यह डिमाडज पर बहस का जवाब दे रहे है या अपनी बात बोल रहे है?

इनको सपने मे कोई बात दिखाई दे गयी। कोई ज्याति दिखाई दे गयी या कमल का फूल दिखाई दे गया जिसकी वजह से अब यह डर रहे है। अडवानी जी अयोध्या जायेगे तो वहा पर कमल का फूल ही तो चढाएगे। इनका हाथ काट कर तो चढाएगे नही।

**श्री उपाध्यक्ष:** गोदरा जी, आप डिमाडज पर ही बोले।  
(व्यवधान एवम भाोर)

**श्री हीरा नन्द आर्य:** डिप्टी स्पीकर साहब, अगर दोनो तरफ से भाोर न हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

**श्री आत्मा राम गोदारा:** अगर सभी इस पर अमल करेगे तो मै भी ठीक तरह से बोल पाऊंगा और आप लोग भी असलीयत जान पायेगे। मेरे साथी अखबारो को बार बार दिखाते है कि वह छपा है वह छपा है। यहा पर कुछ न कुछ गडगड लगती है। अखबार वाले ऐसे मामलो को कवर करते है और लोगो तक खबरे पहुचाते है लेकिन उन्होने सही खबरे नही पहुचायी है। पिछले दिनो तक इनकी खबरे पहुचाने की जो भूमिका थी, वह सही नही थी। पिछले दिनो तक इनका रोल खबरे पहुचाने का सही नही था। वास्तविक रूप से जो रोल इनका होना चाहिये था, वह नही था, अखबार वाले भी हयूमैन बीडग्ज होते है। कई बार वह भी गलत सूचा दे देते है। जिसकी वजह से लोगो के अन्दर बहुत उत्तेजना आयी। इससे भी पुलिस के उपर सबसे ज्यादा भार पडा है। मै अपने साथियो से यह कहना चाहता अखबार की बात कोई

गौस्पल ट्रूथ नहीं होती। कई बार ऐसा भी होता है कि अखबार वाले साथी सही घटना की गहराई में नहीं जा पाते। उनको जल्दी से रिपोर्ट भेजनी होती है। इसलिये कई बार खबरों में त्रुटियाँ रह जाती हैं। जिस कारण कई दफा खबर में फर्क आ जाता है। इसलिये मैं बीजेपी के साथियों को यह कहना चाहता हूँ कि अखबार वालों पर ज्यादा रिकार्ड करेंगे तो यह लोग खुद ही फंस जायेंगे। अखबार वालों ने तो पता नहीं इनके बारे में क्या क्या बातें लिख रखी हैं। इसी तरह से हमारे जनता दल वाले भी खुद फंस जायेंगे क्योंकि इनके बारे में भी पता नहीं अखबार वालों ने क्या क्या लिख रखा है। तो मेरा कहना यह है कि गृह विभाग से संबंधित मांग इसलिए है क्योंकि पब्लिक में उत्तेजना आयी। झगड़े बढ़े और उन झगड़ों को रोकने के लिये पुलिस पर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है।

**श्री उपाध्यक्ष:** आप डिमांडज पर ही बोलिये।

**श्री आत्मा राम गोदार:** ठीक है जी। अगर आप समझते हैं कि मैं डिमांडज पर नहीं बोल रहा हूँ तो आप मुझे टोक दें। मैं अब इस संबंध में इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा।

इसके अलावा अब मैं थोड़ी सी बात ट्रांसपोर्ट के बारे में भी कहना चाहूंगा। यह डिमांड नं० 23 पर है। सारा ही हिन्दुस्तान जनता है कि हरियाणा के अन्दर हरियाणा परिवहन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इसका कार्य बड़ा ही सराहीनय रहा है।

हरियाणा परिवहन सारे हिन्दुस्तान मे नम्बर वन पर है। कमाई के लिहाज से और लोगो को सहूलियते देने के लिहाज से इसने बडा ही सराहनीय काम किया है। फिर यहा पर मडल कमी न का जिकर भी आया है। मै अगर इसका जिकर कर दूगा तो फिर वही बात आयेगी। मै सिर्फ बताना चाहता हू कि 1990-91 वर्ष के अन्दर मडल और कमडल की वजह से हरियाणा परिवहन पर सबसे ज्यादा भार पडा है।

**श्री विठ्ठल प्रसाद:** यही मंडल और कमडल आपका नाम है। आप करेगा। (विधन)

**श्री आत्मा राम गोदारा:** उपाध्यक्ष महोदय, मै यह कह रहा था कि इससे हरियाणा परिवहन पर अतिरिक्त भार पडा है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे हरियाणा की परिवहन की सम्पत्ति को बडा नुकसान पहुचाया गया। इसके बावजूद आज भी इस समय हरियाणा परिवहन लोगो की सुख सुविधा के लिए बहुत काम कर रही है। इसके साथ ही साथ मै हरियाणा परिवहन मंत्री के नोटिस मे एक बात लाना चाहता हू। हमने देखा है कि कुछ लोग बसो की छत पर बैठकर चलते है। इसका कारण यह हो सकता है कि या तो बसो मे बैठने की जगह नही होती या उनको छत पर बैठने को भाोक है और छत पर बैठने की उनकी आदत बनी हुई है। मै मंत्री महोदय से प्रार्थना करूगा कि वे कोई व्यवस्था करे और कम से कम लोगो की सुरक्षा के लिए कोई ऐसा इन्तजाम करे कि लोग छते पर चढे हुए नजर न आए। चाहे तो परिवहन विभाग ज्यादा

बसिज चलाए या कोई और इन्तजाम करे। मेरी परिवहन मंत्री श्री वेद मलिक से वि शेष प्रार्थना है कि इस चीज पर वे वि शेष ध्यान दे।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं इरीगे ान एड पावर के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। 1987 में जब से हमारी सरकार आई है इन दोनों विभागों ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारा प्रदेश कृषि प्रदेश है। इसलिए कृषि के मामले में हमारे देश में बहुत तरक्की की है हमारे प्रदेश में 61 प्रति भात लोग खेती करके अपना पेट पालते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, कृषि विभाग और सिंचाई विभाग से प्रभावित होती है। बिजली विभाग और सिंचाई विभाग ने बहुत कोशिश करके लोगों को नहर का पानी और ट्यूबवैलज दिए हैं। इन विभागों का बहुत ही अच्छा काम रहा है। डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं अपने हल्के के बारे में कहना चाहता हूँ। पावडा ब्राच में मेरे हल्के में पडती है और वह सतर साल से सब ब्राच चल रही है। मुझे पता लगा है कि सरकार ने कोई स्कीम बनाई है जिसके तहत पावडा सब ब्राच मेरे हल्के पर टेल बन जाएगी। डिप्टी स्पीकर साहब, इससे मेरे हल्के को बहुत नुसान पहुँचेगा। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस स्कीम को अच्छी तरह से स्टडी किया जाए और इसको इस रूप में लाया जाए जिससे कि मेरे हल्के में भी ज्यादा फायदा हो और मेरा हल्का किसी नुकसान से प्रभावित न हो तो इस स्कीम का जो भी फायदा हो वह मेरे हल्के को भी पहुँचे।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं फूड एण्ड सप्लाइज के बारे में कहना चाहता हूँ यह मांग नम्बर 14 है। पिछले दिनों खाड़ी युद्ध के कारण लोगों ने जमाखोरी करनी शुरू कर दी थी और इस कारण कीमतों में वृद्धि हुई थी लेकिन अच्छा हुआ कि वह युद्ध अब खत्म हो गया है। वैसे तो हमारे यहाँ फूडग्रेज की कोई कमी नहीं है लेकिन खाड़ी युद्ध के कारण लोगों के मन में ऐसी भावना पैदा हो गई कि युद्ध के कारण अनाज की कमी हो जाएगी। इस बात को देखते हुए अनाज की कीमतों में कुछ बढ़ोतरी आई। कीमतों का बढ़ना न तो हरियाणा सरकार के हाथ में है और न ही फूड एण्ड सप्लाइज विभाग के हाथ में हैं यह तो सारे देश का मामला है। लेकिन देखने वाली बात है। उपाध्यक्ष महोदय, इस दिनांक में फूड एण्ड सप्लाइज विभाग ने जो काम किया उसके आकड़े में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल जनवरी, फरवरी और मार्च 1990 इन तीनों महीनों में फूड एण्ड सप्लाइज विभाग ने लोगों को कितना अनाज गेहूँ वितरण किया मैं उस वितरण के आकड़े आपके सामने देना चाहता हूँ।

12.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, अनाज के वितरण का मामला बड़ा ही आवश्यक है हमारे साथी इस बात की आवाज उठा रहे थे कि अनाज नहीं मिला। मंहगा हो गया। इसलिये मैं इस संबंध में कुछ आकड़े यहाँ आपकी आज्ञा से सदन में प्रस्तुत करता हूँ। (गोर) फूड एण्ड सप्लाइज विभाग की बहुत जरूरी बातें सदस्यों के सामने

मैं रखना चाहता हूँ। जनवरी, 1990 में 2009 मीट्रिक टन अनाज का वितरण किया गया और जनवरी 1991 में 19500 मीट्रिक टन अनाज बाटा गया। इसी तरह से फरवरी 1990 में 470 मीट्रिक टन अनाज और इसके मुकाबले में फरवरी 1991 में 30529 मीट्रिक टन अनाज बाटा गया। ( गोर एवम व्यवधान) तो ये लोग कैसे कहते हैं कि अनाज नहीं मिल रहा।

**श्री उपाध्यक्ष:** गोदारा साहब, आप बैठिए। आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है।

**श्री आत्मा राम गोदार:** उपाध्यक्ष महोदय, ये सच्ची बात तो सुनना ही नहीं चाहते। इनको सच्ची बात तो कम से कम सुननी ही चाहिये। इसलिये मैं यह कहूँगा कि इस फूड एण्ड सप्लाई विभाग में बड़ा ही सराहनीय काम किया है।

अब मैं डिमांड न0 13 जो कि समाज कल्याण विभाग से ताल्लुक रखती है पर कुछ बोलूँगा। समाज कल्याण के मामले में अगर सब से ज्यादा समाज कल्याण कारी काम हुए हैं तो वे केवल चौधरी देवी लाल जी के नेतृत्व में ही भुरू कि ये गये थे। यह विभाग छोटे एवम कमजोर वर्गों के लोगों के लिये बड़े ही सराहनीय काम कर रहा है। इस विभाग की भूमिका बहुत बढ़िया है इस समय श्री अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए। इस विभाग के बढ़िया कामों की भी हमें यहाँ पर अब यही चर्चा करनी चाहिए। यह सारा काम 1987 में जब हमारी सरकार आई और चौधरी देवी लाल

जी उस वक्त मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने लोगो की भलाई के लिये, लोगो के कल्याण के लिये बुढापा पैन्शन और भोडयूल्ड कास्ट लोगो को कर्जा देने की स्कीमे चलाई। इन स्कीमो की वजह से इस विभाग का काम और बढ गया।

**श्री अध्यक्ष:** गोदार साहब अब आप वाइड अप कीजियेगा।

**श्री आत्मा राम गोदारा:** स्पीकर साहब, मुझे तो बोलते हुए अभी केवल 10 मिनट ही हुए और आप मुझे वाइड अप करने के लिए कह रहे है। ( गोर)

**श्री अध्यक्ष:** गोदारा साहब, आपने 11.34 पर बोलना भुरु किया था अब आपको बोलते हुए आधा घन्टा हो गया है लेकिन आप कह रहे कि मुझे 10 मिनट ही हुए है। आप कृपया वाइड अप कीजिएगा। ( गोर)

**श्री आत्मा राम गोदार:** स्पीकर साहब, मै यह कह रहा था कि जितनी भी आज इस विभाग के पास कल्याणकारी स्कीमे है वे सभी चौधरी देवीलाल जी के कार्यकाल मे ही उन्ही द्वारा बनायी गयी थी। ( गोर एवम व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** गोदारा साहब, बस आप बैठिये। आपका समय हो गया है।

**श्री आत्मा राम गोदार:** ठीक है जी, धन्यवाद।

**चौधरी सतबीर सिंह कादयाना (नौलथा):** स्पीकर साहब, धन्यवाद। मैं 1991-92 के बजट से संबंधित डिमांडज पर अपने विचार रखने के लिये खड़ा हुआ हूँ और इनका समर्थन करता हूँ सब से पहले डिमांड न0 3 जो कि गृह विभाग से ताल्लुक रखती है, पर कुछ कहूँगा जिसके तहत 1241707000 के खर्चे का प्रावधान है। यह खर्चा कल्याणकारी स्कीमों के बेनाम ज्यादा है परन्तु इस प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण इस विभाग के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिये ज्यादा पैसे का प्रावधान करना स्वाभाविक ही था ताकि जनता को सामान्य प्रशासन और न्याय दिलाया जा सके। यह नहीं, इस डिमांड के तहत तो और पैसा बढ़ाने की आवश्यकता है। पुलिस को आधुनिक हथियार और जीपें चाहिए क्योंकि हमारी प्रदेशों पंजाब से जुड़ा हुआ है और दिल्ली के भी तीन तरफ लगा हुआ है। दिल्ली में जब कभी राजनैतिक अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए गलत काम कर जाते हैं। जैसे मडल कमीशन की रिपोर्ट को जल्दबाजी में अपने साथियों से सलाह मँगि वर्रा किए बगैर लागू करने की कोशिश की गई। उससे सारे देश में हालत बिगड़े। हम मानते हैं कि सब को अपने अपने अधिकार चाहिए लेकिन मडल कमीशन की रिपोर्ट जल्दबाजी में लागू की गई। उस समय चौधरी देवी लाल जी देश के उप प्रधान मंत्री थे उनका इस्तीफा जिन हालात में लिया गया वह भी सब को मालूम है। उन्होंने एक भ्रष्ट मंत्री के खिलाफ प्रधान मंत्री को दर्खास्त भेजी थी वे देखे कि इस मामले में कहीं मंत्री का हाथ तो नहीं है। हम लोग जब यहाँ पर अपने मुख्यमंत्री को कोई

ऐसी बात बताते हैं तो वे उसकी छानबीन का आदेश देते हैं। लेकिन इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री की दखिस्त की तरफ ध्यान न दे और उल्टे उनको सरकार से बखिस्त कर दे। उसके बाद चौधरी देवी लाल जी ने देश की जनता को बताने के लिए एक विमल रैली की कि यह मडल कमीशन की रिपोर्ट जल्दबाजी में लागू की गई है। उनकी बातों को सुन कर लोगों की आत्मा भडकी लेकिन हरियाणा पुलिस ने बडी बखूबी से हालात कन्ट्रोल किया। स्पीकर साहब, विधार्थी मार्किट कमेटी के दफतर में आग लगा दे या सेल्ज टैक्स के रजिस्टर फूक दे, उनका इससे कोई वास्ता नहीं। ऐसे रजिस्टरो में सरकार के रैवेन्यू का रिकार्ड होता है। इसके पीछे तो किसी राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किन्ही लोगों का हाथ था। बडे बडे पूजीपति चाहते थे कि वे रजिस्टर गुम हो जाए या जला दिए जाए ताकि प्रदेश में अव्यवस्था फैल जाए। परन्तु मैं हरियाणा सरकार और गृह मंत्री को इस बात के लिए बधाई देता हूँ जिन्होंने स्थिति को बडे अच्छे ढंग से काबू किया। इसके अलावा जब भी पजाब से आतकवादियों ने हरियाणा की तरफ घुसने की कोशिश की, हरियाणा पुलिस ने उनको रोका। उनके साथ ऐनकाउटर किए और उनको पकड पर तौरचर कियां हमारी पुलिस उनको दिल्ली की सल्तनत तक जाने में रोकने के लिए सफल रही। जहा तक आरक्षण की बात है हमने श्री गुरनाम सिंह की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया। उस कमीशन की रिपोर्ट को आदरणीय चौधरी हुकम सिंह की सरकार ने लागू किया। इस

रिपोर्ट को लागू करने से हरियाणा के हरि वर्ग के आदमी को न्याय मिला है।

अब मैं डिमांड न0 4 जो राजस्व के बारे में है पर अर्ज करना चाहता हूँ इस विभाग के खर्च को आज कम करने की जरूरत है क्योंकि सरकार किसानों के लिए एक ऐसी पद्धति बना सकती है जिससे यह खर्चा कम हो सकता है। जैसे जमा बन्दी की नकल लेने के लिए किसान को बार बार पटवारी के पास जाना पड़ता है, कभी उसने बैंक से कर्जा लेना होता है या अपनी जमीन किसी को रहन रखनी पड़ती है तो उसके लिए उसको जमीन को पूरी जानकारी पटवारी लिख कर देता है। मैं चाहता हूँ कि सरकार किसान को कोई ऐसा डाकुमैट बना कर दे जिस में उसकी जमीन की पूरी डिटेल्स हो कि किस गांव में उसकी जमीन है और कितनी है। इससे उनको लोन लेने में सुविधा होगी। अध्यक्ष महोदय, मेरे नोटिस में एक बात रीहैबिलीटेशन के बारे में आई है। फरीदाबाद में एक तहसीलदार ने कुछ लोगों से झूठे एफेडैविट ले कर गलत तरीके से प्लॉट अलॉट किए हैं। उस तहसीलदार को हमारी सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। मैं अपनी सरकार से यह जानना चाहूंगा कि उस समय मंत्री कौन थे और अफसर कौन कौन थे जिनकी रहनुमाई में यह काम हुआ। इस बारे में सरकार जांच करे ताकि हरियाणा प्रदेश के राजस्व के जो खर्च है उनका दुरुपयोग न हो, प्रदेश की सम्पत्ति का सदुपयोग हो। सरकार को इस बारे में पूरी तरह से जांच करनी चाहिए।

अब मैं डिमांड नम्बर 5 के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। यह डिमांड कराधान विभाग से संबंधित है। हमारी सरकार ने यह एक बहुत ही सराहनीय काम किया है कि उसने ट्रैक्टरों, जीपों और कारों के टैक्स कम किए हैं। हमारी सरकार ने उद्योगपतियों को पिछले तीन चार साल में 8.66 करोड़ रुपये की अनुदान जेनरेटिंग सैट्स लगाने के लिए दिया। हमारी सरकार ने जेनरेटिंग सैट्स लगाने के लिए जो 50 हजार रुपये की सबसिडी दी जाती थी उसको बढ़ा कर 15 लाख रुपये कर दिया है ताकि उद्योगों को पूरी बिजली मिल सके और 24 घंटे बिजली मिले और उद्योगपति स्वयं अपने जेनरेटर से बिजली पैदा कर सकें। इसके इलावा हरियाणा के किसानों को भी 24 घंटे बिजली मिल रही है।

अब मैं डिमांड नम्बर 8 के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। यह डिमांड भवन तथा सड़कों से संबंधित है। हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के गांवों में सड़कों का जाल बिछा दिया है। मैं अपनी सरकार से निवेदन करूंगा कि करनाल में मूरथल तक जो हाईवे को फोर लेन बनाना है उसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के कारण हाईवे पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा मात्रा में चलता है। इसके अलावा मैं अपनी सरकार से निवेदन करूंगा कि पानीपत में दो फ्लाइंग ओवर ब्रिज बनने हैं। एक असध रोड पर और एक गोहाना रोड पर, उनका काम जल्दी शुरू कराया जाए ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो। हरियाणा का बिजली विभाग सारे प्रदेश में सबसे अच्छा विभाग

है जिसके कारण हमारे किसानों को 24 घंटे बिजली मिल रही है दूसरे प्रदेशों में किसानों को ट्यूबवैल कनेक्शन लेने में बड़ी भारी दिक्कत है लेकिन हरियाणा में किसानों को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हरियाणा प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है। जब भी चौधरी देवी लाल जी मुख्यमंत्री बने हैं या उनकी पार्टी का राज आता है बिजली के मामले में हरियाणा प्रदेश की जनता अपने आपको स्वर्ग में महसूस करती है।

अब मैं डिमांड नं० 17 के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। यह डिमांड कृषि विभाग से संबंधित है। हमारे प्रदेश का मुख्य पैदावार कृषि है। हमारे देश की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का कृषि महकमे पर इतना कंट्रोल है कि केन्द्रीय सरकार बनते ही कृषि से संबंधित जो बात जनता सोचती है उसको उससे पहले ही पूरा कर देते हैं औलावृष्टि से फसलों के हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाता है किसानों को खाद दी जाती है। कृषि विभाग एक डाइवर्सिफिकेशन भी हुई है। एक हॉर्टीकल्चर विभाग भी बनाया गया इसलिए स्वाभाविक है कि उस पर खर्चा ज्यादा होगा। हॉर्टीकल्चर विभाग ने बागबानी लगाने की स्कीम चलाई है। यह बहुत अच्छी बात है। बाग लगाने से वातावरण भी ठीक होता है। इसके अलावा आदरणीय नेता चौधरी देवी लाल जी ने पहली बार 32 रुपए क्विंटल के हिसाब से गेहूँ का भाव बढ़ाया था और लगभग 19 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हमारी मौजूदा सरकार

पिछले तीन साल मे गन्ने का भाव बढा चुकी है। चीनी का भाव भी उस समय से 8 या 9 रूपए किलो रहा है। हमारी सरकार की अपने सारे खर्चे कम करके जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुचाने की जो स्कीम है उसकी हम बडी प्रोत्साहन करते है।

हमारी हरियाणा प्रदेश का परिवहन विभाग एक नमूने का विभाग है। हरियाणा राज्य परिवहन की बसे प्रदेश के दूसरे प्रान्तो मे भी आती है जब हरियाणा की बस उत्तर प्रदेश मे जाती है तो उत्तर प्रदेश के पैसेजर हरियाणा राज्य की बसो मे बैठ कर बहुत खुश होते है पजाब की सवारिया भी पजाब की बसो मे बैठने की बजाय हरियाणा की बसो मे बैठना पसंद करती है। स्पीकर साहब, मण्डल और कमण्डल के बारे मे जो बाते कही गई है उसको कुछ भाइयो ने अच्छा नही माना इसलिए मै उसकी बात नही कहता (विधन) स्पीकर साहब, दूसरे प्रदेशो मे जो रोडवेज है वे हमारी रोडवेज का मुकाबला नही कर सकती।(विधन) लेकिन मण्डल कमीशन की रिपोर्ट के विरोध स्वरूप हमारी बसो को कुछ बैड एलिमेटस ने जला दिया। जिन बैड एलिमेटस ने हमारी बसो को जलाया उससे उनको तो कुछ फर्क नही पडा लेकिन उसका नुकसान हरियाणा रोडवेज और हरियाणा की जनता को हुआ। इसलिये अब मै मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हू कि ऐसे बैड एलिमेटस पर कन्ट्रोल करे और गावो मे पूरी बसे भिजवाने की व्यवस्था करे क्योकि चौधरी देवी लाल की पार्टी की सरकार कभी भी वह नही चाहेगी कि गावो मे बसो न जाये। गावो मे बसे

अब यह भेजी जाये चाहे इसके लिए बाहर के रूटो को ही कैंसिल क्यो न करना पडे। यदि फिर भी कमी बनी रहती है। तो सरकार को नई बसो की खरीद कर लेनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं सहकारिता विभाग के बारे जो डिमांड है उस पर बोलना चाहता हू इस विभाग ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है। इस विभाग के माध्यम से लोगो को भूमि विकास बैंक और को आप्रेटिव बैंको के जरिये काफी लोन लेने सुविधा दी जा रही है। हमारी स्टेट मे जितने भुगर मिल लगे हुए है वे सभी के सभी मुनाफे मे चल रहे है। इन मिलो मे काफी लोगो को रोजगार भी मिलता है। और किसानो को कै । आप का लाभ भी मिलता है। इस समय सारे हिन्दुस्तान मे हरियाणा के अन्दर गन्ने का भाव सबसे अधिक दिया जा रहा है हमारे प्रदे । मे किसानो को 45 रूपये प्रति क्विटल के हिसाब से गन्ने का भाव दिया जा रहा है। (घटी) स्पीकर साहब, मैं जल्दी ही खत्म कर देता हू। इतना भाव देकर सरकार ने एक बहुत ही खु ।हाली का कदम उठाया है। (विघ्न)

अध्यक्ष महोदय, अब मैं सिचाई की डिमांड पर बोलना चाहता हू इस डिमांड के तहत जो पैसा मांगा गया है वह बहुत ही कम है इसे और बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार को किसानो को ठीक समय पर नहरी पानी देने की व्यवस्था करनी चाहिए। हरियाणा सरकार ने जो सुविधाए अपने किसानो को अब तक दी है उन पर किसी को कोई आपत्ति नही है। इसलिये इस मांग के

तहत जो पैसा मांगा गया है वह सब को स्वीकार्य होना चाहिए। इस संबध मे मै बोलते हुए यह भी कहना चाहता हू कि एस0वाई0एल0 नहर जल्दी से जल्दी बने ऐसे निर्दे । चौधरी देवी लाल जी के कहने पर केन्द्र सरकार ने दिए है इस नहर को जल्दी से जल्दी बनाया जाये। जिनती जल्दी यह नहर बनेगी उतना ही अधिक फायदा हरियाणा को होगा। अध्यक्ष महोदय, बाते तो बहुत सारी कहनी थी लेकिन समय के अभाव जी की तरफ से सदन मे आई है इनको पास कर दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।

**श्री देवी दास (सोनीपत):** स्पीकर साहब, मै मांग की सख्या 3,8,9,11,12,14 और 16 पर बोलना चाहता हू । सबसे पहले मै माग सख्या 3 पर ही बोलूंगा क्योकि इस माग पर मेरे से पहले सतबीर सिंह कादियान और गोदारा साहब ने बोलते हुए काफी कुछ कहा है। साथ ही साथ मांग है कि इस डिमाड के तहत जो 134 करोड रूपये मागे गए है इनको पास कर देना चाहिए। इस मांग के तहत बोलते हुए यहा पर मण्डल और कमण्डल की बात भी आई है। मै मण्डल की बात तो करूंगा ही लेकिन कमण्डल की बात करते हुए मै यह स्पष्ट कर देता हू कि वह कमण्डल नहीं था बल्कि एक रथ यात्रा थी। कल मेरे एक सवाल के जवाब मे हाम मिनिस्टर साहब ने बताया था कि मण्डल रिपोर्ट लागू होने पर जो दगे हुए उनमे अकेले सोनीपत जिले मे पुलिस विभाग का 1 लाख 46 रूपये, हरियाणा रोडवेज का 3 करोड 35 लाख रूपए, पी0डब्ल्यू0डी0 बी0एण्ड0आर0 का 1 लाख 10 हजार रूपये, फूड

एण्ड सप्लाई डिपार्टमेंट का 29 हजार रुपये, पी0एड0टी0 का 50 हजार रुपये, सैन्ट्रल एक्सार्ज डिपार्टमेंट का 50 हजार रुपये, हरियाणा टूरिज्म का 30 हजार रुपये, एफ0सी0आई0 का 30 हजार रुपये, भारतीय खादय निगम का 2 लाख 50 हजार रुपये, हैफेड का 31 हजार रुपये, सहकारी बैंक का 1 लाख 70 हजार रुपये, दूरभाष तथा सचार केन्द्र का 2 लाख 50 हजार रुपये और इसी तरह से पजाब नै नल बैंक का भी काफी नुकसान हुआ था। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टे न भी वहा पर जलाया गया और म्यूनिसिपल कमेटी के ऑफिस को भी आग लगाई गई। इतना ही नहीं जो वहा से दिल्ली को पानी जाता है। उसमे भी साईफन डाल दिया गया। (विघ्न) वहा पर होम मिनिस्टर साहब दो बार गए थे। (विघ्न) यह जो कहा जा रहा है कि इस सरकार ने बहुत कल्याण कार्य किए है ठीक नहीं है। (विघ्न) अभी मेरे माननीय साथी श्री गोदारा जी ने कहा है कि सरकार ने किसानो का बडा भला किया है और चौधरी देवी लाल पापुलर हो रहे है। स्पीकर साहब, इस बात मे कोई भाक नहीं है कि चौधरी देवी लाल ने किसानो के लिए, आम आदमी के लिये बहुत काम किए है। मण्डल और कमण्डल की बात भी कही गई । इस बारे मे मै यह कहना चाहता हू कि वह कमण्डल नहीं बल्कि रथ यात्रा थी जो दे । को इक्ठठा करने के लिये और लोगो मे जागृति लाने के लिये की गई थी। रथ यात्रा गुजरात से भुरू हुई। विघ्न। वहा पर कुछ नहीं हुआ। गुजरात मे जनता दल का राज था और वहा पर बिल्कुल अमन रहा और हजारो लोगो ने रथ यात्रा का स्वागत किया था

और भाति के साथ सहयोग दिया। महाराष्ट्र के अन्दर कांग्रेस का राज है, रथा यात्रा जब महाराष्ट्र के अन्दर गई तो वहा पर भी कुछ नहीं हुआ। भाहरो और गावो के लाखो लोग ने रथ यात्रा का स्वागत किया। मध्यप्रदे ा मे और राजस्थान मे भी लाखो लोगो ने रथ यात्रा का स्वागत किया। (विघ्न)

**प्रो० सम्पत सिंह:** जयपुर मे 200 लोग मारे गये थे।

**श्री देवी दास:** यह रथ यात्रा के दौरान की बात नहीं है। एक हरियाणा स्टेट ही ऐसी रही जहा रथ यात्रा मे कुछ बाधा डालने की कोि ा ा की गई और रथ यात्रा के समय नारे बाजी की गई। जब यह रथ यात्रा दिल्ली के अन्दर से गुजरी तो वहा पर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं था। बिहान मे कुछ नहीं हुआ। (विघ्न) कहने काम मतलब यह है कि जहा जहा भी रथ यात्रा गई उसका स्वागत हुआ। (विघ्न) यह कमण्डल की बात नहीं थी बल्कि यह रथ यात्रा थी।

**श्री मनी राम:** स्पीकर साहब, मेरा प्वायट आफ आर्डर है?

**Mr. Speaker:** What is the point of order at this stage?

**श्री देवी दास:** अध्यक्ष महोदय, अब मै डिमाड नम्बर 8 पर आता हू। स्पीकर साहब, इस मद मे 570531000 रूपये खर्च करने का प्रोविजन है। अध्यक्ष महोदय, सोनीपत जिले के अन्दर

एक भी नई सडक नहीं बनाई गई और न ही किसी सडक की मुरम्मत की गई। स्पीकर साहब, कादियान साहब ने मूरथल से लेकर करनाल तक डबल सडक बनाने का जिकर किया था लेकिन अभी तक यह सडक बन नहीं सकी और इस काम बन्द पडा है। मैं चौधरी जगननाथ जी और माननीय मुख्यमंत्री साहब से यह जानना चाहूंगा कि सडक बन क्यों नहीं रही, इस को ठेकेदार कौन है, इस सडक को बीच में छोडने की क्या बैकग्राउड है? स्पीकर साहब, इस सडक के बनने से हमें बड़ी खुशी होगी। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस सडक को जल्दी ही बनाया जाए।

स्पीकर साहब, अब मैं डिमाड नम्बर 16 पर बोलना चाहूंगा। हमारी सरकार ने एक रूरल इण्डस्ट्रीच स्कीम बनाई थी जिस में यह कहा गया था कि सरकार कच्चा माल देगी और तैयार सामान भी खरीदगी। आज हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने यह स्कीम ऐडाप्ट की थी लेकिन उन्हें न तो कच्चा माल मिला और न ही उन द्वारा तैयार किए गए माल को खरीदा गया और न ही कोई अन्य सहायता उन्हें दी गई। रूरल स्कीम के अर्न्गत चल रहे उधोग आज ठप्प हो रहे हैं इसलिये सरकार से अनुरोध है कि वह इस और विशेष ध्यान दे और इन उधोगों को तबाह होने से बचाए।

**श्री अध्यक्ष:** अब आप वाईड अप करिये।

**श्री देवी दास:** स्पीकर साहब, अब मैं डिमाड नम्बर 11 पर बोलना चाहूंगा। सोनीपत के अन्दर और सारे हरियाणा के

अन्दर टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिक विभाग से जमीन ऐक्वायर करने के नोटिस आ जाते हैं। इसलिये लोग बहुत परे गान हैं। उसकी मियाद होती है कि इतने साल तक वह कन्ट्रोल एरिया रहेगा। फिर सैक्ट 4 का नोटिफिके गन होगा, फिर सैक्ट 6 का नोटिफिके गन होगा और फिर वह जमीन ऐक्वायर होती है। 15-15 साल तक कन्ट्रोल एरिया पडा हुआ है। गाव के गाव पडे हुए हैं जो भाहर के साथ लगते हैं और उनके सरकार कन्ट्रोल एरिया डिक्लेयर किया हुआ है। हमारे लोकल बौडीज के मिनिस्टर कहते हैं हम सोनीपत को कुछ नहीं दे सकते जबकि नगर की बहुत ही खराब हालत है तो मैं यह कहना चाहता हू कि लोग तीन किस्म के अदायतरो से परे गान हैं। एक तो हुडडा है दूसरा हाउसिंग बोर्ड है और तीसरा म्यूनिसिपल कमेटी है। तीनों के अलग अलग सीवरेज ओर तीनों के ही अलग अलग नक्शे बनवाये गये हैं। भाहर के बन्द की निकासी के लिये यह बहुत ही नुकसानदायक डालेंगे। हाउसिंग बोर्ड वाले यह कहते हैं कि हम अपने सीवरेज में डालने नहीं देंगे। नगरपालिका वाले अपने सीवरेज में डालने नहीं देते क्योंकि उनकी अपनी समस्या है। सरकार के तीनों डिपार्टमेंट यहा पर बैठे हुए हैं, मेरा कहना चहा है कि भाहर के अन्दर ऐसी समस्या है। इसको हल करना चाहिये। विशेषकर सोनीपत में जो ड्रेन न0 8 है उसके बारे में कई दफा सी0एम0 साहब ने कहा भी है कि वहा पर एक पुल बनायेगे। वहा पर सैक्टर 14 और 15 के बीच में एक पुल बनना है। वह फौरी

तौर पर बनना चाहिये ताकि सैक्टर 14 और 15 को भाहर के साथ मिलाया जा सके ।

अब मै मांग सख्या 9 जो िाक्षा के बारे मे है, पर आता हू ।

**श्री अध्यक्ष:** देवी दास जी, आप कन्क्ल्यूड करे ।

**श्री देवी दास:** मुझे तो अभी 6-7 मिनट ही हुए है ।

**श्री अध्यक्ष:** आपको 9 मिनट हो चुके है । आप अब जल्दी खत्म करे ।

**श्री देवी दास:** मै एक दो मिनट से खत्म कर देता हू । सोनीपत के अन्दर एक गोहान गाव है । वहा के स्कूल की हालत बहुत खराब है । कई दफा डी0जी0ओ0 ने ऐजूके िन डिपार्टमेंट की लिखा हुआ है कि वहा पर बच्चो की जिन्दगी खतरे मे है । मेरे साथी कृशि मंत्री श्री कि िन सिंह जी सागवान यहा पर बैठे हुए है और ऐजूके िन डिपार्टमेंट के औफिसर्ज भी यहा पर बैठे हुए है । मेरी प्रार्थना है कि इसकी और ध्यान दिया जाये । स्पीकर साहब, अब तो िाक्षा राज्य मंत्री बरवाला जी भी आ गये है । मै इनसे अर्ज करूगा कि आठवी की किताबे तो सरकार छापती है लेकिन 10वी किताबे ऐजूके िन बोर्ड छापता है । किताब बनाता ऐजूके िन बोर्ड और सरकार है और उनको सरकार प्रैस से छपाते है । वहा पर इतनी देरी हो जाती है कि प्राईवट लोग किताबो को छाप कर मार्किट मे लाकर ब्लैक करते है । ये दोनो डिपार्टमेंट ही

सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं। इसके लिये कोई न कोई बोर्ड बनाना चाहिये ताकि आठवीं और मैट्रिक की कितनी ठीक समय पर छप सके। बेनाक इनको एक बोर्ड ही छापे। मैं सरकार से यह कहूंगा कि इसकी तरफ भी पूरा ध्यान देना चाहिए।

अब मैं मांगा सख्या 12 के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। सोनीपत एक इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण वहाँ पर लेंबर की बड़ी प्रॉब्लम है। फैक्ट्रियों के मलिक मजदूरों को बिना किसी कारण के निकाल देते हैं। (व्यवधान व भाँवर).....

**Mr. Speaker:** Will up please.

**श्री देवी दास:** गरीब आदमी लेबल ऑफिस में घूमते रहते हैं। उनका टाइम जाया होता है मेरा कहना यह है कि इनका फैसला डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर होता चाहिये ताकि मजदूरों को तकलीफ न हो। धन्यवाद।

**श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू):** स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, इसके लिये धन्यवाद। यह बजट के अनुदानों की मांगों पर चर्चा हो रही है। मैं आपका ध्यान विशेष रूप से मांगा सख्या 2,3,7,17,23,5 और 21की और दिलाते हुए इन पर अपने विचार रखूंगा। अध्यक्ष महोदय, एक बात तो यह है कि मैं सबसे पहले वित्त मंत्री महोदय का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस तथ्य को सबके सामने रखा है कि पहले 240 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करने की बात कहते थे, वह केवल 41 करोड़ रुपया

है। इस तरह से सच्चाई हाउस के सामने और जनता के सामने आ गई है। इसके लिए इनका धन्यवाद। स्पीकर साहब, दूसरी बात यह है कि कृषि के जितने भी उपकरण हैं दूसरे प्रान्तों में उन पर सेल्ज टैक्स माफ है। हरियाणा सरकार स्प्रिक्लर सैटस पर चार हजार रूपया सबसिडी के तौर पर किसान को देती है। उस सबसिडी को लेने देने में अधिकारियों/कर्मचारियों, बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों और किसान के बीच काफी गडगड होती है और उका नतीजा यह होता है कि जो किसान को लाभ होना चाहिए वह खत्म हो जाता है। सबसिडी देकर किसान को जो लाभ पहुंचाने की सरकार की मं ता है, उसका लाभ किसान को नहीं मिलता। इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार इस बारे में दुबारा विचार करे। सरकार जो चार हजार रूपया सबसिडी दे रही है यह अच्छी बात है लेकिन जितना फायदा किसान को पहुंचना चाहिए वह नहीं पहुंचता। स्पीकर साहब, 1983 में कृषि के सम्बन्ध में अल्यूमीनियम के जो भी उपकरण हैं उन पर भारत सरकार ने ऐस्साइज ड्यूटी माफ कर दी थी। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह भी इस विषय में और खासतौर पर स्प्रिक्लर सैटस पर सेल्ज टैक्स माफ कर दे तो अच्छा रहेगी। स्पीकर साहब, अगर हरियाणा सरकार माफ करेगी तो उसका नतीजा यह होगा कि कुछ उद्योगपति जिन्होंने यू0पी0 में या दूसरे प्रान्तों में व्यापार कर रखा है वे किसानों के नाम से सीधे ये उपकरण ले आएंगे और यहां बेचेंगे। यहां वे व्यपारी ज्यादा सेल्ज टैक्स वसूल करेंगे। इससे किसान को कोई लाभ नहीं होगा और व्यपारी ज्यादा कमा जाएगा

तथा फेयर कम्पीटी इन भी नहीं होगा। इसलिए सैल्ज टैक्स माफ जरूरी है। स्पीकर साहब, हमारा प्रदेश अप कृषि प्रधान प्रदेश है। चौधरी देवी लाल ने 1988 में घोषणा की थी कि हम कृषि उपकरणों पर से सैल्ज टैक्स माफ करेंगे। 1983 में भारत सरकार ने ऐल्यूमीनियम पाइप्स पर से ऐक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी थी और दूसरी प्रोडक्ट्स पर केवल 45 प्रतिशत ड्यूटी रखी थी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार भारत सरकार की बात न माने तो चौधरी देवी लाल की बात तो माने जिसकी उन्होंने 1988 में घोषणा की थी। उन्होंने तो सारे टैक्स माफ करने की बात की थी लेकिन यह सरकार उनकी भी बात नहीं मान रही है।

स्पीकर साहब, सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिये हरियाणा सरकार ने जो पैसा रखा था वह 2900 करोड़ था लेकिन वह बाद में 2500 करोड़ रह गया। मेरा कहना यह है कि ज्यादातर पैसा नौन प्लान स्कीम के लिए पर ज्यादा खर्च होने के कारण जितनी तरक्की होनी चाहिए उतनी तरक्की नहीं होती। अगर ऐसा ही होता रहा तो मैं समझता हूँ कि तरक्की कम होती चली जाएगी। स्पीकर साहब, 1991-92 का जो बजट अनुमान रखा है वह 765 करोड़ रूपए का है। मैं समझता हूँ कि अगर महगाई इसी हिसाब से बढ़ती रही तो साल के अन्त में 572 करोड़ रूपए का ही रह जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं सरकार का विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जब भी यहां पर कोई बात आती है

तो विशेष रूप से पुलिस के बारे में आका उठती रहती है। अध्यक्ष महोदय आज से एक सौ तीस वर्ष पहले पुलिस कानून बना था और उस समय सामाजिक परिस्थितियों आर्थिक परिस्थितियों और पुलिस के काम धंधे की व्यवस्था भिन्न थी। एक सौ तीस साल में देश की और प्रदेश की परिस्थितियों बदली है। उनके काम करने का जो तरीका था, जो परिस्थितियों थी वे बदली है। इसलिये इस आधुनिकीकरण के समय में केवल उनकी संख्या बढ़ाने से काम चलने वाला नहीं है। जब तक कि उनको ठीक प्रकार से ट्रेनिंग नहीं दी जाए और ठीक प्रकार से उनको साधन उपलब्ध नहीं करवाये जाए जब तक उन्हें साइकलोजिकली, ठीक प्रकार से बताया जाए कि किस तरीके से लोगों से व्यवहार करना है तब तक पुलिस में जागरूकता नहीं आएगी। जब तक हम पुलिस रूलज को नहीं बदलेंगे, उस समय तक पुलिस का जो सालों साल से दुरुपयोग हो रहा है उसमें और बढ़ाव होगी और अगर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा तो एक दिन प्रजातन्त्र के लिये खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिये सरकार को इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, 1979-80 में श्री धर्मबीर जी पंजाब के राज्यपाल थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बैठा था। केन्द्रीय स्तर पर उन्होंने विभिन्न प्रान्तों से अपने अपने विचार इस बारे में मांगे थे। हमने अपने विचार प्रस्तुत किये थे। जो जो सुझाव हम लोगों ने दिये थे हो सकता है उनमें से एक आध बात मानी जा चुकी हो लेकिन फिर भी पुलिस वालों के आवास के लिये, रहन

सहन के लिये, दूसरी सहूलियतो के लिए एक कमेटी बनाई जानी चाहिये जो यह देखे कि आज जो पुलिस का राजनीतिकरण हुआ है और अब राजनीतिकरण अपराधीकरण में बदल गया है इसके कारण क्या है? अगर इन सभी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो प्रजातन्त्र के लिये बड़ा भारी खतरा पैदा होगा और लोगों के लिये भी दुखदायी होगा। इसलिये सरकार को इस ओर सतर्कता से सोचना चाहिए। इसी प्रकार से अखबार वालों के बारे में भी सरकार को कुछ भाकाए थी, उन से गिला था तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि प्रजातन्त्र के अन्दर प्रैस चाहे किसी प्रदेश की हो उनके विचार की स्वतन्त्रता निहायत ही जरूरी है। इसके लिए पिछले दिनों बार बार यह सुना गया था कि प्रैस वालों पर सरकार ने झूठे मुकदमों बनाये हैं और वहाँ भिन्न भिन्न सस्थाओं ने सगठन के रूप से सगठित होकर दिल्ली में धरना भी दिया है जिसका जिकर अखबारों में भी आया है। इनकी एक सस्था एल०एम०एम० नाम से जानी जाती है जिसको लोग लूट मार सघ के नाम से भी जानते हैं उन्होंने प्रैस पर हमला किया और वहाँ काम काज बिल्कुल ठप्प हो गया। यह एल०एम०एम० जो सस्था है वह जनता एस से संबधित हैं और इन सब घटनाओं के पीछे राजनीतिक हाथ अब यहाँ है और ऐसे जो व्यक्ति इस देश में प्रदेश में भासक व प्रशासक बने बैठे हैं जो कि यह सारे काम करवा रहे हैं ऐसे व्यक्तियों से जब तक ठीक प्रकार से निपटा नहीं जाएगा तब तक यह प्रदेश के लिये, देश के लिये व प्रजातन्त्र व लोगों की प्रैस

की आजादी के लिये खतरा ही पैदा करते रहेगे। इसलिये सरकार को इन बातों का कोई न कोई हल अवय निकालना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, इससे आगे मैं यह कहूँगी कि हमारी सरकार ने पिछले सालों में काफी प्रगति की है और प्रगति विशेष रूप से एक बात में तो अवय की है औरों की मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी के दामाद को हिसार में डिसटिलरी के लिए मोलैसिज का काटा 1/1/4 लाख की कैपैसिटी से बढ़ाकर पिछले तीन सालों के दौरान 3 लाख टन कर दिया है। यह एक प्रगति का कार्य अवय इस सरकार ने किया है। इस के खिलाफ हमने चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व वाली केन्द्रीय सरकार को और फिर श्री राजीव गांधी जी को एक मांग पत्र भी दिया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको क्या बताऊँ। आप आज अगर हिसार की उस सड़क पर जाएँ पर वह फैक्टरी लगी हुई है तो वहाँ खड़े नहीं हो सकोगे। लोगों का उस जगह पर आना जाना बड़ा दूभर है। लोगों का उस जगह पर रहना हराम है और उस फैक्टरी के पोल्यूशन के कारण लोग उनके बीमारियों के शिकार हुए पड़े हैं। उस फैक्टरी का मोलैसिज का जो कोटा बढ़ाया गया है, क्या इस हिस्सेदारी में भी कहीं सरकार इवाल्ड तो नहीं है या कोई और कारण तो नहीं है? इसका स्पष्टीकरण सरकार करे वरना इस सरकार के प्रति भाकाए स्वाभाविक तौर पर बढ़ेगी। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हम स्वच्छ प्रशासन की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह

से स्टेट के अन्दर भाराब बनाने को बढाव दे रहे है। महात्मा गांधी जी ने भी भाराब के खिलाफ बहुत कुछ कहा है लेकिन ये लोग अपने आपको गांधीवादी कहते हुए भी इस ओर ज्यादा उदारता का सबूत दे रहे है।

इससे अगली बात मै ऊन मिल के बारे मे कहना चाहता हू जो कि लोहारू के अन्दर लगाई जानी थी। पिछले दिनों जब चौधरी औमप्रका । चौटाला मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वहा पर इस सम्बन्ध मे घोशणा की थी उसके बाद श्री बनारसीदास गुप्ता आये। धीरपाल जी भी सहकारिता मंत्री थे। गुप्ता जी की अध्यक्षता मे लोहारू के अन्दर इस ऊन मिल का िालान्यास किया गया था लेकिन आज सरकार किन्ही कारणो से टाल मटोल कर रही है। इतना कहने के बाद और चौधरी देवी लाल जी की घोशण के बाद भी वह काम सिरे नही चढ पाया। उसके िालान्यास पर 70-80 हजार रुपए का खर्च हुआ था। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी जब डिवैलप्मेंट मिनिस्टर हुआ करते थे उस वक्त इन्होने अपने विभाग के संबध मे एक चिटठी लिखी थी कि पचायती की जमीन पर कुछ प्रभाव ाली व्यक्तियो ने कब्जा कर रखा है। कल जब एक सवाल आया तो उसके जवाब मे कहा गा कि नाजायज कब्जा करने मे श्री औमप्रका । चौटाला का नाम नही है। तो हम जानते चाहते है कि ऐसे प्रभाव ाली आदमी कौन है? अगर कोई और आदमी इनके सरक्षण मे हो तो उसके नाम हमे बता दे। ( गोर)

श्री अध्यक्ष: आर्य जी अब आप बैठे। अब श्री हरपाल सिंह जी बोलेंगे।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा।

**Mr. Speaker:** Please take your seat now. I have already called upon Shri Harpal Singh. Nothing more will be recorded, If Arya Ji Says something now.

कामरेड हरपाल सिंह (टोहाना): स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत भुक्तिआ कि आपने मुझे बजट की डिमाडज पर बोलने का समय दिया। सब से पहले मैं लेबल एंड एम्पलायमेंट की डिमाड न0 12 पर बोलना चाहूंगा। इसके लिए इन्होंने 212064000 रूपये का खर्चा मांगा है। इसमें इडस्ट्रियल रिले ाज के लिए 75.31 हजार रूपये है वर्किंग कडी ान एंड सेफटी के लिए 31.74 हजार रूपये है और जनरल लेबल वैलफेयर के लिये 6.99 हजार रूपये है। दूसरर तरफ सो ाल सिक्क्योरिटी फार लेबर के लिए कुछ भी नहीं है, रिहैबलीटे ान आफ बौडिड लेबर के लिए कुछ नहीं है। और असिसटैस टू अर्बन पूअर के लिए भी कुछ नहीं है। कल जब बजट पर चर्चा चल रही थी तो हमारी सरकार का दावा था कि 71 प्रति ात बजट ग्रामीण विकास पर खर्च होगा। लेकिन असिसटैस टू रुरल पूअर के लिए कोई पैसा नहीं है और चाइल्ड लेबर की वैलफेयर के लिए कोई पैसा नहीं रखा गया है। मैंने एक कामल अटैन् ान मो ान दिया था कि 25 हजार भट्ठा मजदूर हडताल

पर है। भट्टा मालिको ने उन पर हमला किया लेकिन हमारे मजदूर श्रम विभाग में कुछ नहीं किया। इसलिये मैं इस श्रम विभाग को अगर बे र्म विभाग कहू तो कोई गलत न होगा। मजदूरों के केस कई कई सालों से पैडिंग पड़े हैं। इनके अफसर हमें आ भट्टा मालिको की हिमायत करते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से दरखास्त करूंगा कि वे इस विभाग को चुस्त करे ताकि मजदूरी की वर्किंग कंडी ान सुधर सके।

अब मैं डिमांड न० 14 जो फूड एण्ड सप्लाइज के बारे में है पर कुछ कहना चाहूंगा। गोदारा साहब कह रहे थे कि लोगों को बहुत ज्यादा अनाज अलाट किया गया। यह बड़ी खु ि की बात है और मैं सरकार को बधाई देता हू। लेकिन सरकार एक बात बताए कि वह अनाज रास्ते में कहा ब्लॉक हो गया? सरकार इस बात की इन्कवायरी करवा कर दोशियों को सजा दे। वह अनाज लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा। मैं फूड एण्ड सप्लाइज विभाग से संबंधित डिमांड पर बोलते हुए यह कहना चाहूंगा कि जो रोजमर्रा की चीजे हैं जैसे साबुन, तेल, मिर्च मसाले और सूती कपडा बगैरहा इनको उचित तथा सस्ते दामों पर बेचने के लिए नीचे स्तर तक गावों में सरकार दुकानें खोली जाए ताकि देहात के गरीब लोगों को रोजमर्रा की चीजे उचित और सस्ते दामों पर मिल सके। सरकार की तरफ से एक परिवार एक रोजगार की बात कही गई है। यानी यह सरकार एक परिवार के एक बेरोजगार को रोजगार देगी। यह सरकार एक परिवार एक रोजगार की बात तो

करती है हमें यह बताए कि सभी परिवारों के एक एक बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बजट में कितने पैसे का प्रावधान किया गया है ?

डिमांड न० 16 विलेज इंडस्ट्रीज और स्माल स्कैल इंडस्ट्रीज से संबंधित है। इस डिमांड में बताया गया है कि सरकार लगभग 9 करोड़ रुपये स्माल स्कैल इंडस्ट्रीज पर खर्च करेगी। इस डिमांड में टोटल 13 करोड़ रुपये के लगभग प्रावधान किया गया है जिसके अन्दर विलेज इंडस्ट्रीज, स्माल इंडस्ट्रीज, हैडलूम एंड हैडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। हैडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज के लिये तो केवल 56 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है और डायरैक्ट एंड ऐडमिनिस्ट्रेटिव के लिए 1 करोड़ 92 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। लेबर एंड एम्प्लायमेंट के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मेरी समझ में नहीं आया कि इतने थोड़े पैसे में वह सरकार किस किस बेरोजगार को रोजगार दे पाएगी। इसके अलावा सरकार यह भी कहती है कि उन सभी बेरोजगारों को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती परन्तु हम एक परिवार के एक बेरोजगार को रोजगार के साधन जरूर उपलब्ध कराएंगे। इस सरकार ने लेबर एंड एम्प्लायमेंट के लिए 5 करोड़ 71 लाख रुपये के लगभग प्रावधान किया है और सरकार यह भी कहती है कि हरियाणा में डेढ़ लाख परिवार हैं जिनके एक एक बेरोजगार को रोजगार देना है। इतने कम पैसे में यह सरकार किस किस बेरोजगार को रोजगार दे पाएगी। मुझे तो इस सरकार

की ईमानदारी पर भाक होता है इतने कम पैसे के प्रावधान से हरियाणा प्रान्त के सभी परिवारो के एक एक बेरोजगार को रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं कराए जा सकते । एक तरफ तो यह सरकार कहती है कि सभी परिवारो के एक एक बेरोजगार को रोजगार दिया जाएगा और दूसरी तरफ इस सरकार ने लेबर एण्ड एम्प्लायमैट के लिए केवल 5 करोड 71 लाख रूपए के लगभग प्रावधान किया है । तो यह सरकार सभी परिवारो के एक एक बेरोजगार को नौकरी कैसे दे पाएगी? सरकार इसके लिये ज्यादा से ज्यादा पैसे का प्रावधान करती ताकि सभी परिवारो के एक एक बेरोजगार को रोजगार के साधन जुटाए जा सकते ।

डिमांड न0 10 पब्लिक हैल्थ विभाग से संबधित है । इस डिमांड के बारे मे बोलते हुए मै कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने इसमे 57 करोड 51 हजार रूपये के लगभग वाटर सप्लाई स्कीम तथा सेनीटे ान के लिए प्रावधान किया है । जिसमे से डायरैक् ान एण्ड एडमिनिस्ट्रे ान के लिए 22 करोड 68 लाख रूपए के लगभग प्रावधान किया गया है अबैन वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 1 करोड 60 लाख रूपए के लगभग प्रावधान किया है और रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 1990-91 मे 34 करोड 50 लाख रूपए का प्रवधान किया गया था लेकिन वर्ष 1991-92 के लिए 26 करोड 60 लाख का प्रावधान किया गया है । एक तरफ तो हरियाणा प्रान्त के हर गांव को पीने का पानी मुहैया करने का दावा करती है और दूसरी तरफ इस साल पिछले साल से कम पैसे का इस स्कीम के

लिए प्रावधान किया है। मेरी समझ में नहीं आता कि वह सरकार इतने कम पैसे से हरियाणा प्रान्त के हर गांव को किस तरीके से पीने का पानी मुहैया कराएगी। अर्बन डिवैल्पमेंट के नाम जिस तरीके से म्यूनिसिपल कमेटीज को ग्रांट बांटी गई उसके बारे में तो आपको पता ही है स्पीकर साहब, एक दिन पहले बोलते हुए भी मैंने यह सवाल किया था और आज फिर कह रहा हूँ कि गांवों के जो लोग भूमिहीन हो चुके हैं वे लोग रोजगार की तलाश में भाहरो के अन्दर आ गये हैं। जो पहले गांवों के अन्दर कारीगर का काम करते थे या मजदूरी करते थे वह रोजगार के लिए भाहरो में आ कर छोटी छोटी बस्तियों में बस गए हैं। उन लोगों की बहुत बुरी हालत है। न उनको पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है, न उनके पास रहने के मकान उपलब्ध हैं, न उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल का प्रबंध है यानि उनको जिन्दगी की जरूरियात की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। पता नहीं फिर यह सरकार म्यूनिसिपल कमेटीज को इतनी कम ग्रांट दे कर अर्बन डिवैल्पमेंट की बात कैसे करती है। मुझे तो सरकार की यह बात थोथली नजर आती है। टोहाना एक छोटा सा कस्बा है, भूना एक छोटा सा कस्बा है उन कस्बों में जो बस्तियां हैं उन बस्तियों के लोगों को पीने के पानी की बहुत कीम है। पीने के पानी के लिए उन बस्तियों के लोगों को आपस में झगड़े होते हैं। ऐसे बस्तियों में रहने वाले भी इस देश के नागरिक हैं। इस प्रदेश के नागरिक हैं। किसी भी सरकार के नागरिक हो उनको जिन्दा रहने के लिए पानी बहुत ही जरूरी है। इसलिए उनको सरकार द्वारा पीने का

पानी जरूर मुहैया कराया जाना चाहिए। न उन लोगों के लिए रोजगार के कोई साधन हैं न उनके रहने के लिए मकान हैं न उनको पीने के लिए पानी उपलब्ध है। क्या सरकार ऐसी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए इन सभी चीजों का इन्तजाम कर पाएगी? स्पीकर साहब, अगले साल के लिए सेनीटे इन के लिए एक पैसे का भी प्रावधान नहीं किया गया है। सिवरेज सर्विस के लिए 2 करोड़ 95 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। मैं इस सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या म्यूनििसिपल कमिटीज इतने कम पैसे में सिवरेज कवर कर पाएगी।

स्पीकर साहब, अब मैं डिमांड न० 8 पर बोलना चाहता हूँ इस डिमांड के तहत कैपिटल ऐक्सपैन्डिचर के लिए 53 करोड़ 43 लाख 67 हजार रुपये मागे गए हैं। इनमें से डायरेक्ट इन एण्ड ऐडमिनिस्ट्रेटिव इन पर 3 करोड़ 65 लाख 79 हजार रुपये खर्च होंगे। कन्स्ट्रक्शन इन के लिए 36 लाख 20 हजार रुपये रखे गये हैं। मीनरी एण्ड एक्वूपमेंट के लिए 2 करोड़ 15 लाख रुपये रखे गये हैं। मेन्टीनेंस के लिए 3 करोड़ 20 हजार रुपये रखे गये हैं। स्पीकर साहब, एक तरफ तो सरकार विकास का दावा करती है और दूसरी तरफ विकास नाम की कोई चीज यह नहीं कर रही। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1990-91 में तो मेन्टीनेंस और रिपेयर के लिए 5 करोड़ 79 लाख रुपये के करीब रखे गए हैं जबकि अगले इस काम के लिए 1991-92 में सिर्फ 3 करोड़ 20 लाख रुपये ही रखे गये हैं। यानि इस काम के लिए उल्टे 2 करोड़ रुपये कम

रखे गये है। इसी प्रकार से पुल वगैरा बनाने के लिए 1990-91 में तो 21 करोड़ रुपये रखे गये जबकि अब 1991-92 के लिए 19 करोड़ 27 लाख रुपये रखे गये है यानि इस के लिये भी पिछले साल के मुकाबले 2 करोड़ कम रखे गये है। इस बात का सभी को पता है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल काफी महगाई बढ़ चुकी है इन्होंने ज्यादा पैसा रखने की बजाये कम कर दिया है। इससे ही पता चलता है कि ये क्या विकास कर पाएंगे? स्पीकर साहब, किसी भी प्रदेश में ट्रांसपोर्ट को कोई सुविधा दी जानी होती है तो सबसे पहले उस प्रदेश में सड़कें बनानी होती है और जो पुल बीच में पड़ते हैं वे बनाने होते हैं। इसके अलावा जो पुरानी सड़कें खराब हालत में हों उन्हें ठीक कराया जाता है।

**अध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नं० 2 पर बोलना चाहता हूँ।** सरकार इस मांग के तहत पब्लिसिटी के लिए बहुत अधिक पैसा रखा है। सरकार ने अपनी पब्लिसिटी कराने के लिए 5 करोड़ 51 लाख 87 हजार रुपये रखे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि पब्लिसिटी के लिए इतना अधिक पैसा रखने की क्या जरूरत थी? इस बारे में मेरा सरकार को सुझाव है कि पब्लिसिटी पर ज्यादा पैसा खर्च करने की बजाये अगर विकास पर यह पैसा खर्च किया जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

**श्री अध्यक्ष:** अब आप बैठिये। अब श्री मनीराम जी बोलेंगे।

**श्री सूरज भान:** स्पीकर साहब, जब 6 तारीख को भागमल जी बोलने के लिये खड़े हुये थे तो आप ने कहा था कि बजट पर बोल लेना। लेकिन इनको समय अभाव के कारण बजट पर भी बोलने का मौका नहीं मिल पाया। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन्हे भी 10 मिनट का समय दे दे।

**श्री अध्यक्ष:** 10 मिनट का समय तो नहीं दिया जा सकता, हां पाच मिनट का समय दिया जाता सकता है। अब श्री मनीराम जी बोलेगे उसके बाद भागमल जी बोलेगे।

**श्री मनीराम (डबवाली, अनुसूचित जाति):** स्पीकर साहब, मे डिमाड न0 10,12,13,16,17,22,19 और 10 पर बोलना चाहूंगा। स्पीकर साहब, आपको भी और सभी साथियो को भी पता है कि हरियणा प्रदे 1 एक कृशि प्रधान प्रदे 1 है। 1977 मे जब चौधरी देवी लाल जी के नेतृत्व मे पहल बार गैर काग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो उन्होने किसानो की सुविधाआ के लिए बहुत काम किए थे। जब इससे पहले काग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उसने किसानो के लिये कुछ नहीं किया था। अब हाउस मै चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह और कैप्टन अजय सिंह, जिन्हे हम सीनियर हवलदार कहते है वे बैठे नहीं है अब मै उन्हे बताता कि चौधरी देवी लाल जी किसानो के लिए क्या क्या काम किये। स्पीकर साहब, मै बताना चाहता हू कि हमारी सरकार ने दे 1 मे सबसे पहले किसानो को औलावृशिट से हुए नुकसान का मुआवजा 400 रूपये पर एकड के हिसाब से दिया है। इसी तरह से सडक के साथ

साथ किसानों के जो पेट हैं उनमें भी आधा हिस्सा उनको दिया गया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जितनी हमदर्द यह सरकार किसानों की है उतनी कांग्रेस कभी नहीं रही। सरकार के नोटिस में मैं एक बात लाना चाहता हूँ कि 84 करोड़ 97 लाख रुपये जो कृषि के लिये रखे गये हैं ये बहुत ही कम हैं। मैं चाहूँगा कि इस राशि को बढ़ाया जाये। अब जो मौजूदा सरकार है वह अपने किसानों को अच्छे बीज देती है और खाद पर भी सबसिडी देती है। किसानों की भी जो मांगें होती हैं उनको पूरा करने की कोशिश की जाती है।

अध्यक्ष महोदय, जब से प्रो० सम्पत सिंह जो आई०पी०एम० बने हैं तब से किसानों को पूरी बिजली और पूरा पानी मिल रहा है। हमारी सरकार ने रजवाही को और नहरों को भी पक्का करना शुरू कर रखा है। खालों को भी पक्का किया जा रहा है। यदि इनको पक्का न किया जाए तो टेल पर पानी नहीं पहुँच पाता। अगर रजबाहे पक्के हों, खाली पक्की हों तो पानी अधिक से अधिक मात्रा में टेल पर जाता है। इसके साथ ही किसानों की सुविधा के लिए एक्सीशन कम से कम 15 दिन में एक बार जा कर देखता है कि काम ठीक प्रकार से चल रहा है या नहीं। अगर किसानों को बिजली और पानी ठीक मिलता है तो खेतों में अच्छी फसल होगी अच्छा बीज किसान को मिले तो पैदावार ज्यादा होगी, फसल ज्यादा होगी तो किसान को भाव

अच्छा मिलेगा। अच्छा भाव मिलने से किसान खुश होगा और यदि किसान खुश होगा तो प्रदेश भी खुश होगा।

स्पीकर साहब, अब मैं शिक्षा के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। चौधरी देवी लाल की सरकार आने से पहले हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश था जहाँ लड़कियों को पढ़ाना उचित नहीं समझा जाता था। चौधरी देवी लाल की सरकार ने लड़कियों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। आज सारे हरियाणा में कोई ऐसा गाँव नहीं है जहाँ लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था न हो। हमारी सरकार हर साल 100 से लेकर 500 तक स्कूल नये बनाती है। इसके अतिरिक्त प्राइमरी स्कूलों को मिडल स्कूलों, मिडल स्कूलों को हाई स्कूलों में अपग्रेड भी किया जाता है। अगर देश और प्रदेश के लोग पढ़े लिखे होंगे तो प्रदेश और देश की प्रगति होगी। माता का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर माता पढ़ी लिखी होगी तो वह अपने बच्चों को अधिक तरह से पालेगी। बच्चे घर से पहली ट्रेनिंग लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के एक पौली क्लिनिक बनाया जाना है। इसके लिये जमीन भी दे दी है लेकिन अभी तक इस पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। इस पोलिक्लिनिक के खुल जाने से गाँव चौटाला और उसके आस पास के कई गाँवों को लाभ होगा इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूँगा कि इसको जल्दी से जल्दी खोला जाए। स्पीकर साहब, अब मैं श्रमिक वर्ग को दी जाने वाली मजदूरी के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूँ। जब चौधरी

देवी लाल की सरकार सत्ता में आई तो एक मजदूर को 7 रुपये प्रति दिन मजदूरी मिलती थी लेकिन उसके बाद इसे बढ़ा कर 19.25 रुपये किया गया। इस वक्त हरियाणा में एक साधारण मजदूर को 31.40 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलती है जो कि भारतवर्ष में पंजाब को छोड़ कर और किसी प्रान्त में नहीं है। आज राजस्थान और मध्यप्रदेश में मजदूर को प्रतिदिन कितनी मजदूरी मिलती है यह मेरे बीजेपी के साथियों को मालूम ही होगा। ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा भी हरियाणा सरकार ने दिया है। राजस्थान के किसान मुआवजे के लिए मुख्यमंत्री श्री भैरो सिंह भोखावत से मिलने गए और उन्हें मुआवजे देने के लिए कहा तो भैरो सिंह भोखावत ने कहा कि फसल पर किसान का खर्चा क्या आता है मुटठी भर बाजरा लगता है उसके लिए क्या मुआवजा दिया जाए। (विधन)

**श्री राम बिलास भार्मा:** चौधरी मनी राम जी आप की सरकार ने पिछले 4 साल के दौरान कितने कर्जे माफ किए हैं यह तो आपको भी मालूम ही है। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने 11 महीने के भासन में 664 करोड़ रुपये के कर्जे लोगों के माफ किए हैं।

### **13.00 बजे**

**श्री मनी राम:** स्पीकर साहब, गावों के अन्दर चौपाले बनायी गयी, बेरोजगारी भत्ता दिया गया। आठवी पास को 50

रूपये, मैट्रिक पास को 75 रूपये और बी0ए0 पस को 100 रूपये बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। (घटी) स्पीकर साहब, आपका आदे 1 मानते हुए तथा धन्यवाद करते हुए इतना कह कर ही मैं अपना स्थान लेता हू।

**श्री भाग मल (सढौरा अनुसूचित जाति):** स्पीकर साहब, मेरे हल्के मे आपको यह तो पता है कि बरसात ज्यादा होती है लेकिन पानी वहा पर ठहरता नही है न वहा पर कोई नहर है और न ही ट्यूबवैल्ज है। अगर बारि 1 हो गयी तो थोडे बहुत दाने हो जाते है। अगर बारि 1 न हो तो वहा पर सारे ही इलाके मे सुखा पड जाता है। ऐसी हालत मे वहा पर जमीन भी थोडी पडती है। जो जमीन है भी, उसमे जगलात लगे हुए है। जगलात मे से पेड काटने की इजाजत नही है। दूसरे तरीके से, वहासे चोरी से जंगलात जरूर काटे जा रहे है। वह डिपार्टमेंट की मिली भगत से काटे जा रहे है इसकी कोई इक्वायरी नही होती। मेरी एक प्रार्थना है। मेरे हल्के से सूरजमुखी के पौधे की बहुत खेती होती थी। पिछली बार वहा पर 40 रूपये पैकेट के हिसाब से वह बीज मिल रहा था। अब की बार सारे अम्बाला और यमुनानगर मे बीज के लिये लोग तरस रहे है। हमारे यहा वैसे तो खाने के तेलो की कमी है। लेकिन जब किसान यह बीज बोना चाहता है तो उसको बीज ही नही मिलता। मेरी किसानो की इस सरकार ने यह प्रार्थना है कि इस बीज का कोई न कोई जरूर तुरन्त इंतजाम करे क्योकि मैने सुना है कि अगर किसी को चाहिये तो यह 40 रूपये का एक

पैकेट ब्लैक मे 300 रूपये मे मिल रहा है। यह भी देखना चाहिए तो यह जो बीच डिपार्टमेंट के पास आया था, वह कहा गया, किस को बेचा गया चोरी से किसी एक आधा को तो नही दे दिया गया। इस बात की पूरी इंकवायरी होनी चाहिये, कि वह बीज कहा गया। कितना बीज आया था, किस किस को सप्लाई हुआ है। स्पीकर साहब, मेरा हल्का एक पिछडा हुआ इलाका है। नारायणगढ से लेकिन ठीकरपुरा गांव तक सिर्फ एक हाई स्कूल है। उसके आप पास 20 किलोमीटर तक कोई दूसरा हाई स्कूल नही है। नारायणगढ से लेकर भाहपुर तक कोई हाई स्कूल नही है। बच्चो को 20-20 किलोमीटर तक जाना पडता है। पिछले दिनों एक प्रोपोजल एजूके इन डिपार्टमेंट को दी थी। हमारे लोग एजूके इन मिनिस्टर साहब से मिले थे। मेरी प्रार्थना है कि नगला राजपूतान, मारवा कलां और मछरौली के स्कूलो को अपग्रेड किया जाये। नगला राजपूतान का स्कूल मिडल से हाई स्कूल बनाया जाये। दूसरा मारवा कला और मछरौली के नजदीक कोई हाई स्कूल नही है। दो सौ अठाई सौ बच्चो रोजाना उन स्कूलो के लिए बसो मे जाते है। उनको बस भी नही मिलती। बडी तकलीफ है। 8-10 किलोमीटर दूरी तक कोई हाई स्कूल नही है। हमारा इलाका एक पिछडा हुआ इलाका है। इसमे बहुत सी जगहो पर सडके नही है। पुल नही बने हुए है। मेरी मांग यह है कि एक पुल तो संगरानी गाव के नजदीक है तो अव य बनाना चाहिये। वहा पर 1978 मे यह पुल बनना भुरू हुआ था। बीच मे बरसाता हो गयी। दोनो तरफ की दीवरो बन गयी थी। एक तरफ की दीवार बह गयी। एक

तरफ की दीवार अब भी खडी है। एक तरफ बडी तगडा गांव है। वहा पर बरसात के दिनो मे काफी पानी आ जाता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि उस पुल को जल्दी से जल्दी कम्पलीट किया जाये ताकि लोगो को सुविधा हो सके। वहा के लोगो को तरफ से यहा पर बार बार अनुरोध किया गया है कि वहा पर पुल भीघ्र अति भीघ्र बनाव जाए। वहा पर दो अढाई लाख रूपये का खर्च होना है। अगर वहा पर कोई डूब जायेगा तो हमारे लोगो का नुकसान हो जायेगा। उनकी बहुत सी प्रौपर्टी का तो नुकसान हो ही रहा है। एक दूसरा पुल सढौरा नदी का एक पुल था। उसका ऐस्टीमेट आया था। चौधरी देवी ला जब इलैक् इन के समय मे सढौरा गये थे तो उस समय उनसे बात हुई थी। उनको यह बतायया गया था कि इस पुल के न होने की वजह से लोगो को काफी परे ानी है। उस समय उन्होने यह कहा था, ठीक है, इसको बनायेगे। वह मुख्यमंत्री बनने के बाद केन्द्र मे भी पहुच गये लेकिन आज तक वहां पर पुल नहीं बन पाया है। इस पुल के बनने से 25-30 गावो को फायदा होता है। इसके न बनने से यह गांव बिल्कुल कट आफ हो जाते है। साल मे आठ महीने तक उनको एप्रोच करना मुि कल हो जाता है। इसके साथ ही दो तीन रोडज ऐसी है जो कम्पलीट होनी जरुरी है। एक किलोमीटर का एक टुकडा है। जो महे वरी से पिजौर तक बनना है। वहा पर बस सर्विस भी नहीं है। दूसरी तक सडक कोटला से बजौली की है। इस के बनने से 15 किलोमीटर का चक्कर बच जाता है। इससे लोगो की असुविधा दूर हो सकती है।

स्पीकर साहब, महे वरी से पिजौरा की सडक एक किलोमीटर लम्बी है इसके बनने से रणजीतपुर से लाडवा के लिए सीधा रास्ता मिल जाएगा और लोगो को पन्द्रह बीस किलोमीटर का फासला कम हो जाएगा। दूसरी सडक कोटला मे बिजली की है। इसके बनने से सढौरा से रणजीतपुर को जाने के लिए पन्द्रह सोलह किलोमीटर का फासला कम हो जाएगा। अब रणजीतपुर जाने के लिए बिलासुपर से होकर जाना पडता है। स्पीकर साहब, हमारे यहा की जो म्यूनिसिपल कमेटी है वह कभी बहुत अच्छी थी लेकिन आज उसकी वित्तीय स्थिति खराब है क्योकि उसके अनुदान सहायता नही मिलती। मेरी प्रार्थना है कि उस म्यूनिसिपल कमेटी को अनुदान देकर वहा की जो समस्या है उनको हल किया जाए। (घटी) इन भाब्दो के साथ स्पीकर साहब, आपका धान्यवाद करते हुए मै अपना स्थान लेता हू।

**वित्त मंत्री (श्री तैयब हुसैन):** मोहतरिक स्पीकर साहब, तकरीबन बाते कही गई है जो कल कही गई थी और करीब उन सब का जवाब भ दिया जा चुका है। फिर भी, मुख्तसर तौर पर मोआजिज मैम्बर साहिबान की इफरमें उन के लिए मे कुछ अर्ज करना चाहता हू। स्पीकर साहब, यहा पर पुलिस के खर्च के बारे मे बार बार आई है कि पुलिस पर इतना खर्चा क्योकि किया जा रहा है? जिस दिन मे हाउस चल रहा है उसी दिन से हाउस मे किसी न किसी बात पर पुलिस का मामला आजाता है। इस बारे मे बडी तफसील से बात हु ई है और सदन को बताया गया है कि

हमारे पड़ोसी राज्य में हालात ऐसे हैं उसकी वजह से खर्चा ज्यादा बढ़ गया है। मैं हाउस को यह भी बताना चाहता हूँ कि हमने जितनी सैंटर की मांग की थी वह अभी भी पूरा नहीं हुई है। सभी सदस्यों को इस बात के लिये हरियाणा गवर्नमेंट का मतांकुर होना चाहिए कि हमारे सूबे की ला एण्ड आर्डर की पोजीशन बहुत बेहतर है। भाम को दिल्ली से या कहीं और ये आने से जब देर हो जाती है तो लोग भाहबाद के बाद हरियाणा की टैरटरी में से गुजर कर आना पसन्द करते हैं। सभी को इस बात के लिए सरकार को मुबारिकबाद होना चाहिये कि लोगों को यकीन है कि हम हरियाणा की टैरटरी में महफूज हैं। स्पीकर साहब, एस0वाई0एल0 के बारे में काफी बात आई। स्पीकर साहब, इसके लिये हमारी सरकार सीरियस है और सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि यह नहरे जल्दी से जल्दी बने। खुडिया साहब ने कुछ बातें आईं। उन्होंने जो कुछ कहा है वह हमारे नोटिस में है मैं समझता हूँ कि इसका दुक्का कोई बात हो जाती है और हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने पेन्शन की बात कही। स्पीकर साहब, मैं हाउस की इन्फरमेंशन के लिये बताना चाहता हूँ कि जिनको पहले साठ सत्तर रूपया पेन्शन मिलती थी हमने उसको सौ रूपये में कन्वर्ट कर दिया है और अब 36 हजार केसिज में सौ रूपया महीना पेन्शन दे रहे हैं। उनकी कुछ मुकामीशिकायतें थीं। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन की सराहना की है। रोहतक के डी0सी0 और एस0पी0 अच्छी हैं उन्होंने ऐसा कहा है। उन्होंने फूड एण्ड सप्लाइज डिपार्टमेंट में खरबी बताई है, कमी

बताई है। स्पीकर साहब, जब जिले के हैड ठीक काम कर रहे हैं तो फूड एण्ड सप्लायज विभाग कोई गलत काम कैसे कर सकते हैं? यह बात समझ में नहीं आई। हरिजनो का जहां तक ताल्लुक है सरकार इस बारे में जागरूक है जहां भी कोई चीज इस बारे में नोटिस में लाई जाएगी हम उस पर ऐक्टिवान लेगे। श्री योगे आ चन्द भार्मा ने कहा कि औलावृशिट का जो मुआवजा चार सौ रूपए फी एकड दिया गया वह कम है उसको बढ़ाया जाना चाहिये। स्पीकर साहब, जो कुछ भी दिया गया है। यह नियम के मुताबिक दिया गया है। स्पीकर साहब, ये सारी चीजे मुकामी है। सम्बन्धित मिनिस्टर्ज को भेज देगे। चौधरी असलम खां ने अपने यहां किसी टैक्स बैरियर की बात कही। उनकी ग्रिवेन्स को मुताल्लिका महकमे को भेज देगे और जरूरी कार्यवाही करेगे वैसे तो गोदारा जी ने और सतबीर सिंह कादियान जी ने सारी बाते बडी तफसील के साथ बताई है। वे पूरे फेक्टस बता रहे थे लेनिक अपोजी इन के भाई भाोर मचा रहे थे। कम से कम सच्ची बातों को तो इन्हें आराम से सुनना चाहिये। ये लोग रैवेन्यु विभाग के खर्च की बात को और पास बुक लेने की बात को काफी उलझा रहे थे। जब मेरे पास यह विभाग था उस वक्त इन सारी बातों को फाइलेलाइज किया गया था और अब त्यागी जी इसकी देख रहे हैं। हम ने यह सारा मामला भारत सरकार के पास भेजा हुआ है।

**आवाजे:**जर फरीदाबाद वाली प्लाटो की बात भी बात दीजियेगा।

**श्री तैयब हुसैन:** वहा के तहसीलदार को ससपैन्ड ही नही किया गया बल्कि उसके खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज हुआ है। प्लाटो की अलाटमैट मे काफी गडबड भी हुई है। उस वक्त सूरजभान जी उस महकमे के वजीर थे। यह सारी अलाटमैट उन्ही के जमीनो मे ही हुई थी। ( गोर एवम व्यवधान) अब जब उस आदमी के खिलाफ सरकार ने कोई कार्यवाही की है तो इनको परे गानी हो रही है। उस केस से सम्बन्धित सभी फाइले पचकूला के किसी एक इडस्ट्रियलिस्ट के घर से बरामद हुई है। ( गोर)

**श्री राम बिलास भार्मा:** अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे है कि उस वक्त री सूरजभान जी मंत्री थे। वे कोई इनकी मेहरबानी से वजीर नही बने थे। इन्होने उस जमींदारे के खिलाफ कार्यवाही की थी। जो भी बाते वित्त मंत्री महोदय कहे जर सजीदगी से कहे और उत्तर भी इन्हे बडी सजीदगी से देना चाहिये। विपक्ष के आदमी ने जो बात कही है इन्हे उसका आदर करना चाहिये। आप वित्त मंत्री है, हरेक बात का सही उत्तर दीजियेगा।

**श्री तैयब हुसैन:** मोहतरिम स्पीकर साहब, मैने कोई ऐसी बात नही कही जिसके कारण मेरे मौआजिज दोस्त परे गान हों रहे है। ( गोर)

**श्री राम बिलास भार्मा:** तैयब हुसैन जी, इन दूसरे भाईयो की निस्बल हम आपसे अच्छी बातो की उम्मीद करते है।

**श्री तैयब हुसैन:** भार्मा जी, आपकी जो बाते है, हम भी उनको मानते है आपका हम आदर करते है, आपका सम्मान करते है। स्पीकर साहब, मै तो इन्हे असलियत के करीब लाने की कोशिश कर रहा हू लेकिन ये मेरी बातों का बुरा मना रहे है। ( तौर) स्प्रिंकलिंग सैटस पर सबसिडी की बाते इडीविजुअल तौर पर श्री हीरा नन्द आर्य काफी टाइम पहले मुझे से डिस्कस कर चुके है। चौधरी देवी लाल जी के समय इस बात पर डिस्कसन के लिए मीटिंग हुई थी, उस वक्त इन सैटस पर 3000 रूपये किसानों को सबसिडी के तौर पर दिये जाते थे फिर किसानों की तकलीफों को ध्यान में रखते हुए यह राशि बढ़ाकर 4000 रूपये कर दी गयी है। इन सैटस पर सेल्ज टैक्स माफ करने की बात भी आई। इन में जो पाईप्स लगते है अगर इन पर टैक्स की छूट दी गई तो भायद इस का मिसयूज होने का डर होगा। इसलिये सेल्ज टैक्स माफ करना उचित नहीं है। जहा तक लोन वेविंग की बात है, मैने इस बारे में कल भी बताया था कि हमारे यहा 10.36 लाख आदमियों का 266.05 करोड रूपये का कर्जा माफ किया गया है। पता नहीं ये कहा से फिगर उठा कर ले आए। जहा तक हिसार की डिस्टिलरी से पोल्यूशन की बात है उस पर हमने काफी कार्यवाही की है लेकिन अदालतों की तरफ से स्टे आर्डर है इसलिये इस पर मजिद कार्यवाही नहीं की जा सकी। कामरेड हरपाल सिंह ने चाइल्ड लेबर के बारे में कोई स्पैसिफिक बात नहीं कही लेकिन मै उनको बता दू कि हमारे यहा बौडिड लेबर की कोई बात नहीं है गेहू की जहा तक बात है, इस बारे में एक काल अटैन्शन में आना

भी ऐडमिट हो चुका है। मैं फिर भी बता दू कि गेहूँ बहुत ज्यादा तादाद में डिस्ट्रीब्यूशन के लिये भेजा गया उसके बाद भी पता नहीं इनको क्यों परेशानी होती है। फिर भी कोई विकल्प अगर कोई लिख कर देगा तो उसे देखे लेंगे। एम्प्लायमेंट देने के लिए कल भी मैंने बताया था उस वक्त भायद कामरेड साहब सदन में नहीं थे। हमारी स्कीम है कि हर परिवार के एक आदमी को नौकरी मिले उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। उसमें यह जरूरी नहीं है कि सब को सरकारी नौकरियों ही मिलें, सवाल तो रोजगार देने का है। अगर कुछ आदमियों को सरकारी नौकरियों मिल जाती है। और उनका पहले एक भी आदमी सरकारी नौकरी में नहीं है तो पता नहीं इनको उससे क्यों परेशानी है। उन लोगों को परेशानी हो सकती है जिन लोगों के आदमी नौकरियों में ज्यादा लगे हुए हैं। (विधन) चाइल्ड लेबर की सिक्योरिटी के लिए हमारे यहाँ कोई प्रोब्लम नहीं है, अगर कोई प्रोब्लम आएगी तो उस पर गौर कर लेंगे। सड़को का जहाँ तक टाल्लुक है इसके लिए 21 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन्होंने पता नहीं कैसे कह दिया कि यह नहीं हुआ वह नहीं हुआ। कुछ लोग पब्लिसिटी के लिए ही बातें कर देते हैं। हाँ तक वाटर सप्लाई की बात है, हमारी इरादा था कि सितम्बर और मार्च तक इस काम को पूरा कर देंगे लेकिन कुछ कारणों की वजह से कुछ गावों में पानी देने का काम नहीं हो सकता इसलिये अगले साल के लिए इस मद में हमने कम पैसे का प्रावधान किया है। जहाँ तक ओलावृष्टि की बात है यह एक कुदरती बात है इसके लिए हमने स्पैशियल

गिरदावरो के आर्डर कर दिए है और पहले ही डी०सी० की डिसपोजल पर 167.15 लाख रूपए दे दिए है ताकि वे लोगो को तुरन्त सहायता दे सके। प्रोफैसर परमा नन्द जी ने बोलते हुए कहा कि पिछले साल इस सरकार ने केवल 80 गावो को पौने का पानी उपलब्ध करया। मैं अपने माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमने 80 गावो को नहीं बल्कि 380 गावो को पीने का पानी उपलब्ध कराया है। आप अपना रिकार्ड करैक्ट कर ले। इसी तरह से स्कूलो के मामलात है। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जो ओप्रे न ब्लैक बोर्ड है उसके तहत स्कूलो मे फर्नीचर और ऐजुके न जी भी इक्विपमैटस है वह सब दिए जा रहे है। अगर कोई बात मुखालफत करने के लिए कही जाए तो वह अलग बात है उसका कोई इलाज नहीं है। इस सरकार ने अपने कर्मचारियो को 34 करोड रूपए की राहत दी है। इसके बारे मे मैने आपकी कल भी बताया था। माननीय सदस्यो ने जो जी बात कही है इस सभी बातो को पूरा करने की कोशिश करेगे। प्रदे श के विकास के लिए से हमे सहयोग दे। किसी बात की केवल मुखालफत करने के लिए ही मुखालफत न करे। इन्ही भाब्दो के साथ मे अर्ज करूंगा कि इन डिमाण्डज को पास किया जाए।

**Mr. Sperker:** Hon'ble members before I put the various damands to the vote of the House, I have to inform that notices of amendments to demand Nos. 4 & 9 were received form Dr. Harnam Singh. M.L.A which have been disallowed.

**डा० हरनाम सिंह:** स्पीकर साहब, मैं एक अमैडमैन्टस को प्रैस करता हूँ।

**Mr. Speaker:** Very Sorry, I have disallowed these notices. और ये अमैडमैटस आ नहीं सकती अब डाक्टर साहब आप बैठिए।

अगर हाउस की सहमति हो तो सभी डिमांडज को एक साथ पुट कर दिया जाए।

**आवाजे:** ठीक है जी।

**Mr. Speaker:** Quesation is-

That a sum not exceeding Rs. 17447000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 1 Vidhan Sahba.

That a sum not exceeding Rs. 460008000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 2 General Administration.

That a sum not exceeding Rs. 12441707000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 3 Home

That a sum not exceeding Rs. 28218000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that

will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 4 Revenue.

That a sum not exceeding Rs. 108467000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 5 Excise & Taxation.

That a sum not exceeding Rs. 792625000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 6 Finance.

That a sum not exceeding Rs. 11991694000 for revenue expenditure and Rs. 3665000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 7 other Administrative Services.

That a sum not exceeding Rs. 570531000 for revenue expenditure and Rs. 534367000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 8 Buildings and Roads.

That a sum not exceeding Rs. 3557614000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 9 Education.

That a sum not exceeding Rs. 1654161000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year

1991-92 in respect of charges under Demand No. 10 Medical and Public Health.

That a sum not exceeding Rs. 80697000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 11 Urban Development.

That a sum not exceeding Rs. 212064000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 12 Laboru and Employment.

That a sum not exceeding Rs. 1800102000 for revenue expenditure and Rs. 18264000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 13 Social Welfare and Rahabilitation.

That a sum not exceeding Rs. 48254000 for revenue expenditure and Rs. 1970080000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 14 Focd and Supplies.

That a sum not exceeding Rs. 2313501000 for revenue expenditure and Rs. 848394000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 15 Irrigation.

That a sum not exceeding Rs. 229535000 for revenue expenditure and Rs. 64216000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 16 Industries.

That a sum not exceeding Rs. 849720000 for revenue expenditure and Rs. 6300000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 17 Agriculture.

That a sum not exceeding Rs. 300599000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 18 Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs. 31766000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 19 Fisheries.

That a sum not exceeding Rs. 452406000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 20 Forest.

That a sum not exceeding Rs. 737814000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 21 Community Development.

That a sum not exceeding Rs. 352767000 for revenue expenditure and Rs. 181286000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 22 Cooperation.

That a sum not exceeding Rs. 184892000 for revenue expenditure and Rs. 255400000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 23 Transport.

That a sum not exceeding Rs. 18552000 for revenue expenditure and Rs. 20500000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 24 Tourism.

That a sum not exceeding Rs. 2476256000 be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1991-92 in respect of charges under Demand No. 25 Loans and Advances by State Government.

The motion was carried.

**श्री अध्यक्ष:** अब हाउसव कल सुबह 9.30 बजे तक ऐडजर्न किया जाता है।

**13.22 बजे**

(इस समय वीरवार, दिनांक 14 मार्च, 1991 प्रातरू 9.30  
बजे तक \*स्थगित हुआ)